†[شری سکندر بخت: صدر صاحب، میرے لئے یہ نامناسب تھا کہ میں لیڈر آف دی ہاؤس کے کہہ دینے کے بعد کچھ کہوں، لیکن یہ انفاقیہ انسیڈینٹ نہیں ہے۔ اس قسم کا سلسلہ ممبرس کو ذلیل کرنے کے لئے لگاتار ہوتا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے اور بالکل لاعلاج مرض بنا ہوا ہے۔ اس قسم کی توہین آمیزی کو کسی خاص لیول پر ٹیکل کرنا ہوگا، لیکن اس کو بہت سرل معاملہ، ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ لگاتار ہوتا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے اور اسکا کوئی علاج ہو نہیں سکا ہے۔]

**श्री लछमन सिंह (हरियाणा)**: सर, एक मिनट।

**श्री सभापति**: देखिए, यह हो गया और इसको देख लिया जाएगा।

**श्री लछमन सिंह**: सर मेरे से वह बिल मांगते हैं जब मैं एम०पी० नहीं था, 1976 से पहले का मांगते हैं और कहते हैं मेरी बिजली काट देंगे। मैंने कहा कि मैं एम०पी० ही नहीं था तो उस वक्त का बिल कहां से दूं तो कहते हैं कि बिजली काट दी जाएगी। वे ऐरियर मांगते हैं उस वक्त का जब मैं एम०पी० नहीं था। अब बताइए इसका क्या इलाज है?

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, .... *(Interruptions)*.... Regarding telephone bills, they say that our telephones will be cut of unless we pay the arrears... *(Interruptions)*...Sir, this may also be taken note of.... *(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Now this is over..... *(Interruptions)*.... We will look into it.

---

## MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (Contd.)

**श्रीमती सरोज दुबे** (बिहार): सभापति जी,

**[उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) पीठासीन हुई]**

उपसभाध्यक्ष महोदया जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रकट करते हुए और विनम्रता के साथ यह कहना चाहती हूं कि मैं इस अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकती। यह अभिभाषण सरकार द्वारा किए गए कार्यों तथा उनके भावी कार्यक्रमों की एक रूपरेखा है। शब्दों के जाल से एक सुन्दर सब्जबाग की रचना करके उसमें हम सबको सैर कराने का असफल प्रयास

---

†[ ] Translitration in Persian script.

किया गया है क्योंकि यह जो सब्जबाग बनाया गया है इसमें बनावटी हरियाली तो है लेकिन फूलों में महक नहीं है, भंवरों की गुंजन नहीं है, भंवरों की गुंजन की जगह साम्प्रदायिकता और अत्याचार से तड़पते हुए लोगों की चीख और गरीबी और भ्रष्टाचार की मार से तड़पते हुए लोगों की सिसकिया सुनाई देती हैं। यह अभिभाषण वास्तविकता से बहुत दूर हैं और इसमें समाज के उपेक्षित, दबे-कुचले और मेहनतकश लोगों की समस्याओं को केवल छुआ भर गया है, उनके समाधान का कोई उपाय नहीं बताया गया है और न ही कोई ऐसे समयबद्ध कार्यक्रम की योजना बताई गई है कि यह कार्यक्रम कब तक आगे बढ़ जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, अभिभाषण के पैरा तीन में गांधी जी के सपनों के भारत का जिक्र किया गया है, लेकिन इस दस्तावेज में यह नहीं बताया गया कि गांधी जी के सपनों के भारत का वह अंतिम इंसान जो विकास की सीढ़ी के नीचे खड़ा है, विकास की सीढ़ी पर कदम रखने का प्रयास कर रहा है, उसका हाथ पकड़कर, उसको सहारा देकर, वे उसको कैसे ऊपर लाएंगे, कैसे विकास की रोशनी में लाएंगे, ऐसा कोई भी समयबद्ध कार्यक्रम उसमें नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि सभी समुदाय मिलकर काम करेंगे, गरीब को भी एहसास होगा कि इस देश में उसकी भागीदारी है, लेकिन माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का इन्होंने कोई भी योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया है। आज गरीब बहुत गरीब होता चला जा रहा है, उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अमीरों के ऐश-ओ-आराम बढ़ते चले जा रहे हैं परन्तु इसको दूर करने का भी कोई सुझाव नहीं दिया गया है। केवल गांधी जी के सपनों के भारत का उल्लेख करके इसको लुभावना बनाने का प्रयास किया गया है।

महोदया, मैंने इसीलिए इस अभिभाषण को एक सुनहरा सब्ज़बाग कहा क्योंकि कल भी लोग सिसक रहे थे और आज भी वे बेबसी और लाचारी के आंसू बहा रहे हैं और जिस तरह का सरकार का रवैया चल रहा है, उससे आने वाले दिनों के प्रति वे आशंकित हैं, भयभीत हैं और परेशान हैं। महोदया, यह सच है कि इस समय देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें देश का आर्थिक विकास करने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए और पूरे विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए कार्य करना है और यह तभी संभव है जब सारे लोग एकजुट होकर इसके लिए कार्य करें। महोदया, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति उद्देश्य को लेकर काम करने के संकल्प की बात दोहराई है। मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों से यह कहना चाहती हूं कि ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति जी के आह्वान पर हम अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन क्या कभी सरकार ने भी अपने रवैये पर ध्यान दिया है?

महोदया, हमारे सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने विपक्ष की भूमिका पर अंगूली उठाई है और सवालिया निशान लगाया है। लगता है वह अपने ढंग से विपक्ष की परिभाषा करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर सरकार को, सत्ता पक्ष को विपक्ष का पूरा सहयोग चाहिए तो उसको अपना भी रवैया बदलना पड़ेगा। सत्तापक्ष का रवैया जिस ढंग का है वह आपको पता चल ही गया होगा। बोफोर्स केस में स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम डालकर क्या सत्तापक्ष के लोगों ने कांग्रेस को संघर्ष के लिए चुनौती नहीं दे दी है, स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे चार्जशीट में उनका नाम डाल दिया गया लेकिन जो इस संसार में अभी जीवित हैं, उनका नाम डालने का कष्ट नहीं किया गया, उनको दूसरे हिस्से में डाल दिया गया। यह साफ जाहिर करता है कि स्वर्गीय राजीव गांधी की छवि को धूमिल करने का निंदनीय प्रयास किया गया है।

महोदया, डीजल के दाम अंधाधुंध तरीके से बढ़ाए गए हैं और किसानों की पीठ में छूरा भोंक दिया गया है। गरीबों की यात्रा और महंगी कर दी गई है और डीजल के दाम बढ़ने से सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। क्या ये सारी बातें विपक्ष आसानी से बरदाश्त कर जाए और आपकी हां में हां मिलाता रहे?

महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 36 में केन्द्र और राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंधों की बात कही गई है लेकिन इनकी कथनी और करनी का अंतर आप देखिए—बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बिहार में हर साल नेपाल से छोड़ा हुआ पानी गंडक, कोसी और कमला नदियों में भरकर आता है और उत्तरी बिहार में तो साल में दो-तीन बार बाढ़ आ जाती है और सारा विकास उस पानी में बह जाता है। बाढ़ की विभीषिका में सारे विकास की रेखाएं गायब हो जाती हैं और जान और माल का बहुत नुकसान होता है, जानवर बह जाते हैं और गरीब हर साल सड़क पर आ जाता है।

महोदया, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि आजादी के बाद के 50 सालों में क्या कभी सरकार ने यह सोचा कि बिहार में जो हर साल यह तबाही का आलम होता है नेपाल से पानी आने के कारण उसका कुछ हल निकालना चाहिए। क्या उसके बारे में कभी कोई ठोस कार्यक्रम बनाया या उस पानी को कभी रोकने का प्रयास किया? कभी नहीं किया क्योंकि बिहार को इन्होंने उपेक्षित कर रखा है और बिहार की जनता को इन्होंने विकास के लायक नहीं समझा है और हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है।

महोदया, बिहार खनिज संपदा से भरपूर है। इन खनिज पदार्थों के दाम बढ़ते रहते हैं लेकिन बिहार को केन्द्र सरकार केवल रायल्टी देती है। दामों में जो बढ़ोत्तरी होती है, उसके हिसाब से कभी भी रायल्टी नहीं दी जाती। हमारे संसद सदस्यों ने बार-बार इस रायल्टी को बढ़ाए जाने की मांग की है लेकिन कभी भी रायल्टी बढ़ाई नहीं गई है। नतीजा यह होता है कि खनिज संपदा हमारी है, हमारे पास है, हमारी चीजों से केन्द्र का विकास हो रहा है लेकिन बिहार की उपेक्षा हो रही है। इसलिए मैं यह बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि हमारा अधिकार तो हमें दिया नहीं जाता, आर्थिक सहायता देना तो बड़ी दूर की बात है।

महोदया, बिहार की मुख्यमंत्री एक महिला है, वह पिछड़े वर्ग की भी हैं। केन्द्र सरकार बार-बार माफिया राज और जंगल राज कहकर महिला मुख्यमंत्री को अपमानित करने का प्रयास करती है, उनको उखाड़ने का प्रयास करती है। क्या यह केन्द्र और राज के सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में एक कदम है? चुनाव के दौरान बिहार सरकार को बदनाम करने का जिस तरह से झूठे आरोप लगाकर के पूरे देश में प्रचारित किया गया यह क्या बहुत अच्छा कदम था? आज भी बिहार के ऊपर ही चक्रव्यूह की रचना की जाती है कि किस प्रकार से बिहार को बरबाद किया जाए। यह केन्द्र सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण रवैया रखने का कोई तुक नहीं है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल की भूमिका रही है, हर अधिकारी ने, हर पदाधिकारी ने अपने पद की गरिमा को भूलकर बिहार सरकार के खिलाफ एक घेराबंदी की। लेकिन जो जनता का प्रतिनिधि है, जो जनता के बीच में रहता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मेरा ऐसा दावा है। मैं केन्द्र सरकार से कहती हूं कि बिहार के साथ ऐसे सौतेले रवैये का कारण क्या है? क्या बिहार भारत के नक्शे में नहीं है? क्या बिहार के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान नहीं दिया? क्या कारगिल युद्ध में बिहार के जांबाज सिपाहियों ने शहादत देने में कोई कमी रखी? क्या बिहार के प्रतिभावान अधिकारी पूरे देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? बिहार की प्रतिभाओं का किसे पता

नहीं? तो किसलिए बिहार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है, किसलिए बिहार के साथ उपेक्षा की जाती है? अन्य प्रदेशों में बाढ़ आती है तो प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री मुआयना करने जाते हैं हेलीकोप्टर से। लेकिन बिहार की तरफ देखने की किसी को याद नहीं रहती है। बड़े दुख की बात है कि इन लोगों ने बिहार को इतना उपेक्षित किया है तथा इसको हिन्दुस्तान से काटने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन बिहार इस देश का अंग है। अगर आप बिहार को उसका हक नहीं दोगे तो बिहार छीनकर इसको ले लेगा, यह मेरा आपसे कहना है।

फिर आप चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका बड़ी रचनात्मक रहे, विपक्ष आपकी हां में हां मिलाता रहे। तो फिर चुनाव का वातावरण क्यों तैयार किया गया, फिर विपक्ष की जरूरत ही क्या है? विपक्ष का काम है कि यह सरकार के ऊपर तलवार बनकर लटकता रहे। विपक्ष अपनी भूमिका के प्रति सजग है। लेकिन अगर सरकार अपना रवैया ठीक रखती है तो विपक्ष को सहयोग देने में कोई आपत्ति नहीं है। देश के विकास के लिए विपक्ष रचनात्मक सहयोग करना चाहता है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी-बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। 1972 के शिमला समझौते के 27 साल के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया। 27 साल तक उसकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी सीमा में घुसकर हमारे धवल हिमालय को रक्त से लाल करने का काम किया। लेकिन हमारे जांबाज सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत की आन-बान-शान की रक्षा करी और अपनी शहादत देकर एक नया इतिहास लिखा। मैं ऐसे जांबाज सैनिकों को ऐसी शहादत देने वाले सैनिकों को शत-शत प्रणाम करती हूं। लेकिन कारगिल प्रकरण ने एकबार हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसकी खामियों को उजागर किया है। तो हमें चाहिए कि कारगिल में अपनी कमियों को छिपाएं नहीं बल्कि एक समय-सीमा बनाकर जो भी कमी थी, खामियां थी उन पर विचार करें कि क्यों नहीं सैनिकों को आधुनिक हथियार मिले, क्यों नहीं हमारे सैनिकों को वक्त पर लड़ने वाली वर्दी मिली, क्यों नहीं सैनिकों को जो संचार के माध्यमों को मजबूत करने के लिए इक्विपमेंट मिले? इन सारी कमियों को दूर किया जाए और जो भी रक्षा बजट में बढ़ावा देना है उसको निसंकोच किया जाए और भारत की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि यह देश हम सबका है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सारे लोगों की है हमारे जो शहीद हुए परिवार हैं उनकी भी हमें पूरी देखभाल करनी है। जिस समय युद्ध चलता है और सैनिक शहीद होते हैं उस समय तो लोग भावनाओं में आ करके इनके परिवारों को वह जो चाहता है उनको देते हैं तथा मदद करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे यह गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। बहुत से सैनिकों के ऐसे परिवार हैं जिन्होंने शहादत दी और आज वह अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि जो शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है उनके परिवारों की देखरेख के लिए हर तीन महीने बाद समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं कोई परिवार ऐसा तो नहीं है जिसका परिवार तथा उसके बच्चे पढ़ने-लिखने में असमर्थ हो रहे हों। तो इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि अपने देश की सीमा के अन्दर जो हो रहा है और जो सीमा के बाहर हो रहा है उससे सरकार को बेखबर नहीं रहना चाहिए। कारगिल प्रकरण सरकार की बेखबरी और लापरवाही का ही नतीजा था। दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। महोदया, इसके कई पैराग्राफों में गरीबी पर काबू पाना, शुद्ध पेयजल देना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की बातें फिर से दोहराई गई हैं और इनके लिए कहा गया है कि नई योजनाएं चलाई जाएंगी, साक्षरता विभाग बनाया जाएगा। महिलाओं के विकास की बात

की गई है, बालिकाओं के लालन-पालन की बात की गई है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हर समस्या उसको आप पूरा कर पाएंगे? क्या यह केवल खोखला नारा बन कर नहीं रह गया है? क्या इस देश की पिछड़ी और उपेक्षित नारियों के लिए कोई स्थान होगा या नहीं होगा? क्या महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण नौकरियों में नहीं दिया जा सकता था? क्या इस देश की महिला जो राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में पूरा योगदान देती है, क्या उन महिलाओं को अपने परिवार को पालने के लिए 33 परसेंट आरक्षण नौकरियों में देना आपने ज़रूरी नहीं समझा? आज हम 21वीं सदी की दहलीज़ पर खड़े हैं लेकिन भारतीय नारी कहां पर है? आज आप महानगरों की आठ, दस या पचास नारियों की स्थिति को देखकर अंदाज़ लगाना चाहते हैं कि सभी विकास के मार्ग पर चल रही हैं। मैं आपको उन सुदूर गांवों की तरफ ले जाना चाहती हूं जहां पर आज भी नारी सिसक रही है और उन्हीं आंसुओं को लेकर वह 21वीं सदी में प्रवेश कर जाएगी। उसके आंसू न पहले थमे थे और न आज थमें हैं।

गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की बात की गई है। आज भी हमारी 60 से 80 प्रतिशत बहनें खून की कमी का शिकार हैं। 1901 में हमारी संख्या 1000 में 972 थी और 1991 में जब इसका आकलन किया गया तो हमारी संख्या घटकर 927 हो गई। अब तो हमारे अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। आज आधुनिक उपकरणों की सहायता से हमने बालिकाओं को जन्म से पहले ही मारने की योजना बना ली है। हमारे देश में केवल 27 प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता है तो किस प्रकार से आप सुविधा देने की बात करते हैं? हमारी जो मेहनतकश महिलाएं हैं, जो बहनें खेत में काम करती हैं, जो बहनें सड़कों पर काम करती है, जो बोझा उठाती हैं, उनकी स्थिति आज भी बद से बदतर होती चली जा रही है। आज बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है लेकिन वह खेत में काम करने वाली महिला अपने बच्चे को किसी खटोले से बांध कर उसके मुंह में ज़रा सी अफीम चटा देती है ताकि वह निश्चिंत होकर काम कर सके और बच्चा रोने न पाए। वह गर्भवती महिला जो खेतों में काम कर रही है, जो बोझा ढो रही है, यदि काम करते-करते प्रसव पीड़ा से छटपटाती है तो किसी पेड़ के पीछे जाकर, किसी कूड़े के ढेर पर वह बच्चे को जन्म देती है और उसी गंडासे से वह बच्चे की नाल काट देती है और उसी चीथड़े में बच्चे को लपेट कर वहीं पर सुला देती है। घंटे, दो घंटे का आराम कर के वह सूखे मुंह से फिर काम पर चली जाती है क्योंकि अगर वह काम पर न जाए तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा और ठेकेदार उसको काम से निकाल देगा। यह हमारी बहनों की वास्तविक स्थिति है और आपने इसकी ओर कोई विशेष ध्यान देने का काम नहीं किया है।

आज भी ग्रामीण इलाकों में केवल दो प्रतिशत घरों में शौचालय हैं। आपको याद होगा आप जब कभी लाल बत्ती की गाड़ी में सड़कों पर चलते हैं चमचमाती हुई रोशनी में तो आपको दिखाई देता होगा कि क्यों महिलाएं अचानक घूंघट निकाल कर सड़क के किनारे पर खड़ी हो जाती हैं सकुचाती हुई। क्या आपको मालूम है कि शौचालयों की कमी ने महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय बना रखी है? उन महिलाओं को अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता है नित्यक्रिया से निवृत्त होने के लिए। सवेरे उठने में अगर उनको ज़रा सी देर हो जाती है तो वह दिन भर पेट पकड़ कर बैठी रहती हैं। यह स्थिति आज इस आज़ाद भारत देश की है। वे महिलाएं जिनके घर झुग्गी-झोपड़ियों में हैं, उनकी बहू-बेटियों को चौराहे पर नल पर आकर नहाना पड़ता है क्योंकि उनके यहां कोई पर्दा नहीं है और न कभी सरकार ने बनाने का कोई काम किया है। **(समय की घंटी)** क्या मेरे बोलने का टाइम पूरा हो गया है?

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** आपकी पार्टी के लिए जो यहां पर समय दिया हुआ है वह 16 मिनट है। आपने 12 बजकर 17 मिनट पर बोलना शुरू किया था।

**श्री रामदेव भंडारी** (बिहार): मैडम, अभी तो आठ मिनट भी नहीं हुए हैं।

**श्रीमती सरोज दुबे:** ठीक है, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं। महिलाओं की स्थिति यह है कि उन को खुले चौराहे के ऊपर नहाने के लिए विवश होना पड़ता है। हमें इस पर एतराज नहीं है कि बड़े घरानों की महिलाएं सुसज्जित बाथरूम में, पर्दे वाले बाथरूम में स्नान करती हैं। लेकिन हमारी मांग यह जरूर है कि हमारी ग्रामीण महिलाओं को जगह-जगह पर स्नानघर बनाकर देना चाहिए क्योंकि इज्जत चाहे बड़े घराने की महिलाओं की हो, चाहे छोटे घराने की महिलाओं की हो सबकी बराबर होती है। जो महिलाओं के बुनियादी अधिकार हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं वह उनको मिलनी चाहिएं। इस बारे में आपको सोचना होगा। एक महिला को दिन में आठ किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, एक बार में वह पानी लेने जाती है, फिर चारा लेने जाती है, फिर वह घर के लिए लकड़ी लेने के लिए जाती है, फिर घर में आकर वह जानवरों का सारा काम करती है, बच्चों का काम करती है और उसके बाद वह गीली लकड़ियों में खाना बनाने का काम करती है और उसके बाद भी अपने शराबी पति से मार खाती है। यह जो दयनीय स्थिति महिलाओं की है इसके बारे में आपको सोचना होगा। आपने केवल एक लाइन में महिलाओं के लिए 33 परसेंट आरक्षण मिलेगा यह लिखकर अपने उत्तरदायित्व से छुटकारा पा लिया है, यह नहीं चलेगा। महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण तो देना ही देना है लेकिन उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण देने का प्रावधान आपको करना होगा। साथ ही साथ महिलाओं की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वह भी आपको देनी पड़ेंगी क्योंकि वे महिलाएं जो गांवों में रहती हैं, जो खुले में नहाती हैं, सड़कों के किनारे ऊपर शौच के लिए जाने को विवश हैं वे भी इसी भारत की नागरिक हैं। उनको भी बुनियादी सुविधाएं पाने का अधिकार है। बच्चा चाहे नर्सिंग होम में पैदा हो या एयर कंडीशन नर्सिंग होम में पैदा हुआ हो, चाहे सड़क के किनारे पैदा हुआ हो, चाहे गंदे नाले के पास पैदा हुआ हो वह भी इसी देश का नागरिक है और वह भी हर सुविधा पाने का अधिकारी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि एक बार अपनी योजनाओं पर आप पुनर्विचार करें। इस देश की युवा शक्ति इस समय भटक रही है। आपने एक करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है पिछली बार भी अपने 13 महीने के शासनकाल में एक करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि आपने 10 लाख लोगों को भी रोजगार दिया होगा। आपने इस खोखली योजना पर सच्चाई का जामा पहनाने का काम किया है। आपने 20 लाख घर बनाने की बात की है। शहरों में तथा गांवों में लोग सड़कों के किनारे पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, बिना छत के खुले आकाश के नीचे पड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 20 लाख घरों से काम बनेगा? ठंड के दिनों में जब हम हीटर लगाकर बैठे रहते हैं तो लोग पेड़ के नीचे खुले में सोया करते हैं। क्या 20 लाख घरों से काम बनेगा? क्या उन लोगों को छत के नीचे रहने का अधिकार नहीं है? युवाशक्ति को रोजगार चाहिए। अगर युवाशक्ति को आप रोजगार नहीं देंगे तो वे लोग रचनात्मक कार्यों को छोड़कर विध्वंसात्मक कार्यों में लग जाएंगे। आज बढ़ता हुआ आतंकवाद उसी का नतीजा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह जो आपका सब्जबाग है इसको आप सच्चाई के धरातल पर लाएं। वास्तविक मार्ग बहुत खुरदुरा है। अगर आप उस पर ठीक से नहीं चलेंगे तो आपके तलवे लहु-लुहान हो जाएंगे।

मैं आपसे कहना चाहती हं कि जो मुद्रास्फीति की दर आपने दी है वह बड़ी संतोषजनक है, आपकी जो विकास दर है छह प्रतिशत वह भी बड़ी संतोषजनक है। आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं जिससे मुद्रास्फीति उछलकर आगे आ गई है और अभी आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने वाली है? मुद्रास्फीति की दर से इस देश के जनमानस को कोई मतलब नहीं है, इस देश के जनमानस को रोटी, कपड़ा और मकान से मतलब है। आप उसको रोजगार देने का प्रयास करें।

आपने धर्म-निरपेक्ष और पंथ-निरपेक्ष की बात कही है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपने पहले से ही देश को साम्प्रदायिकता के नाम पर बांटने का काम किया है, इन्सानों के मन में भय, आशंका, विद्वेष, नफरत पैदा की है। पोप की यात्रा को लेकर जो विवाद पैदा किया जा रहा है यह देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहा है। यह देश हिन्दू, मुस्लिम, सिख ईसाई सबका है। इस देश ने सब धर्मों का आदर किया है। इसलिए देश को बांटने का, देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करने की कोशिश न करें। यह देश हम सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, सिख का है। आप सबको मिलकर चलने दीजिए। इस देश के मंदिरों में घंटियां बजने दें, मस्जिदों में अज़ाने होने दें, गुरूद्वारों में सतश्री अकाल होना चाहिए और सभी चर्च में घंटी बजती रहनी चाहिए। यह देश मिल-जुलकर चलेगा तभी आगे बढ़ेगा। आपने धर्म के नाम पर जो कठोर रवैया अपना रखा है, उसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए विपक्ष आपका साथ देता है या नहीं देता है। आपको विपक्ष का सहयोग लेने से पहले अपना रवैया, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यह जो सिद्धान्तविहिन आपने समझौता किया है यह ऐसा ही है जैसे कि गांव की औरतें चिथड़ों को जोड़कर कथरी बना लेती हैं पुराने टुकड़ों को धागे से जोड़कर पूरी चादर बना लेती है परन्तु जैसे ही जरा-सा पैर फैलाया वैसे ही कथरी फटने लगती है क्योंकि धागा कमजोर रहता है। वही हाल आने वाले दिनों में आपका होने वाला है, यह जो साझागत, नीतीगत कार्यक्रम आपने बनाया है, यह चलने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं, बजरंग दल के लोग कुछ कहते हैं। जो बीजेपी खुद कुछ नहीं कह पाती है वह बजरंग दल से कहलवा देती है, आरएसएस से कहलवा देती है। आपकी यह सांठगांठ बहुत दिन चलने वाली नहीं है, आपका मुखौटा उजागर हो गया है। सिद्धान्तहीन समझौते हुए हैं। जो धर्म-निरपेक्षता की बातें करते थे, वे साम्प्रदायिक ताकतों की बगल में खड़े होकर फोटो खिचवां रहे हैं और उनके साथ सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। इस देश का तो भगवान ही मालिक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम सब का यह कर्तव्य हो जाता है कि देश को सजा-संवारकर आगे ले जाने के लिए एक जुट हो कर चलें और धर्म के नाम पर देश को बांटने की जो साजिश है इसको बिल्कुल विफल कर दें और भारत की जो संस्कृति है, एक उदार विचार है सर्व-धर्म समभाव की जो नीति है, वसुधैव कुटुम्बकम की जो नीति है, उसको मजबूत करने में योगदान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं और महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

**SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Thank you, Madam, Vice Chairperson. While expressing our gratitude and respect to the honourable President for the Address he delivered to the Joint Session of Parliament, I oppose the motion moved by the hon. Member, Shri Arun Shorie. The President's Address contains the polices of the Government. When a new**

Government assumes office, after receiving the mandate of the people in the General Elections, naturally, it indicates a series of measures. The President's Address delivered to the Joint Session also contains such provisions.

Before I come to some of these aspects, I would like to start my observations by referring to what Mr. Arun Shourie said. He in his brilliant, persuasive, way, tried to create an impression that there is a need for co-operation and that the country should be run by politics of consensus. I entirely agree with his premise, his hypothesis. Perhaps he will agree with me that our leader, immediately after assuming the Office of the Leader of the Opposition, extended the hand of co-operation and used the phrase that our opposition will be "Co-operative opposition". But what intrigues me, Madam is : Does this Government seriously want operation from the principal Opposition party? Immediately after our leader assumed the Office of the Leader of the Opposition, our former leader of the party Late Shri Rajiv Gandhi has been chargesheeted, knowing fully well that he cannot stand trial, knowing fully well he cannot defend himself, that he cannot explain his side of the story, knowing fully well that the Congress Party is not in the habit of ditching its leader whether he is alive or dead, knowing fully well the sensitivity of the Congr ssmen and women on this issue, knowing fully well that we went to the extent of withdrawing support to the UF Government and facing the criticism, still, they thought it necessary to put Rajiv Gandhi's name in the chargesheet. He is not being accused as a recipient of money, but as a co-conspirator along with some others. Nobody knows when the court would give its decisive verdict. But in the intervening period Rajiv's name will continue to be in the chargesheet. The Prime Minister, and no less a person than the Home Minister of the country, during the campaign had clearly demonstrated, had clearly pointed out, that a chargesheet would be filed in the Befors case after receipt of the whole set of documents.

The document related to the Sixth account is yet to be recived. Therefore, what does one read from this action of the Government? For two years, three year, five years or ten years, the man will be referred to as an 'accused' in the chargesheet! You Know the judicial system in this country. And he will have no way of defending himself! Is this the way of seeking co-operation from a political party? This is not the first occasion. When last year, in 1998, this Government came to office, in its Agenda for Governance, it indicated, "We would like to have governance through consensus". Did we find the process of consensus in changing a major policy of this country? While changing the nuclear policy of the country, the Government considered it necessary to consult a one-member party, the then Janata Party, led by Dr. Subramaniam Swamy. He was consulted while changing the nuclear policy from keeping the nuclear option open to nuclear weaponsisation, which was projected in the national Agenda for Governance. But the Government did

not consider it necessary to consult the pricipal Opposition Party which had articulated the nuclear policy of this country. Therefore, I have my own doubt. I do not believe that with a change of seat, one should change one's policies. Yesterday, when Mr. Malkani referred to my signing W.T.O. agreement I said, "Yes, I signed the Marrakesh Agreement." I own it. I considered it beneficial to the country. Simply because I am sitting here now, I would not change my view. I extended cooperation to the Government, my Party extended cooperation to the Government, when Mr. Sikander Bakht was the Leader of the House and the Minister, in getting the Patents Bill passed. You may have your different view. But the point I am trying to drive home is that simply because of the accident of change of seats, we do not change our policies. My question is, do you want cooperation? If you want cooperation, why are you queering the pitch? Why are you totally insensitive to the feelings of the people?

We have said umpteen times that we don not want to shield corruption, we do not want to hold brief for any guilty persons. But where is the guilt? Have you been able to establish it? I do not know what would happen. But surely, the initiative is to be taken by the Government, not by us. It has been stated in the Presidential Address that they would give statutory recognitioon to the Vigilance Coimmission. Who prevented you from doing so? For 13 months you were in office. You brought in two amendments to implement the verdict of the Supreme Court. You were so careless that you did not study the judgment of the Supreme Court while bringing in the amendment to the Central Vigilance Commission Act through an ordinance. That is why you had to supplement it by an additional emendment. But till date, you have not brought it for formal legislation. Who prevented you? We wanted to extend cooperation. You have stated it in the Presidential Address. Who prevented you from getting the legislations brought before the House and getting them passed? The mere saying it just from public consumption, playing to the gallery, is not going to help us.

The second point, Madam, which I would like to draw attention to, and which has not debated, is about paragraph 5. The Government comments on the outcome of the general elections. They have talked of the maturity of the Indian voter. Not only that. I would like to read a particular sentence. "The electorate has put an end to the phase of instability at the Centre by giving a clear and decisive mandate to my Government." They say that a clear and decisive mandate in favour of the Government has been given. I am not going into the aspect as to whether it is clear or decisive and whether it will end political instability But it is your assumption. It is your conclusion that political instability has come to an end by the verdict of the people. Again, in para 37 of the same Address, you say that you are going to appoint a Commission consisting of experts to look into the Constitution in the Context

of fifty years experience. There is nothing to object. You also said it last time. But what are you going to do now? You are suggesting two things—a constructive vote of confidence and a fixed term to the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas in order to prevent political instability, both at the Centre and in the States. Is it possible? Ours is a Parliamentary System. Our Parliamentary System is based on West Minster pattern. The cardical principle of our political system is that there is a fine balance between the political executive, the Council of Ministers and the elected representatives of the House. The elected representatives of the House have the right to remove the political executive by passing a vote of no confidence. At the same time, the political executive, headed by the Prime Minister, has a right in case of differences to make recommendations for the dissolution of the House. It was very nicely articulated by a British Prime Minister when he was reminded in the House of Commons that he is the servant of the House of Commons. The Prime Minister Baldwin's response was: "Yes, I do agree that I am the servant of this House. But I am that unique servant who has the privilege and prerogative of making recommendations for the dissolution of the House of Masters." Have you ever thought that by giving a fixed term to the legislature, by injecting political stability in the Legislature, are you not going to institutionalize instability in the executive? It is not an imaginary fear. What happened in France between 1945 till the arrival of Charles D Gaulle when he amended the Constitution? There was a joke that if you sit in a Paris 'Cafe' every third person you meet, will whisper into your ear that he was Minister in the department of so and so etc.etc. At the interval of every three months, four months and five months, the Ministry changed. you will institutionalize the political instability in the executive. I do not like the Budget of the Finance Minister. As M.P. I have fixed five years guaranteed term. Not only the individual but the groups of the political party will say: either change this Finance Minister or we are going to change you. I am not going into the merits of this matter whether it is a basic structure or not. That is for the lawyers to judge whether you will have the adequate majority or not. But the point which I am trying to drive is that your proposed changes will create more problems. Have you ever thought of that in order to find a remedy in one sector, you are going to create problems in another sector? You are talking of constructive vote of confidence. Ours is not a German system. Ours is totally a British system. Imagine a situation after 15th of April, 1999. Mr Vajpayee's Government had been voted out. A new Government could not be installed. In your concept of constructive vote of no confidence, either the Members will not have the right to bring the vote of no confidence or when the alternative Government cannot be formed, an alternative arrangement cannot be made, the old Government which was voted out of power will continue to remain in office. Therefore, Madam Vice Chairperson, I feel that the Government must applly its mind seriously to these issues. It is just not rhetoric. Let them think what they want to have?

You are talking of changing one of the very fundamental principles of secrecy of ballot by extending the facilities to the Armed Forces, by introducing proxy voting. I have no objection to that. All the facilities should be given to our Armed Forces to exercise their voting rights. If you find that in the present arrangement, the postal ballot system is not quite adequate, fine; improve that system. But the day you introduce proxy voting, the secrecy of voting will go, the secrecy of ballot will go. It will be known, and in the political situation and the economic situation of our country, one can easily imagine how much misuse it would lead to. You are not in a position to improve your postal ballot system, the existing arrangement. You are not in a position to achieve that, to ensure that everybody can use this postal ballot system so that it reaches them in time and the voters can exercise their voting right. Therefore, you have to subvert the policies and some of the very fine principles and institutional arrangements which have developed over the years are to be given up. Secrecy of ballot is one of the guarantees, an important guarantee, through which a voter can exercise his vote without fear or favour. If you do away with that in one section, there will be pressure on you from some other sections, and it will go on. Madam Vice-Chairman, I am sorry, I have to finish it. I don't know how much time I have taken. How much time have I taken, Madam?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have started around 12.41.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I don't want to take more than 20 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) : There is still time.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I would like to draw the attention of the Government towards it and request the Government to think over it. I have no problem if they have a debate. They came out with the nuclear doctrine during the time of elections. Dr. Manmohan Singh very clearly pointed out what they wanted to achieve through these objectives. We were told, when nuclear explosions took place, Pokhran II, "There is nothing to fear. We have taken care of our legitimate security requirements. The whole world has recognized it. We have exploded bombs." And within one year, you find that "It did not act as an effective deterrent!" We did not manufacture bombs, I agree. As a Minister, I was against nuclear weaponisation. But after 1971, during our regime, we did not have any attack from Pakistan, we did not have any Kargil. Within ten months of your nuclear weaponisation and explosion, your weaponisation did not act as an effective deterrent. You had Kargil, I am not going into that aspect any more.

Only one more point I would make and, thereafter, I will conclude. The Government is claiming that the economy is taking an upward turn. Yes, it is taking an upward turn because it was the lowest base. Therefore, statistically, it will move upward. If they have registered a negative export growth in a particular year, the next year, with a little improvement, they will have some statistical advantage. But how are they going to have an eight per cent growth rate? It is not merely by words. They are talking of reducing the expenditure. And in this year itself, they have created five departments and Ministries. They are talking of downsizing the Government and are giving the signal by creating more and more departments, have more and more bureaucratization. And they are saying that they will downsize the expenditure. But we feel that in the first four months, which is the lean season of the Government, their non-Plan expenditure is 29.2 per cent. I am not talking of the Plan expenditure. The Plan expenditure was much less compared to that. The fiscal deficit, they may say, is Rs. 79,995 crores because simply for according advantages they have transferred Rs. 25,000 crores, 75 per cent of the small savings from the Budget to the Public Account, and they may tell us, no; the fiscal deficit is not 1,04,000 crores of rupees; it is 79,995 crores of rupees.

1 P.M.

Whom are you fooling? Eight per cent growth will not come like words out of heaven. The minimum requirement in terms of investment should be 32 per cent of GDP. What is your savings rate? It is 26.1 per cent? About 80 per cent is coming from the household sector. A part of it cannot be transferred for real investment. You are expecting 10 billion dollars to come from FDI. Apart from ideological differences, which Mr. Malkani reflected yesterday in his observations, assuming that his views will not be taken into account by the Government of the day from where do you get that money? Where is that money? It is simply not available. I can give you one figure. It is the developmental report of 1997. The total investible surplus was 315 billion US dollars. Out of that, 63 per cent was invested within the European countries and industrialized countries. Of the remaining available, if 63 goes 37 remains, 68 per cent out of 37 was invested in the neo-industrialized countries of South-East Asia. What would be your share? Shri Chidambaram talked of 10 billion dollars in 1996. In 1999, you are talking of 10 billion dollars and if Dr. Manmohan Singh comes in 2001, he may have to repeat the same figure. That figure will simply not be available. I am coming to the point with which I started. Yes, we want cooperation; we want consensus. But, please show, not in words but in your actions, that you seriously mean it. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We adjourn the House till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

---

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock, The Vice-Chairman **(Miss Saroj Khaparde)** *in the Chair.*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) : Now we will continue with the Motion of Thanks on the President's Address. Shri Janeshwar Mistra.

**श्री जनेश्वर मिश्र** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह हर बार राष्ट्रपति महोदय के मुंह से सरकार अपना तैयार किया हुआ भाषण दोनों सदनों को सुनवाती है। राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है कई बार उस गरिमा के मुताबिक भाषण नहीं होता तो हमारे जैसे आदमी को चोट लगती है। कभी-कभी मन करता है कि महामहिम से हम कह दें कि बेहतर होता कि आप अपने मन से ही भाषण तैयार करके बोल दें। यह भाषण, सत्ता पक्ष के लोगों ने हम से कहा कि इतना उबाऊ भाषण हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। लेकिन यह केवल उबाऊ नहीं रहा इसमें इस सरकार में कई तरह के तत्व मिले हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान में पलटनी शासन को ले करके राष्ट्रपति महोदय के भाषण में चिंता जताई गई है और जब पलटनी शासन लगा था तो इस सरकार के एक मंत्री महोदय ने बयान दिया था कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और वह मंत्री, थोड़ीसी इमरजेंसी लग गयी थी, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो रहे थे तो बहुत से पुल उड़ाने के लिए डायनामाइट लेकर घूम रहे थे। महोदया, लोकतंत्र किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, वह एक सिद्धांत है, जिंदगी का रास्ता है और पाकिस्तान कोई दूसरा मुल्क नहीं। आज से पचास साल पहले वहां के लोग हमारे लोग थे या हम लोग उन के थे। हां, हुकूमत कुर्सी पर किस की बैठती है या यहां किस की बैठती है, यह बहस नहीं है। बहस यह है कि इस समय वहां के लोगों की दुर्दशा क्या हो रही होगी? कोई भी आदमी बोल नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण मंत्री बोल दे कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है तो उस समय मैं बहुत बौखला गया था क्योंकि वह आदमी हमारे नेता थे, उम्र में हम से बड़े थे और इसलिए हमने सोचा कि क्या बोल रहे हैं? महोदया, इमरजेंसी में जब हम लोग बंद थे तो जेल में बी० बी० सी० रेडियो खोला करते थे क्योंकि जानते थे कि हिन्दुस्तान का रेडियो हिन्दुस्तान के लोगों की आजादी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हम वहां बी० बी० सी० रेडियो इसलिए सुना करते थे कि दुनिया के और देश हमारे लिए क्या बोल रहे हैं? महोदया, आज पाकिस्तान के लोग यह इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दुनिया के और देश क्या बोल रहे हैं, तब तक हमारे देश के एक मंत्री महोदय ने बोल दिया कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। सच में जब अमेरिका वालों ने वहां के लोकतंत्र के लिए और वहां के पलटनी शासन के खिलाफ चिल्लाना शुरू किया तब भारत सरकार की तरफ से भी थोड़ी-बहुत टिप्पणियां आई, लेकिन जो पहली टिप्पणी थी वह बहुत खतरनाक थी। महोदया, मैं समझता हूं कि सरकार की टिप्पणी और हो, किसी मिनिस्टर की टिप्पणी और हो तो ऐसी सरकार में ऐसे घटक हैं कि कोई पूरब की तरफ देखता है तो कोई पश्चिम की तरफ देखता है, कोई उत्तर की तरफ देखता है तो कोई दक्षिण की

तरफ और इसी को सरकार की दिशाहीनता कही जाती है। महोदया, इस पूरे-के-पूरे भाषण में दिशाहीनता का परिचय मिलता है। यह दिशाहीन भाषण है। इस में मुल्क को कोई दिशा नहीं दी गयी है। मुल्क को यहां तक नहीं बोला गया है कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उन को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा । इस में बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बोला गया है, लेकिन उनकी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी, यह नहीं बताया गया है। तो सिवाय थोथी दलील के कोई दिशा न देना, इस भाषण का प्रमुख लक्षण रहा है।

महोदया, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपनी समय सीमा जानता हूं। मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स को एक-एक कर छू देने की कोशिश करूंगा। सब से पहले बड़े गर्व के साथ इस में कारगिल विजय के बारे में कहा गया। महोदया, जब हमारी सरहद के भीतर घुसपैठ और पाकिस्तान की पल्टन आ गयी, अब किस की गलती से आई मैं यह दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस बारे में बहुत लोग बोल चुके हैं, यह सच है कि हमारी पल्टन के जवानों ने जान की बाजी लगाकर भारत माता की हिफाजत करने की कोशिश की। उन जवानों का अभिनंदन होना चाहिये, लेकिन मैडम क्या यह हमारी जीत थी? महोदया, मैं इस सदन के मार्फत देश से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी पल्टन ने पाकिस्तान की पल्टन को सरहद के बाहर मारकर भगा दिया? क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को बुलाकर डांटा कि तुम्हारी पल्टन भारत की सरहद के भीतर क्यों गयी, उसे वापिस करो और एक नौकर की तरह से उन्होंने कहा कि हुजूर हफ्ते, दो हफ्ते में वापिस कर लेंगे । उस समय प्रधान मंत्री जी ने विरोधी पक्ष के लोगों को बुलाया था। महोदया, मुलायम सिंह जी नहीं थे और हम से कहा गया कि चले जाना तो हमने कहा कि अगर पाकिस्तान की पल्टन मारकर भगा दी जाती तो सरहद पर जितने लोग हैं उनके लिए हमारी पल्टन का आतंक बढ़ जाता, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर पाकिस्तान की पल्टन जा रही है, हमारा आतंक और रौब खत्म हो गया है। इसको विजय कहा करते हैं। कई बार हमने चुनाव के दौरान देखा, एक नेता की फोटो है दुपट्टा डाले हुए, वोट के लिए आजकल जैसे किसी देवी की रोरी लगा लिया करते हैं, माथे पर रोरी लगाए हुए और हाथ लहराते हुए, कहा जाता है—कारगिल नायक। क्या वाकई हम नायक हैं? हमने पाकिस्तान की पलटन को हराया है या क्लिंटन के कहने पर पाकिस्तान की पलटन वापस गई? इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि यह मुल्क बहस किया करे।

मैडम, कांग्रेस के बारे में एक बार चीनी आक्रमण हुआ था। चीन की पलटन अपनी तरफ से हमको रौंदते हुए आई और अपने आप लड़ाई बंद करके वापस चली गई। हमने राहत की सांस ली थी। क्या यह सच नहीं है कि अब की बार भी क्लिंटन ने जब कह दिया कि पलटन वापस करो तो हिन्दुस्तान की सरकार ने राहत की सांस ली थी? इसको हम अपनी डिप्लोमेटिक जीत मानते हैं। भारत माता का यह अपमान हुआ है। कोई बाहरी आदमी आकर के हमारी मां की बांह पकड़ ले, उसके बाल पकड़ ले और उसी समय एक वही मंत्री, जो आजकल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कह रहा है, उसने बयान दे दिया कि अगर सुरक्षित लौटना चाहते हो तो तुम्हें हम बढ़िया किस्म का रास्ता दे देंगे, चुपचाप लौट जाओ। यह मां का अपमान है। जो लोग सबसे बड़े रखवाले हैं, जो लोग हिफाजत कर रहे हैं, वह रास्ता दे रहे हैं। हम लोगों को तिलक ने, गोखले ने, चन्द्रशेखर आजाद ने, महात्मा गांधी ने बताया था कि यह जमीन मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह भारत माता है और इधर मां पर कोई हमला करे और उस समय सबसे जिम्मेदार बेटा यह बोलेगा कि हम तुमको सुरक्षित रास्ता दे देंगे, तुम चुपचाप वापस लौट सकते हो। यह

बयान था रक्षा मंत्री का लड़ाई के दौरान । इतना शर्मनाक बयान, कि हिन्दुस्तान की जनता उसको पी नहीं पाई। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने उस बयान को, या भाजपा के लोगों ने उस बयान को पसंद नहीं किया था, जो लोग सरकार चला रहे थे उन्होंने पसंद नहीं किया। रक्षा मंत्री ने पश्चाताप किया या नहीं, यह सवाल नहीं है। एक बार हमारी मां का अपमान रक्षा मंत्री की किसी बोली से हो जाए तो यह अपने आप में शर्मनाक बात है। पछतावा या माफी मांगना मां के सम्मान के सामने कोई मतलब नहीं रखता। यह स्थिति है। हम चाहेंगे। कि इसको नोट किया जाए, हमारी पलटन को सेहरा नहीं मिल सका कि पाकिस्तान की पलटन को सरहद के बाहर भगा सके। यह सेहरा क्लिंटन के फरमान को मिला। नवाज शरीफ गिडगिड़ाते हुए अपनी पलटन लेकर वापस चले गए। इसलिए इस बात को बहुत तूल देकर और जोर के साथ कहने की सरकार को जरूरत नहीं है।

मैडम, यह सच है कि हमारे जवानों ने अपनी कुर्बानी दी और आज राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण में कह रहे हैं कि पलटन को सरहद पर लड़ने के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें सारे साजो-सामान से लैस करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पिछली लड़ाई में सारे साजो-सामान से हमारी पलटन लैस नहीं थी। इस पर मैं सार्वजनिक रूप से बहस नहीं करूंगा। पलटन के जवान जो लौटकर आते हैं, वह बताते हैं कि सरहद पर, उस पहाड़ी पर, पथरीली जमीन पर, बर्फीली जमीन पर जाने के लिए जिन कपड़ों और जूतों की जरूरत होती है वह उनके पास थे या नहीं थे। इस बारे में सरकार कभी सोचती नहीं, आज इस बात की जरूरत महसूस हुई, इसकी मुझे खुशी है।

मैडम, सबसे गंभीर जो बात इस समय देश में छिड़ी है, वह है संविधान संशोधन आयोग की। यह बहुत गंभीर बात है। उस आयोग में, मुझे अच्छी तरह से याद है पहले कहा गया अपने घोषणा-पत्र में, भाजपा गठबंधन के घोषणा-पत्र में, कि संसद और विधायिका का कार्यकाल पांच साल का रखा जाएगा, वहीं एक बहुत बड़े नेता का बयान हमने पढ़ा एक दिन, जो इस समय सरकार में है, कि उस आयोग के विचाराधीन लोकतंत्र में राष्ट्रपति पद्धति भी होगी। हमने सोचा यह क्या हो रहा है? असल में जो कोई भी कुर्सी पर बैठता है, और यह सरकार तो केअर-टेकर थी, केअर-टेकर सरकार आमतौर पर जितनी अब तक आई हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की हो या चन्द्रशेखर जी की हो या गुजराल जी की हो, हिंदुस्तान की जनता ने केअर-टेकर सरकार को दुबारा यहां आने का मौका नहीं दिया। हिन्दुस्तान का लोकतंत्र बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। जिस किसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उस सरकार को दोबारा आने का मौका नहीं दिया गया। लोकतंत्र की इस खूबी को और भारतीय लोकतंत्र की इस खूबी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बारीक बात यह है, मैडम, कि हिन्दुस्तान की मिट्टी लोकतंत्र की मिट्टी तो थी नहीं, कभी यहां के आदमी ने अपना मालिक बनाया नहीं था। हिन्दुस्तान जब से बना, जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते भरत खंडे, तब से हिन्दुस्तान के आम आदमी ने अपना मालिक नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। कोई मालिक होता था, राजा होता था, वह मर जाता था तो उसका बेटा मालिक हो जाता था। किसी दूसरे राजा की पलटन हमला करती थी, वह जीत जाता था, राजा बन जाता था। हिन्दुस्तान की जनता को मालूम नहीं था। सन् 47 में भी अगर संविधान बनाकर के चुनाव करा दिया जाता तो एक राजनीतिक परिवर्तन के साथ हिन्दुस्तान की जनता मान लेती कि हमने अपना मालिक बनाया, लेकिन उस समय पंडित जी प्रधान मंत्री बन गए, जनता के बीच चुनाव नहीं हुआ 52, 57, 62, जो मालिक है, वही मालिक रहा और यह सिलसिला चलता रहा। थोड़ा-बहुत 1967 में जब डा० लोहिया

ने संविद का प्रयोग किया, गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर के, तो हमको अच्छी तरह से याद है कि कुछ सूबों ने करवट बदली, लेकिन 1977 में पहली मर्तबा हिन्दुस्तान की जनता ने महसूस किया कि अगर हमारी उंगली पर काली रोशनाई लग गई तो दिल्ली बदल जाएगी और जनता जब मैं कह रहा हूं तो सांसद को नहीं यह दफ्तरों में काम करने वाले अफसर नहीं, जनता जब में कह रहा हूं तो सड़क पर जूते में कील ठोकने वाला मोची भी, झाड़ू देने वाला जमादार भी, खेत में हल चलाने वाला हरवाहा भी, सड़क पर रिक्शा चलाने वाला भी, इन्होंने महूसस किया कि अगर हमारी उंगली पर काली रोशनाई लग गई तो दिल्ली बदल जाएगी। यह पहली मर्तबा 1977 में महसूस किया गया। हिन्दुस्तान के सबसे अंतिम आदमी ने महसूस किया कि अगर हमारी उंगली में काली रोशनाई लग गई तो हम दिल्ली बदल सकते हैं इंदिरा जी को हटा दिया, राजीव जी को हटा दिया, चौधरी चरण सिंह को हटा दिया दिया, मोरारजी भाई को हटा दिया, चन्द्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो हटा दिया। जब से यह मिट्टी बनी थी हिन्दुस्तान की जनता और अंतिम आदमी को यह अहसास नहीं था कि हम अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं और ज़रुरत पड़े तो बदल भी सकते हैं। बनाने वाली प्रक्रिया तो 1952 से शुरू हुई, बदलने वाली प्रक्रिया 1977 से शुरु हुई। अब जो कोई भी गद्दी पर बैठता है उसको चिंता होने लगती है कि ये जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं दो साल में बदल दिया, ढाई साल में बदल दिया, जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं, टिकाऊ सरकार होनी चाहिए, समय पर चुनाव होने चाहिए, सरकार बने न बने। अभी प्रणव मुखर्जी साहब कह रहे थे कि क्या होगा अगर सरकार गिर गई और विकल्प की सरकार नहीं बनी तो? फिर जो घोड़ा है वह सरकार चलाएगा? नहीं। फिर घोड़े वाली खरीद-फरोख्त शुरु होगी, पार्लियामेंट घोड़ा बाजार बन जाएगा और पार्लियामेंट को घोड़ा बाज़ार बनने से बचाने के लिए इस तरह का कोई भी आयोग गठित होता है तो नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि संविधान संशोधन के लिए आयोग गठित हुआ, आयोग ने रिपोर्ट दे दी, उसमें प्रधान मंत्री को पूरी ताकत दे दी, संविधान संशोधन की कुछ प्रक्रिया हुआ करती है, लेकिन किसी भी आयोग की रिपोर्ट पर अगर सदन में प्रस्ताव आता है तो बहुमत और अल्पमत के लिए जो पहले पैमाने बने होते हैं संविधान संशोधन के और मूल अधिकारों के, वह कोई ज़रूरी नहीं हुआ करते। इस तरह लोकतंत्र का कपड़ा पहनकर हिटलर तानाशाह हुआ था। मुझे खतरा लग रहा है कि इस समय जो सरकार सत्ता में बैठी है, वह तानाशाह के रास्ते पर जाना चाहती है, संविधान से छेड़खानी करना चाहती है। दो साल, ढाई साल, पर सरकारें गिरी हैं, 13 महीने पर सरकार गिरी है, रिकार्ड है, लेकिन जो सरकारें लम्बे समय तक रही हैं, उन सारी सरकारों में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं।

पंडित नेहरु की सरकार बहुत लंबे समय तक थी। उस समय मूदड़ा कांड हुआ था। उस समय श्री टी॰टी॰ कृष्णामाचारी वित्त मंत्री थे। बंबई हाई कोर्ट के जज छागला जी ने इसकी जांच की और उन्होंने वित्त मंत्री को दोषी पाया और पंडित जी के ज़माने में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शराफत का ज़माना था। उसके बाद इंदिरा जी के ज़माने में लाइसेंस का घोटाला हुआ। यह है टिकाऊ सरकार का उदाहरण। तुलमोहन राम केस हुआ। उस समय ललित नारायण मिश्र रेल मंत्री थे। उनको पटना में लोगों ने गोली से मार दिया, वह भी मुलज़िम थे। उसके बाद राजीव गांधी का केस हुआ बोफोर्स कांड हुआ जिस पर कल से यहां बहस हो रही है। यह भी टिकाऊ सरकार का एक नमूना है। उसके बाद नरसिंह राव जी का टिकाऊ सरकार का मामला सामने आया। पता नहीं हमारे यहां कोर्टस में कितने मुकदमे चल रहे हैं। जहां कहीं भी जनता अशिक्षित होती है, जहां कहीं भी जनता गरीब होती है, वहां टिकाऊ सरकार का मतलब

भ्रष्टाचार होता है। इसलिए टिकाऊ सरकार 5 साल की सरकार, 10 साल की सरकार, इस पर बहुत बहस हो रही **(समय की घंटी)** क्या हुआ मैडम? अभी तो बात खत्म नहीं हुई है हमारी, शुरु भी नहीं हुई....**(व्यवधान)**

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** मिश्र जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और जब आप बोलते हैं तो वाकई हम लोगों का सुनने का मन करता है लेकिन समय की सीमा के कारण घंटी बजाना जरुरी था।

**श्री जनेश्वर मिश्र:** तो आप समय बढ़ा दीजिए, यह तो आपके हाथ में है। मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करुंगा कि उस सम्मान में कमी आए। चेयर का मैं बहुत सम्मान करता हूं। महोदया, मैं टिकाऊ सरकार की बात कर रहा था। यह जो गैर-टिकाऊ सरकारें बनीं, इनके बारे में जनता ने कहा कि ये निकम्मे हैं, हर दो साल में आ जाते हैं, ढाई साल में लौट आते हैं। अब की बार 13 महीने वाली सरकार ने चुनाव के मैदान में कह दिया कि हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि 5 साल में चुनाव होगा।

महोदया, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में पैरा 5 में कहा गया है कि गैर-टिकाऊपन का माहौल खत्म हो रहा है। जनादेश ने यह बता दिया है लेकिन जिस तरह से वोट लिया गया था, वह आपने देखा होगा। मैं इलाहाबाद में जिस घर में रहता हूं कई बार वहां सवेरे के समय भिखारी आता है। सवेरे के समय जो भिखारी आता है उस पर बहुत दया आती है क्योंकि दिन में तो आदमी काम-धंधे में व्यस्त रहता है तो वह उसको 5 पैसे या 10 पैसे दे देता है। सवेरे कोई भिखारी यह कहते हुए आ जाए कि बाबा, कुछ दे दो तो एक रुपया या दो रूपया आदमी दे देता है।

अब की बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यह कोशिश की थी कि इनको निकलने न दें। विधानसभा के क्षेत्र के हिसाब से 130 से ऊपर सीटों पर हमने कब्ज़ा कर लिया जब कि भाजपा ने केवल 124 पर कब्ज़ा किया। मैं मनमोहन सिंह जी से निवेदन करुंगा कि आपके दोस्त लोग भाजपा पर कम और हम लोगों पर ज्यादा हमला करते रहे हैं। आपके हमलों के कारण इन लोगों को थोड़ी शरण मिल गई, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

महोदया, एकबारगी मैंने सुबह अखबार देखा आंखें मलते हुए तो अखबार में एक सबसे मोटी लाईन थी मुझे एक वोट दे दो। मैं घबरा गया कि यह वोट मांगने का क्या तरीका है। नीचे लिखा हुआ था कि पिछली बार मैं एक वोट से रह गया था, अब की बार एक वोट दे दो, बाबा। लगता था कि जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा है, वोट नहीं मांग रहा है, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है कि एक वोट दे दो। महोदया, हिंदुस्तान की जनता भी बड़ी माहिर निकली भीख देने में। उन्होंने एक वोट मांगा तो जनता ने 181 का 182 कर दिया। इतना बढ़िया दाता कहीं नहीं मिलेगा। लगता था कि जैसे दाता ने बनिए की दुकान खोल ली कि जितना पैसा मांगोगे उतना ही मिलेगा। इन्होंने एक वोट मांगा तो 181 का 182 कर दिया।

**श्री गोविन्दराम मिरी** (मध्य प्रदेश): मांगना भी एक कला है, सबको मांगना नहीं आता। सबके मांगने से मिलता भी नहीं है।

**श्री जनेश्वर मिश्र:** छोड़िए लेकिन दया के नाम पर अगर हिंदुस्तान की जनता पिघल जाया करती है तो मैं आज यह चेतावनी देना चाहता हूं कि एक बार सीता के ज़माने में भी भिखारी गया था, कटोरा हाथ में लेकर गया था और सीता पिघल गई थी और सीताहरण हो गया था। कहीं अब की बार के भिखारी के हाथों पूरे के पूरे लोकतंत्र का हरण न हो जाए। इस बात का खतरा मुझे लगातार महसूस हो रहा है। मैडम, बातें तो मुझे बहुत करनी थीं, मुझे डीज़ल के दामों के बारे में भी बात करनी थी। महोदया, अभी एक राज्य मंत्री ने बयान दे दिया कि कुकिंग गैस और केरोसिन का दाम भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह बयान दे दिया जब कि अभी सरकार का कोई फैसला नहीं हुआ है। डीज़ल गायब हुआ, हमारी सड़कें सूनी हैं, हमारे खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है, किसान की फसल सूख रही है, डीज़ल महंगा होने से सड़कें सूनी हैं। फसल सूखी और कुकिंग गैस भी महंगी हो गई तो हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। अगर राशन महंगा हो गया तो हमारे घर का चिराग नहीं जलेगा। मैं चाहता था कि सरकार अपनी घोषणा इस पर करती कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान इस पर हम लोग चर्चा उठाते जनता के दर्द का। लेकिन इस पर केवल राज्य मंत्री के बयान पर चर्चाएं उठ रही हैं। मैडम् आखिरी बात कहकर मैं खत्म करूंगा।

हमारी पार्टी पर महिला आरक्षण के बारे में तोहमत लगती है। लेकिन हम ऐसे हैं, हमारी पार्टी डा० लोहिया के लोगों की पार्टी है। डा० लोहिया ने जो नर-नारी 7 क्रांतियों का दर्शन दिया था देश, दुनियां और मानवता को उसमें नर-नारी समता की एक क्रांति भी थी। हम लोगों के चरित्र पर ऊंगली मत उठाइए। मुझे याद है मैं पैट्रोलियम मंत्री था, इस सदन में आया। उस समय महिलाओं के लिए गैस की बात की जा रही थी कि महिलाओं का भी कोटा आरक्षित करो। जब गाईड लाईंस तय होने लगी तो हमने तेतिस सैकड़ा कोटा आरक्षित कर दिया। हमने महिला मित्रों से कहा जो संसद की सदस्य थी कि यह तेतिस, सैतिस कयों कर रही हैं जैसे ग्रामोफोन की सुई फंस जाती है, यह तीस भी तो हो सकता है, पच्चीस भी तो हो सकता है, चालिस भी तो हो सकता है, एक ही जगह रट क्यों लगा रहे हैं? लेकिन तुम लोगों ने रट लगाया तो तेतिस कर दिया। लेकिन यह आरक्षण दलितों को क्यों दिया जाता है? इसलिए कि समाज के जो अगड़े वर्ग के लोग हैं उनका वह मुकाबला नहीं कर सकती नौकरी में, चुनाव में, राजनीति में क्योंकि वह पछड़ी हैं। पछड़ों को नौकरी में मंडल कमीशन के आधार पर क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है?

**श्री संघ प्रिय गौतम** (उत्तर प्रदेश): आपसे बाजी मार ले गए चार से चौदह हो गया बी०एस०पी० के----**(व्यवधान)**

**श्री जनेश्वर मिश्र:** हम यहां चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। समाज में जो कमजोर होता है उसको ज्यादा मौका दिया जाता है। घर में जो लड़का पोलियो का रोगी होता है उसको एक गिलास दूध ज्यादा दिया जाता है। यह सिद्धांत है और उस हिसाब से जब महिलाओं की बात छिड़ी, हम भी पहले मना करते थे कि इनका आरक्षण होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बड़े घरों की महिलाओं के मुकाबले वह महिला जो घास काटती है अपनी भैंस के लिए, जो उसका दूध निकालती है, जो गोबर हटाती है, जो गरीब की औरत है, दलित की औरत हैं पछड़े की औरत है, अल्पसंख्यक की औरत है वह बड़े लोगों की महिलाओं के मुकाबले खड़ी नहीं हो सकती। रामगोपाल जी हमारे नेता हैं, उम्र में वह हमसे छोटे हैं।

उन्होंने हमारी सोच को संशोधित किया। उन्होंने ने कहा कि अगर यह आरक्षण देना ही है तो मुकम्मिल दो, जो बहुत पछड़े हुए हैं उनको ज्यादा दे दो। हमने इनकी बात को माना और मान करके हमने फिर कहा कि चूंकि महिलाएं पछड़ी हैं मर्दों के मुकाबले तो उनको आरक्षण दो। तेंतिस दो, तेरह दो या पचास दो। यह तो नहीं करेंगे ढपोल शंख की तरह। लेकिन इतना कहूंगा कि जरुर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो बहुत पछड़ी महिलाएं हैं वह अगड़ी महिलाओं के मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती मैदान में। उनको थोड़ा आरक्षण देना पड़ेगा। यह इस बात को लेकर के जब हम लोग रुकावट डालते हैं तो कहा जाता है कि हम आरक्षण विरोधी हैं। मैडम् हम चाहेंगे कि बहुत सी भ्रांतियां जहां बीच-बीच में उठती रहती हैं उन पर बहस होनी चाहिए। कानून बनाने वाले लोगों से कहेंगे कि जिन के हाथ में बहुमत है और वह बहुमत के बल पर कानून बना सकते हैं। लेकिन बहुमत के दम्भ में बना हुआ कानून लम्बे समय तक चला नहीं करता। कानून कहीं न कहीं टूट जाया करते हैं। अदालत से टूटता है या मैदान में टूट जाता है। अब रह गई बात कि गैर टिकाऊपन का जमाना चला गया, अब टिकाऊपन का जमाना आ गया। हम लोग 1977 में जब सत्ता में आए थे तो हम लोग मान करके चलते थे कि अब हम लोगों को कोई नहीं उठा सकता। ढाई साल में हम लोग लुढ़क गए। राजीव गांधी साहब जब आए, इंदिरा जी जब दोबारा आई तो लोग कहते थे कि कोई नहीं हटा सकता। उनको एमरजेंसी का सहारा लेना पड़ा। राजीव गांधी साहब दो साल में बोल गए। यह मोर्चा वाले जब आए थे तो कहा था कि हम एक हो कर आ रहे हैं अब हम आपस में टूटेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी हाल की जीत है, बहुत इतराने की कोशिश मत करना। छः महीना, आठ महीना के बाद जिन बैशखियों पर आप खड़े हैं वह चरमराना शुरु करेंगी। हम विपक्ष के आदमी हैं। आपकी कोई भी बैसाखी कभी भी चरमराएगी तो हमारा विपक्ष और राजनीति का धर्म बोलता है कि उस बैसाखी को धकिया करके आपको लड़खड़ाने के लिए मजबूर करेंगे।

पिछली बार भी हमने नहीं आपको गिराया, इन कांग्रेस के लोगों ने आपको नहीं गिराया। आपकी ही एक बैसाखी फिसल गई तो हम क्या करते? हम लोग जब गिरा करते थे तो हम लोग अपने से नहीं गिरा करते थे। हमारी बड़ी बैसाखी इन लोगों की हुआ करती थी, वह चट से फिसल जाती थी हम धमाके से गिर जाते थे। बैसाखियों के बल पर चलने वाली सरकारें हैं, कब कौन बैसाखी कहां से चरमराएगी, इसका कोई ठीक नहीं। इसलिए सत्ता में आए हुए लोगों, मामूली सत्ता पाने के बाद एक महीने के अंदर इतराने की कोशिश मत करना। इस अभिभाषण में कुछ नहीं है, यह दिशाहीन है। सरकार के मंत्रियों के बयान गैर मौजूवाद हैं इसलिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका विरोध करता हूं।

SHRI PRAFULL GORADIA (Gujarat): Madam Chairperson, thank you for the opportunity to allow me to stand and support the Motion of Thanks that has been moved on the Address of the hon. Rashtrapatiji on the 25th of the October. As a whole it is splendid agenda for good governance for the years to come. I would particularly like to focus attention on paragraphs 45, 46, and 47 which really if implemented which I am sure will be—will give India a very high and respectable place in the comity of nations. But I am not going by my optimism. My optimism is not based only on what has been promised in the Address. I would like to refer to the performance of the

erstwhile Vajpayee Government which was governing until earlier this month. Its performance during its short tenure was, I think, equivalent to a diplomatic miracle. Since 1947 when the Kashmir issue was first opened, we have found most of the world arraigned against us; we were always being beaten, criticised, thrashed in the world fora. This went on for years and years. It was not confined only to the issue of Kashmir. When our troops marched into Goa to liberate the State from its long colonial rule, we were criticised equally badly. So were we in 1962. Even India-lovers like President Gamal Abdel Nasser, President Josi Tito also remained silent while India was being invaded. Then, of course, another great friend of India Premier Nikita Khruschev, said "Chinese brothers" and only casually "Indian friends". This we have seen for years and years with many countries against us. I felt, not knowing sufficiently of what is going on, that perhaps in 1999 it will be the same sad story. But then with the advent of Kargil, we discovered that, as I called it, a diplomatic miracle had been performed by the enormous work evidently done by the Ministry of External Affairs led by Foreign Minister Jaswant Singh. Now this optimism of mine make me to suggest to make one or two suggestion which can perhaps take India even farther into the comity of nations. I am referring here to a fact that we have 116 embassies and high Commissions and they are all run in the traditional style with first class officers, but, again, trained traditionally who occasionally take courses in Jawaharlal Nehru University or the Institute of Foreign Trade.

But they themselves are not commercial managers. Now, we know that trade has really replaced war as an instrument of bringing home the surpluses of the other economies. Yet, our embassies are, I think, organized—correct me if I am wrong-on the traditional style of diplomacy. I do not think there are more than 8, 10 or 12 countries with which there is a need for diplomacy, followed by defence. Yes; we have our problems with Pakistan; we have some issues pending with China; we also have an odd issue pending with Bangladesh; we buy weapons from Russia; we import weapons from France, Germany, the U.K., the U.S.A., and perhaps, even from Israel and South Africa. Let us say even 16 nations, but what about the other hundred nations? Take for example, Argentina or Brazil. Are we even going to fight a war with them? Do we have anything more than the hope of better international trade? I don't think so. Perhaps, we can attract more tourists. That is all. Our embassies are led by very good foreign service officers. They are trained in traditional diplomacy but they are not experts in international trade. This is one major change which should be considered by the Government.

The other thing I would like to mention is about the Pacific Ocean Region. I think, it has largely neglected by us. We have always had a predilection towards the Atlantic Ocean Region, which is a non-growth area. Even the

United States had started shifting its balance years ago, not quite away from the Atlantic Ocean Region, but certainly giving sufficient emphasis to the Pacific Ocean Region, which is a much larger ocean, which is a much richer ocean below the surface, and I think, has enormous food supplies; plus, it is rimmed by the growth countries like China, Japan, Taiwan, New Zealand, Austrialia, etc. Therefore, much greater emphasis needs to be given to the Pacific-side of the world and let us not just be Atlantic-oriented as we have traditionally been. I just would like to show how Atlantic-oriented we are. Today, our biggest mission abroad as far as I know is, in the United Kingdom and not in a country like China or Japan or, for that matter, even in the United States. In order to bring about the reforms, my modest suggestion is that the Department of International Trade should be merged with the Ministry of External Affairs so that a new thrust can be given to India's international trade, which is less than 1 per cent, while we are exactly 1/6$^{th}$ of the world's population. Our international trade is not even 1 per cent. I think, this needs to be repaired and improved. I am sure, in the years to come, with the kind of Agenda we have ahead of us, all these improvements will be made. With these words, I once again suport the Motion of Thanks that has been moved. I thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to speak.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Madam Vice-Chairperson, the customary speech made by the hon. Pesident to the Joint Session of Parliament consists of several items. Certain objectives have been set, along with an action plan in certain fields. But when we look back, we feel that most of the things that are said are a repetition of what had been said in the President's Address of 1998. For example, there is a mention about the Bills to be passed or the enactments to be made such as the 33 per cent reservation for women, electroal reforms, legislation for setting up of the Lok Pal to combat corruption in higher places. These are certain legislations which they promised to bring at that time also. Along with them, there is an announcement about the establishment of a development bank for women entrepreneurs. But during the 13 months of power, they could not pass these legislations; they could not even form or establish the Development Bank for Women Entrepreneurs. It was not due to lack of time.

Then, I come to the legislation providing reservation for women in the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas. There are some parties which had opposed it. They did not oppose the whole idea, but they had asked for certain amendments. But even with all that, as far as I understand, majority of the MPs or majority of the parties were in favour of passing the legislation. Then, why it could not be passed? It could not be passed just because of the fact that the then Government did not have the will power. They did not have the determination and the will power to do it. Therefore, even now

when they say that these things will be done, I do not believe it. If it is done, it will be good.

Then, I come to the financial and economic position of the country. In the President's Address, a bright, or, a rosy picture has been painted. For example, it is said that there was a growth rate of 6 per cent. Then, in respect of the balance of payments position, it has been said that we are in a comfortable position. Regarding the foreign exchange reserves, it has been said that we have 33 billion dollars. Then, so far as the rate of inflation is concerned, it has been said that it is only 2 per cent, calculated on the basis of the wholesale price index. Of course, these are certain aspects of the financial and economic position. But the financial position, or, the economic position, which the country is facing at the moment is very, very serious. The Government itself has made it clear that the revenue realization is far below the budgeted target. Then, the expenditure has gone about the budgeted target by 18 per cent. The financial deficit has gone up by 6 per cent. Along with that, there are certain other facts also. Unemployment has increased; poverty has increased. All these things are there. Therefore, why should these factors be concealed? Without taking these factors into account, how can the Government say that the economic position, the financial position, is quite safe? It is not correct. In order to improve the financial and the economic situation, they have come forward with certain remedial measures. The remedy that they have suggested is to go ahead with the economic reforms programme. Or, to be more precise, the second generation of economic reforms programme will have to be implemented with determination and with a high speed. This is what they say. What has been the experience of the implementation of the first phase of economic reforms? That we have to look into. I have already said that the present situation is very serious. The implementation of the economic reforms programme, which is followed by the new Government, is not at all a new programme. It has been there for the last eight years. The economic reforms programme was first introduced and implemented in 1991. We know the circumstances in which those economic reforms were thrust on the country. How we were forced to agree to it, that we all know. I will not go into the details. But have those economic reforms in any way helped our country to have a sustained and continuous growth? What is our experience? Sir, during these eight years, we have faced two recessions; the second recession started three years ago and it is still continuing. The Government cannot say that we are on the verge of overcoming that economic recession. That position is there. You look at the field of industry. Thousands and thousands of factories are lying closed and thousands and thousands are on the sick list and they are on the verge of closure. Lakhs and lakhs of workers have been thrown out. This is the situation. Therefore, if you look at the details and examine the whole

situation, these economic reform programmes have landed our country in a very disastrous situation. The effect is very disastrous. It is not only the experience of our country; it has been the experience of various other countries in the world. Sir, due to lack of time, I do not want to go into more details. Now, even the experts of the World Bank say that by the liberalization programmes, by all these economic reform programmes; poverty, unemployment and such other problems cannot be solved. Therefore, those who are the exponents of these new economic reform programmes, are all now saying that along with the economic reform programmes, something additional will have to be done in order to reduce poverty and unemployment, and also to ameliorate the condition of the poor people. That is being suggeted. Sir, ignoring all these things, now, the present Government says no; we will go ahead with the second generation economic reform programmes. That is a policy that will lead to disaster. While stating about their objective, they quote Mahatma Gandhi, as if Mahatma Gandhi had said that there shall not be people of a high class and a lower class in the country. The demand of the poor people should also be met. All these things are being said. It is said that equality should be maintained. But what is the real position? Wherever the economic reform programmes have been implemented, it is now accepted all over the world that the gap between the developed countries and the developing countries is becoming wider. Even in individual countries, the gap between the developed areas and the underdeveloped areas is getting wider. The gap between the rich and the poor is becoming wider. All the facts prove that. This position is there. Then, how can you say that the poor people will be looked after, their interests will be looked after, by implementing all these reforms? Therefore, what I have to say is that this Government, if they are earnest in giving an effective governance, should try to make a review of the economic policy that they are pursuing, or else it would lead the country to disaster. Then, there is another issue. It is said here that the interests of the labour will be looked after. But what is the condition of the labour at present? I have already said that thousands of factories are lying closed and lakhs of workers have been thrown out. Sir, if you look into the details, you will see that these workers have been denied even the legitimate legal dues. Sir, before the closing down of these factories, they were not getting their real wages which were due to them, according to the Payment of Wages Act. They were entitled to get gratuity; but they have not got it. They were entitled to get Provident Fund; but they have not got the Provident fund. They have not got the retrenchment benefits. They are being deprived of all these benefits. Is there a Goverment here to look after the interests of the workers? The law in the country guarantees all these. But the employers are violating it. Take the case of minimum wages. Instead of it being implemented, it is being broadly

violated all over the country. Now, on the basis of liberalization and globalisation and new economic reforms, whatever development that had taken place in the industries, has actually led to a phenomena where, in every industry, workers are being retrenched. They are being thrown out under the VRS. Even their normal wages are not being given. Number of workers are being, in fact, reduced. If you look at each case of new factories, you will find that only 250 workers may be on the register. The others are not on the register. Those who are not on the register, are not being given any legal benefit. They are not being given what is normally due to them under the law. That is what is happening now.

Madam, a new situation is developing in the country. In several places, where new industrial establishments are coming up, they are not allowing them to organize trade unions. That fundamental right is being denied to them. There are instances where the new employers, who are coming up in the field, are mobilizing private armies to see that no trade union activity is organized near the factories. If the workers form an organization, the private armies are told to beat them up; and, if necessary, use fire-arms. They also ensure that the police connives with them.

In the closed factories, the workers are not being given the provident fund amount that is due to them. They are also not being given loans for months together. Employers realize the money that is due from the workers, but they do not remit the Provident Fund amount that is recovered from them. All these things are happening with the connivance of certain officers in the Office of the Provident Fund Commissioner. Otherwise this cannot be done. This is the situation obtaining in the organized sector.

If you look at the unorganized sector, you will find that the situation is much more worse. I do not want to go into details. How can you say that, you will try to improve the condition of the labour and their interests will be safeguarded? Nothing has been said about it. Nobody looks into it. See what is the position of the Labour Ministry. It has itself been downgraded. it is given a Minister of State, not having an independent charge of it. Is there an independent Labour Minister? Who will look after this problem. There is nobody.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): The Prime Minister will look into it.

SHRI J. CHITHARANJAN: How can the Prime Minister look into all these things?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He has been looking at the problems of the whole country.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The CII will look into all the labour problems.

SHRI J. CHITHARANJAN: Well, you are thinking of the development pace of the private sector. You say in the speech itself that they are the most efficient; they will give dynamism of management to the industry. Look at the thousands and thousands of factories. Of course, there are several factories belonging to the public sector which are lying sick, but in the private sector also there are large number of factories, which are lying sick. Such industries are in the hands of the big industrialists, not the smaller ones. Wherever they could make the profit, they run the industry. They make use of the amassed wealth by taking profit out of it and finally throw them out as junk. That is what they have done. Then they put all the responsibility on the workers.

Sir, a new situation is coming up now. If you go through the papers, you will find reports where the CII, the ASSOCHEM, the FICCI, all such organizations from the organized sector are, for the first time in the history of India, coming up with statements which were never made earlier. The President of CII has come forward with a proposal as to who should be the Finance Minister. Sir, it is the prerogative of the Prime Minister to see as to who should be the Finance Minister. The CII says "so and so should be the Finance Minister" and they oblige them. That is what is happening. Then, they come forward with the proposal that these are the policies that are to be implemented. Then, they say that for the first 30 days these things should be done; for the next 60 days, these things should be done.

"For the next 90 days, these are the things to be done. For the next 120 days. These are the things to be done." These are all being dictated. These are all being followed. What a pitiable situation! ..(*Interruptions*).. Not only that; several assurances are being given. I will not go into the details.

Another point I would like to say is about the international relations. It has been said in the Address, "India seeks to further deepen and broaden her relations with the United States of America, on the basis of the values and ideals we both share." Of course, USA is the richest country and the most powerful country in the world. We should have beter relations with them. you think that we share common goals, but you should not forget the relationship between India and the USA in the last 52 years. This morning, one of our hon. Members referred to the liberation of Goa. The same is the case with Kashmir. What was the attitude taken by the USA towards these issues? What was the attitude taken by USA at the time of liberation of Bangladesh? Due to lack of time, I will not go into the details. Even now, what is their ideal? You say that you are for a new world economic order, with equity. What is the stand of the USA? They stand for a uni-polar world.

They stand for a world order in which they dominate. They say that their interests will be predominant. That is what they have said. Are you sharing that idea? If you share those ideals, please say that. I am not against friendly relationship with the USA. But don't say about the common goals. Don't forget the fact that the USA is having its own goals which are not acceptable to India and to the people of India and even to the other developing countries in the world. We should not forget that.

Then, another thing I would like to say is about the Constitutional reforms. On the one side, it has been said, "During the last elections, people have given a verdict against political instability." Now you have complete political stability. Why should you then seriously think of introducing a legislation, ensuring a five-year tenure for the Lok Sabha and Vidhan Sabhas? If you are so sure, why should you think about all these things? ...(*Interruptions*).... It is not a question of perfection of a democratic Constitution. you are making it more and more anti-democratic. Political instability does not depend on the number of Members in Parliament, whether in India or anywhere else in the world. So, some combination should come to power wherein, arithmetically, they may be having majority. If they follow certain anti-people policies, finally, what would happen? The base would be eroded. Naturally, the Government would become unpopular. Then, repercussions would be there at the top also. Therefore, you should not feel very happy about it. When the diesel price was increased, several constituents of the NDA reacted. For example, the Telugu Desam Party, the Indian National Lok dal, even the Akali Dal (Badal Group), have said that this hike was wrong and it should be withdrawn. Finally, one party had said, "For the time being we agree to the hike in the diesel price, but if the Government hikes the prices of kerosene and LPG, then we would oppose it." You are going to face such problems. Therefore, don't be assured of political stability and all that.

Another thing is regarding the Constitution. Suppose Parliament is there, majority of Members think this Government should not continue.

3 P.M.

Then, what is the meaning of this amendment that you are intending to bring in? Your intention is to see that in spite of the fact that the Government had become unpopular, even though a majority of the Members of Lok Sabha are against it, you want to continue in power. Is it democracy? Then you say that the Constitution itself will be amended. I do not know what are the things that are there. Due to lack of time, I do not go into these things. But these are attempts to give up the democratic nature of our Constitution. Please do not meddle with that. Please do not venture to do that. That is all I have to say.

With these words, Madam, I conclude.

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): Madam Deputy Chairperson, we have to take a serious view of the entire situation as it is prevailing in the country. Unfortunately, there are a number of things which have been said.

The first thing I would like to mention is about the role of the Election Commission, knowing fully well that the Election Commission has done a commendable job in spite of the things which, in fact, had been happening. I would like to emphasise one of the aspects of the question and that is about the role of the Government so far as the Election Commission is concerned. For the first time, I have come across such a situation. The Election Commission wanted to play their own role under Article 324. The Government, for reasons best known to them, opposed the Election Commission with regard to the Code of Conduct in the Supreme Court. Knowing fully well that the exit polls showing the trend while there were a number of areas where the election had not been held. The Election Commission was being opposed! At least I have not heard so far about such a thing. The Code of Conduct is, in fact, a conclusion after consultation with all the political parties. I do not know what the compulsions were due to which the Government had to do this, excepting, perhaps, political considerations. They wanted to show that. There was the possibility that if they showed the trend, in the other areas, they would get more seats. I think it is highly objectionable and the Government owes an explanation so far as this conduct of the Government is concerned. Is the Government considering bringing in some kind of a legislation, which in fact is required, to strengthen the powers of the Election Commission?

Madam, the second point which I would hurriedly go through is about the provisions of the Constitution under which, in special circumstances, a Special Session of the Rajya Sabha needs to be called. We had been insisting on the President. A number of political parties had gone to the President, seen him in this regard. In spite of the special provisions under the Constitution, why is it that the Government did not think of calling a Special Session and discussing the issue in which we were very much interested? I do not want to go into the aspect of the President writing to the Prime Minister asking him to call the Session. In spite of that if they had not called the Session, certainly some kind of explanation is expected from the Government.

Madam, it is apt that the Government has referred to the shape of things to come under the new dispensation and the dream of Mahatma Gandhi who said, "I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice,". This is a very apt quotation given in the Presidential Address. Is it merely a routine sort of thing, a kind of ritual, that Mahatma Gandhi's name should be taken without

meaning anything knowing fully well the context in which we are working in this country, are we really taking the poor into confidence while shaping the things in our country, or are we now seeing a situation in which, in the name of economic reforms, in the name of the second phase of economic reforms, all the multinationals are going to take over the entire thing? I know that some hon. Members might refer to the Congress Government starting the whole process. But the whole concept was that you should have imports for export purposes and if there is a new technology, by all means, import the same, make our goods competitive and see that our exports increase. But what is the position now? Even consumer items are being imported in a very big way. The other day, the Finance Minister was pleased to state that for the new foreign direct investments, no regulation is required. Automatically, the whole thing can go ahead. I think a stage has come when the power of the Parliament to insist on a ceiling in respect of borrowings has to be clearly defined. If we have to consider the total borrowings, both domestic and external, I think a stage has come when you have to put a ceiling and tell the Government that beyond this ceiling, the Government have no authority to go ahead. Some kind of a legislation of this nature is definitely called for. That is a point which I would like to make.

The third thing to which the President was pleased to make a reference was about creating a separate Department of Education and the Education Minister was also pleased to state that he wants to make right to education a fundamental right. I don't think anything is going to be achieved by this. Are you really sincere about having primary education, specially in those sectors, which in fact, have suffered a lot? Even now, I don't think any of the teachers is prepared to go to the remotest village and give the kind of education that is required. I have thoroughly gone into all the aspects of the question and I am more than satisfied. If we have to see the rate of drop outs in those areas, it is a frightening thing. Nobody seems to be interested in going to the remotest areas where education is just for the name sake. There is hardly anything of that kind. Something has been done in Rajasthan and some people, who, in fact, are not having exactly the same kind of qualification which is called for, are doing something. If there is an educated person, who can possibly educate them, he is being employed for doing that kind of a job and some kind of progress is being seen. But beyond that, I don't think, any serious effort, for that matter, is being made by the Government in this respect. So, by merely having a separate department for primary education or making it just a fundamental right is nothing. We are paying just a lip-service and nothing more.

Madam, another thing has been referred to in the President's Address about which I am not very clear. I do not know as to what exactly is the idea of the Government in saying so. A Commission comprising noted

constitutional experts and public figures shall be appointed to study half a century's experience of working the Constitution and they say that the Government will also examine replacing the present system of no confidence motion by a system contructive vote of confidence and fixed term for the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas in order to prevent political instability both at the Centre and in the States. Certainly, we are ourselves confused and at least, I have not been able to understand as to what exactly the concept is. Somebody has to explain to us as to how they are going to bring about this kind of a thing. Does it come under the kind of a judgment which was given by the Supreme Court about the basic features of the Constitution? You are not entitled to make any changes in that. Does that affect this kind of a situation? This is a point on which some kind of explanation is definitely called for.

Madam, there is one thing which I would like to understand, and here also, I am equally surprised that the Government is saying things without understanding or without meaning anything. On page 12, it has been stated: "Comprehensive electoral reform is necessary if elections are to be made a truly democratic exercise, free from clutches of muscles and money power" Wonderful. The idea is very good. Are you really serious about it? I don't think that in the situation in which we are having the elections, any poor man can think of contesting any elections, any honest worker can possibly think of contesting the elections and winning the elections. There is hardly any possibility. Even the Assembly elections are costing two crores, three crores. The less said the better would it be about the Parliamentary elections. I have seen those who are saying this, they themselves know what has been their role. We have seen what they have been doing. So, let us not unnecessarily say things about which we ourselves are not very sincere. I don't think that you are going to do anything of this nature. Muscle and money power is on the increase and you will see that no sincere person is allowed to contest the elections much less to win the seat. So, this is the situation in which we are today.

There are two things to which I have to make a very quick reference. That is about the question which I had raised on the floor of the House and that was regarding the import of sugar, wheat and oil. I had pleaded—Mr. Barnala was the Minister in charge—with him that you had to impose an excise duty on them and to have a level-playing field. Knowing fully well that those people are paying a huge amount of subsidy, and this was the special condition where invoking the provisions of the Anti-dumping Act should have been resorted to. I was told—I don't know how far it is true—that he has himself conceded it. It is on record that he conceded this thing, that what I was saying is correct; we would have to impose a minimum 60 per cent excise duty and also to resort to anti-dumping measures. What had

happened? The Cabinet turned down that proposal! see what had happened. Why did you do that? The Government definitely owes some kind of an explanation. Were they sure that sugar was not available in sufficient quantities in the country for public distribution? If they were to refer to the Department concerned, everybody was convinced that were was enough sugar available. But sugar had to be imported because they wanted to please Nawaz Sharief! from his area, from his sugar factories, this sugar was being exported! I don't know how far it is true. It is alleged that this money was being utilized by ISI for purchasing the latest equipments and those equipments were meant for using against India. So, this was the role you had played. Certainly, we would like to have an explanation from the Government as to why it had happened, despite knowing fully well that there was enough stock of sugar, enough stock of wheat, enough stock of oil available in the country, and still you wanted to import those things, merely to please certain friends of yours, and against the interests of the cultivators and also the people at large. Why you had done this is a matter fact, is a matter of serious concern for every one of us, and this is why I request the Government that while replying they should be in a position to say as to why they had to do that.

Madam, another point to which I would just make a reference is about the infrastructural development. The Government was pleased to say that they are going to allocate special amount of money from the Central Government for completing some of the irrigation projects, which are in an advanced stage of construction. I was told, that they are going to help the State Government if they can be completed within two years, and it is the responsibility of the State Governments to see that those projects, which can be completed in two years, are completed. They should be in a position to do so. The only difficulty is that they are financially not sound enough, they don't have the money. If the Central Government had helped them, they would have been able to do that. What has been done and in how many States they have been able to take this job seriously is a point which I would like to understand.

Secondly, I would refer to the generation of power which is another very important aspect of the infrastructural development and I would like to know, knowing well the position of the State Electricity Boards, whether they are going to bring about this kind of a thing; unless electricity becomes available, the talk of seven or eight per cent rate of growth will be all tall talk.

I don't think anything of this nature is going to materialize. We are interested in finding out what efforts are going to be made to see that specially these two things come out in such a way that we are able to create the necessary atmosphere for investment in this country where plenty of electricity is available. All other things like irrigation are also to be made

available so that agro-industries are also able to develop in a big way. But, I doubt whether the Government is in a position to do all this. That is why I thought it necessary that they should be able to tell us what exactly they think about this matter. Madam, I have completed my points. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, Mr. O.S. Manian.

*SHRI O.S. MANIAN (Tamil Nadu): Madam, Vice-Chairman, as I rise to speak on the Motion of thanks on the President's Address, I wish to make one thing clear at the outset. Since the Address of the President spells out only the policies and programmes of the Government, I have my reservations on several issues referred to in the Address.

Madam, first of all, on behalf my AIADMK party, my revered leader and on my behalf, I salute the martyrs who have laid down their lives in Kargil operations, I also salute the brave soldiers of our Armed Forces, who, unmindful of the danger to their lives, fought the enemies heroically. But I feel, this conflict could have been avoided, had the centre been receptive to valuable information. In October 1998, my respected leader Dr. Puratchi Thalaivi had cautioned the Centre about an imminent intrusion by Pakistan. This was conveyed by my leader in the Coordination Committee of the erstwhile coalition, and also while addressing the press. But the then Home Minister and the Defence Minister, who continue to hold the same portfolios even now, did not pay any heed. Had the Government taken the advice of my leader seriously, the Kargil operation could have been avoided.

Madam, the President's Address promises to sanctify reservation in States that have more than 50% reservation, through legislation. Here I wish to mention one thing. On 9th November 1993, my revered leader, Dr. Puratchi Thalaivi as the Chief Minister of Tamilnadu, got a resolution passed unanimously in the Assembly urging the centre to protect 69% reservation in the State. Later, with a firm resolve to protect reservation to SCs, STs and backward classes, my leader got the Tamilnadu Reservation Bill passed by the Assembly and also prevailed upon the centre to incorporate it in the Ninth Schedule to the Constitution, through an Act of Parliament. Yet even, the judiciary is standing in the way of reservation. So, I urge upon the centre to effect Constitutional amendment to protect 69% reservation in Tamilnadu.

AIADMK has been insisting for long on 33% reservation for women in Parliament and State legislatures. The Government has promised to do that. It should not remain on papers. Necessary legislation should be brought as soon as possible. Madam, there is only a reference to inter-State water dispute. The Prime Minister and the Chief Ministers of Tamilnadu and Karnataka, held a meeting after which they declared that the Cauvery water dispute had been resolved. I do not want to go into the details of the issue.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

But the fact remains that, when crops in the Cauvery delta districts of Thanjavur Nagappattinam and Thiruvarur were drying up, Karnataka refused to release a drop of water. As one coming from the affected Cauvery delta, I would like to submit that it is the duty of the centre to protect the rights of a State from the whimsical attitude of another State. I am hopeful the Government will take serious note of this.

Reference has been made to creation of three new States and also about giving full Statehood to Delhi. But surprisingly, there is no reference to giving statehood to Pondicherry. The Home Minister had assured the Twelfth Lok Sabha of giving statehood to Pondicherry. I do not know what happened to that assurance. I urge upon the Centre to take steps to grant statehood to Pondicherry without delay.

Madam, AIADMK has been demanding for the declaration of Tamil and 17 other Indian languages in the Eighth Schedule to the Constitution as Official Languages. My leader Dr. Puratchi Thalaivi had prevailed upon the previous BJP-led Government to include an assurance to this effect in the Address of the President last year. But there is no reference in this Address regarding giving of Official Language status to all the 18 languages in the Eighth Schedule. There are political parties from Tamilnadu which are part of the coalition. There are Central Ministers belonging to such parties. Yet they have failed to notice this omission. I demand that the centre should take steps to declare these 18 languages as official languages of the Union.

Madam, Tamilnadu has been demanding for increasing the storage capacity of Periar dam from 136 feet to 152 feet. Since it is on the state border, Kerala has been refusing to do so. I appeal to the centre to intervene and permit storage of water to 152 feet.

The Sethusamuthiram project, which has been hanging fire for several decades, has not been referred to in the Address. The Government should initiate measures to execute the project. The Address refers to creating one crore additional employment opportunities every year. I wish this is translated into action. This Government has been talking about protecting minorities. But what is happening in the country? I feel it my duty to share an information with the House. At Krishnambudhur in Kanniyakumari district of Tamilnadu, a church was set on fire. Certain people are objecting to the reconstruction of Church at the site. They are also indulging in road-blockade in protest.

SHRI VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): It is factually false. (*Interruption*)....

*SHRI O.S. MANIAN: Madam, I assertively say that this kind of assault on minorities are going on.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

There is reference to land reforms in the Address. (*Interruption*)

Madam the then Chief Minister of Tamilnadu, Dr. M.G.R. got the Land Reforms Bill passed unanimously in the Assembly, and had sent it to the Central Government for approval by Parliament. Later, my respected leader Dr. Puratchi Thalaivi had also sent it for approval. But it has not been approved so far. I hope this Government will get the approval at the earliest and help enforce land reforms in Tamilnadu.

The Price of diesel has been hiked. The price was reduced by one rupee before the elections, but it was hiked by four rupees after the election. Diesel price was reduced before elections for the sake of votes. It was again increased after the election.

People should not be taken for a ride this way. Because of this hike, truck operators are on strike all over the country. Industrial and agricultural goods could not be transported. The situation is indeed serious. The Government should not stand on false prestige. It should be resolved soon.

While speaking on this Motion a little while ago, hon'ble Member Shri Viduthalai Virumbi, and a very senior Member Shri S.B. Chavan mentioned that the elections were held peacefully. They also admitted the fact that only those who have money power could contest election. There is no use of working hard for thirty days while compaigning for election. Because, on the day of polling, bogus votes are cast. This flagrant violation of electoral norms should be checked through electoral reforms.

Madam, Vice-Chairman, there is a Member of Lok Sabha, who has been elected from Tamilnadu. He is also a Union Minister. There have been reports that he has coast bogus vote. (*Interruption*)

This matter has been taken up by T M C and also the Communist party. (*Interruption*)

**[The Vice-Chairman (Shri Md. Salim)** *in the chair*]

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I am on a point of order. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Your leader is speaking. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I am on a point of order.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, he is casting aspersions on a Member who belongs to the other House. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: He is a Minister. (*Interruptions*).

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He must substantiate his allegations or withdraw his words. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: My point of order is this. The hon. Member is referring to a very serious charge made against a person who may be a Member of the other House. But he is a Minister. He was sworn in as a Minister in the Council of Ministers. He himself has accepted it. There is no question of substantiating because he himself has accepted that his name was not on the electoral roll of a particular area, but he voted over there. The Election Commission has ordered action against the Returning Officer who permitted him to vote. This is a serious electoral misconduct. (*Interruptions*).

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, what she is mentioning is totally irrelevant. (*Interruptions*). He must substantiate the allegation or withdraw his words. (*Interruptions*). It must be removed from the records. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): If all of you speak simultaneously, I will not be able to follow anything. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, the problem is what the hon. Member referred to is what I am talking about. Unfortunately, my colleagues, the DMK Members, are concerned about the other Minister. We are not referring to that. We are referring to Shri Ponnusawamy... (*Interruptions*). We are not talking about that Minister. We are talking about somebody else. (*Interruptions*).

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I have not mentioned the name of any Minister (*Interruptions*). What I have said, is nobody can cast aspersions on a Member of the other House. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, where is the question of casting aspersions? He is a Minister. We are entitled to raise it in both the Houses. He has accepted it. Where is the question of substantiating? (*Interruptions*).

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: How can you say that he has accepted it? (*Interruptions*). It is hearsay. (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: He has accepted it. (*Interruptions*).

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: On what basis are you saying it? (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, he does not know the name of the Minister. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): What is happening outside the House, we are not concerned with that. Mr. Manian, if you want to make any charges or allegations, you give in writing to the Chair and then you raise it. But now you have to conclude. You have already consumed your time.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, please ask Shri Gautam if he knows the Minister's name. He is defending him even without knowing his name.

*SHRI O.S. MANIAN: Sir, the polling Officer, who permitted him to vote has been suspended. If the one who permitted such voting has been suspended, than what should happen to the person who had cast his vote. He should resign. If he does not resign, the Prime Minister should drop him from the Council of Ministers. With these words I conclude.

**श्री गोविन्दराम मिरी:** उपसभाध्यक्ष महोदय, संसद के समक्ष भारत के महामहिम राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं तथा उन्हें धन्यवाद अर्पित करता हूं। मुझे कहते हुए यह गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने कारगिल के युद्ध के समय जो विजय प्राप्त की और हमारे बहादुर जवानों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी उसके लिए देश कृतज्ञ है और मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि शहीदों के शवों को सम्मानपूर्वक उनके गृह नगरों में लाकर के उनके अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई की गई वह एक अनूठी है और इससे पूरे देश में देशभक्ति का जो जज्बा शुरू हुआ वह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। हमारी सरकार ने हमारे सैनिक पूर्ण साधन सम्पन्न हों इस बात की चिंता की है जिसका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है।

मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं शुरू में 1994 में आया था तो इसी सदन में तारांकित प्रश्न क्रमांक 425 से मैंने तत्कालीन गृह मंत्री श्री चव्हाण जी बैठे हैं, उनसे पूछा था कि आप छत्तीसगढ़ राज्य कब बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है और अभी आवश्यकता नहीं है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस बी०जे०पी० की सरकार ने पिछले समय भी छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात की थी, घोषणा पत्र में उल्लेख हुआ था और अभी भी इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है जिसका उल्लेख इस अभिभाषण में हुआ है। यह महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा भाग है और उसका एक तिहाई भाग छत्तीसगढ़ में आता है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है — वन सम्पदा और खनिज से भरा हुआ है और उसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में आता है। आज जब वहां के लोग सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, पूर्व सत्र में भी यह विधेयक पेश किया गया था तो इससे वे खुश हो रहे हैं और इस सरकार के प्रति धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस छत्तीसगढ़ राज्य में तीन सम्भाग हैं — बस्तर सम्भाग, बिलासपुर सम्भाग और रायपुर सम्भाग। पिछले बिल में इस बात का उल्लेख नहीं हो पाया था तथा यह कहा गया था कि हाई कोर्ट और विद्युत मंडल के कार्यालय जो पूर्व में हैं उनके मुख्यालय वहीं रहेंगे। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि यह विधेयक जो लाएंगे उसमें इस बात का उल्लेख हो कि राजधानी के साथ ही हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है और विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है उसको छत्तीसगढ़ को दिया जाए,

*English Translation of the original speech delivered in Tamil.

यह मेरा विनम्र आग्रह है। मुख्यालय खोलते समय चाहे राजधानी की बात हो या हाई कोर्ट खोलने की बात हो या फिर विद्युत मंडल के मुख्यालय खोलने की बात हो उसमें बिलासपुर की उपेक्षा न की जाए। क्योंकि अधिकांश लोगों को यह भ्रम है कि छत्तीसगढ़ का मतलब रायपुर होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रायपुर ही नहीं अपितु बिलासपुर भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी अनदेखी न की जाए, उनके अधिकारों की अनदेखी न की जाए।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने समाज से छुआछूत के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रतिबद्धता दिखाई है और इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और दस वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा और कुछ राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे पचास प्रतिशत से ऊपर के आरक्षण को विधायी उपायों द्वारा मान्यता दिलाई जाएगी। मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि जहां एक ओर राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, उसको विधायी उपायों द्वारा मान्यता दिलाने की बात आपने कही है वहीं दूसरी ओर मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जाति के लिए पंद्रह प्रतिशत और जनजाति के लिए साढ़े सात प्रतिशत, इसको भी आगे बढ़ाएं। इसमें कोई छोड़छाड़ न की जाए, इसको भी विधायी उपायों द्वारा मान्यता दिलाई जाए, ऐसा मेरा आग्रह है।

एक तरफ हम कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसमें अनुच्छेद 16 बहुत महत्वपूर्ण है, 16(4)(अ)। इसके साथ भी छेड़छाड़ कुछ दिनों से की जा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि कुछ ऐसे निर्णय हो रहे हैं जिसमें हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र-छात्राएं हैं, उनके आरक्षण पर रोक लगाने का फैसला हुआ है कि इसके जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं, उनको समाप्त किया जाए, ऐसी चर्चा चल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी सीनियारिटी को भी प्रभावित करने वाली जो बातें की जा रही हैं, वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एक ओर जहां हमें संविधान के मुताबिक जो आरक्षण किया गया है, वह पूरा नहीं हुआ है, उसमें कमी करने की जो बात की जा रही है, यदि ऐसा है तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज तक लोकतंत्र का जो चौथा स्तम्भ है पी०आई०बी० जिसमें सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची रहती है, उसमें एक भी दलित पत्रकार नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा स्थान कहां है? हमें अपना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है और वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्तरों पर इस आरक्षण की सुविधा को समाप्त करने के लिए एक अभियान चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं विनम्रतापूर्वक अपनी मांग को रखता हूं कि इसके लिए यह आवश्यक है कि आरक्षण से संबंधित जितने भी नियम हैं, आदेश हैं, कानून हैं, इनको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाली सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण विरोधी जो भी मेमोरेंडम जारी किए हैं पांच-सात, उन्हें समाप्त करने के लिए कार्यवाही की जाए। इसी तरह से आरक्षण जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, आरक्षण नीति लागू करने के लिए एक व्यापक कानून बनाकर विधेयक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आयोग

है, उस आयोग को भी वही दर्जा और वही सुविधा मिले जो इलेक्शन कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिली हुई है। जो अधिकार और शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं, जो स्टाफ उनको मिला है, वह भी उसको दिया जाना चाहिए और आरक्षण से संबंधित कोई भी आदेश जारी करने के पहले आयोग से सलाह-मशवरा किया जाए। मेडीकल, इंजीनियरिंग कालेजों में जो सुविधाएं अभी मिल रही हैं, उन सुविधाओं को बरकरार रखा जाए क्योंकि आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को लागू किया जाए। इसी तरह से इसमें एक संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाने की बात कही गई है। मेरा सरकार से आग्रह है, मेरा निवेदन है कि यह जो कमीशन बने इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

महोदय, हमारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति का समाज है इसके हितों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए तभी हमें ऐसा महसूस होगा कि इस वर्ग के लोग भी आगे बढ़ पाएंगे और इनको भी समानता का अधिकार मिला है।

**श्री सतीश प्रधान** (महाराष्ट्र): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जो 48 पैराग्राफ हैं, उनमें मुझे कुछ पैराग्राफ बहुत अच्छे लगे हैं, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिन पर मुझे गर्व है, अभिमान है और जिनकी आवश्यकता थी। सबसे पहले लोक सभा या विधान सभा की मुद्दत पांच वर्ष रखी जाए इसके लिए कानून लाने के बारे में सोचा गया है। साथ-साथ मतदान केन्द्र के पुनर्रचना का भी प्रस्ताव है। मैं थाणे क्षेत्र से आता हूं वह हिन्दुस्तान का दो नम्बर का चुनाव क्षेत्र है। वहां पर 29-30 लाख से ऊपर मतदाता सूची में दर्ज हैं। एक तरफ यह क्षेत्र है और दूसरी तरफ करीबन एक लाख से थोड़ा आगे-पीछे मतदाता की संख्या वाले चुनाव क्षेत्र हैं। इसके लिए कुछ व्यवस्था होने की आवश्यकता है। जहां पर क्षेत्र कम है वहां पर कुछ स्पेशल कंसीडेशन पर विचार अवश्य होना चाहिए। इतने बड़े मतदान केन्द्र का विभाजन होना भी जरूरी है और वह जल्द से जल्द होना चाहिए।

साथ ही इसमें राज्यों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बहाल करने के बारे में कहा गया है। मुझे ज्ञान है, मैं नगर पालिका से आया हूं और नगर निगम से आते समय मैंने देखा है कि केवल एक खेल चलता है, कभी अधिकार बढ़ाकर दे दिए जाते हैं और कभी कोई उन अधिकारों को कम करने की सोचता है। जब बाकी के राजनीति करने वाले लोगों को लगता है कि इनके अधिकार ज्यादा हो गए हैं, ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और फिर अपना क्या होगा, इसके बाद फिर अधिकार कम कर देते हैं।

हमारे यहां महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि नगर निगम के अध्यक्ष को एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्जीक्यूटिव और फाइनेंसियल सभी अधिकार बहाल किए गए। नगर पालिका के अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव हुआ था, जैसे विधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव होता है, वैसे ही पूरे शहर के लोगों ने उनको चुना था। लेकिन काम का तरीका देखने के बाद तुरन्त सब विधायक लोगों ने चिल्लाना शुरू किया और अधिकार कम करने की मांग कर दी। जिन्होंने अधिकार दिए थे उन्होंने ही पांच साल के अन्दर अधिकार वापस ले लिए। मैं सरकार से आज प्रार्थना करता हूं कि अगर आप पंचायत स्तर तक अधिकार बहाल करना चाहते हो, आप वह अधिकार अवश्य दीजिए, मगर वह अधिकार चन्द दिनों के बाद विदड्रा मत कीजिए। यही मेरा कहना है। महोदय, मैंने इस अभिभाषण में यह भी देखा है कि हमारे संबंध अमेरीका के साथ बहुत

अच्छे हैं। तथा ये संबंध और भी सुधर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और अपने विदेश मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक जब भी दुनिया के सामने हमारा कोई भी महत्वपूर्ण सवाल उठा है भले ही वह काश्मीर का हो या कोई और हो हर समय हमें बहुत अच्छा साथ मिला है रशिया का। रशिया ने हमारा साथ दिया तो हम रशिया को न भूले। उसको भी साथ में ले और आगे बढ़े।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि देहातों में खासकर रोजगार नीति का प्रयोग कर रहे हैं। हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि देहातों की तरफ ध्यान देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि देहातों में जो फसल होती हैं जैसे तरकारी, भाजी, वेजीटेबल्स और फ्रूट्स आदि उनके प्रोसेसिंग होने का वहीं पर बन्दोबस्त या इंतजाम करना चाहिए। इसके बाद ही वह बाजार और दिल्ली जैसे मैट्रो सिटी में आए। इससे वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और उनका शहरों की तरफ दौड़ना भी बन्द होगा। यह प्रयोग जापान में हुआ है। वहां पर मैंने देखा है कि लोग शहरों की तरफ नहीं दौड़ते हैं बल्कि वापस देहातों की तरफ जाने लगे हैं। यहां पर भी इस प्रयोग की जरूरत है इसलिए इसको कीजिए।

मैं एक और बात कहना चाहता हं कि सत्र के दौरान और भी बजट्स आए हैं मैंने उनको देखा है और अनुभव किया है। यहां पर फायर के, जायदाद प्रोपर्टीज के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हर साल करोड़ों रुपयों की जायदाद नष्ट हो जाती है। कई लोग आग में जल जाते हैं, खेतों का नुकसान होता है और फसलों का भी नुकसान होता है। इसके लिए हमारे यहां कोई नेशनल प्रोग्राम नहीं बना है। इसलिए इससे विषय पर कुछ करने की आवश्यकता है और सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सरकार का गठन करते समय प्रधान मंत्री ने एक और अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं क्रीड़ा क्षेत्र से आता हूं। प्रधान मंत्री जी ने क्रीड़ा मंत्री को केबिनेट का स्टेट्स दिया है जो कि एक अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कि इससे खेल जगत में और उन्नति होगी और हमें स्वर्ण पदक हांसिल करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा।

आपने लोकपाल बिल का जिक्र किया है और प्रधान मंत्री जी को भी उसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों को जरूरत है। हम यहां हर विषय पर हर समय चर्चा करते हैं और अनुभव करते हैं कि कभी भी यहां चर्चा नहीं करते हैं कि मसल पावर क्या है। कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है लेकिन मसल पावर का निर्णय एक्जिक्यूटिव होता है। दूसरे क्षेत्रों में उसका प्रयोग हुआ है। यहां भी इसका थोड़ा प्रयोग हुआ है इस विषय में। कारगिल के जवानों का गौरव बढ़ा है। यह भी अभिमान की बात है। हमने हर समय अपने जवानों का गौरव बढ़ाया है। जवानों का गौरव उसी समय होने के बाद हम जवानों को भूल जाते हैं। यह भूल जाना बन्द करना चाहिए और उनकी जो भी समस्या हो उसे कार्यस्वरूप दुरूस्त करने के लिए, सुविधा प्राप्त कराने के लिए हमें कुछ न कुछ करना है। जिस दिन जवान लड़ाई करता है तब तो याद रखते हैं, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद जवान कहां गया या हुतात्मा हो गया उसके रिलेटिवज कहां गए, क्या कर रहे हैं, उनको कागजों में जमीन देते हैं और आगे कुछ नहीं होता। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, इसको हमें करना पड़ेगा।

आपने और एक अच्छी बात की कि चुनाव में बाहुबल का, धनबल का प्रयोग नहीं होने दिया और चुनाव सुधार करने का आपने प्रस्ताव रखा, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके लिए धन्यवाद देते समय मैं यह बताऊंगा....**(समय की घंटी)** बस एक मिनट।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** आपको आठ मिनट का समय दिया था, नौ मिनट हो गये हैं, फिर दस मिनट हो जाएंगे।

**श्री सतीश प्रधान:** चुनाव में सुधार करने की आप जब सोच रहे हैं तो चुनाव में सुधार करते समय यह भी सोचने की आवश्यकता है कि धनबल, बाहुबल का प्रयोग न हो। उसके साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार चलता है उसको भी रोकने की आवश्यकता है तथा आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह भी देखने की आवश्यकता है वरना जिसके हाथ में डण्डा है वह सब कुछ कर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह देखने की आवश्यकता है। अभी जो चुनाव हुआ, 13वीं लोक सभा का जो गठन हुआ तथा साथ ही कुछ जगह विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ, उसमें एक मुद्दा उठाया गया था तथा एन०डी०ए० के प्रोग्राम में भी वह मुद्दा उठा था कि देश का प्रधान मंत्री कौन बने, देश का राष्ट्रपति कौन बने। वह देशी बने या विदेशी बनें। विदेशी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस विषय पर चर्चा हुई और इस मुद्दे को लेकर लोगों को चुनाव करने के लिए प्रभावित किया गया। मुझे आशा है कि इस विषय पर आप जब चुनाव सुधार की बात करेंगे तो इस विषय पर दूसरा मुद्दा छेड़ा जाएगा, दूसरी बात की जाएगी, लेकिन यह मुद्दा इसमें नहीं आया और इस विषय पर भी सरकार को जो कुछ उसके हाथ में है उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। एक आखिरी बात यह है कि सभी विषयों पर चर्चा होते समय उत्तरांचल की बात की, वनांचल की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, आपने इन सभी को श्रेष्ठ राज्य बनाने, का आश्वासन दिया है, वचन दिया है मैं उसके लिए आपको शुभकामना देते हुए कहूंगा कि हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद भी उतना ही पुराना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो पुराना विवाद चल रहा है, बेलगांव और धारवाड़ के एरिये में जो मराठावासी रहते हैं उन पर अत्याचार होता है।

**श्री एच० हनुमनतप्पा** (कर्णाटक): यह बात यहां उठा रहे हैं, इस विषय पर चुनाव में ....**(व्यवधान)** आपको जो कहना है बाहर आकर चुनाव में उठाएं....**(व्यवधान)**

**श्री सतीश प्रधान:** आपको जो कहना है....**(व्यवधान)** जो कहना है कि....**(व्यवधान)**

**श्री एच० हनुमनतप्पा:** आपने महाराष्ट्र के बारे में मुद्दा उठाया है, वहां जाकर देख लीजिए....(व्यवधान)

**श्री सतीश प्रधान:** मैं देख लूंगा आप उसकी चिंता न कीजिए, आप अपना काम देखिए, इसीलिए हम 15 सांसद चुनकर लाए हैं।

**श्री एच० हनुमनतप्पा:** उधर भी देखो उधर क्या हुआ। नीचे भी देखना है, ऊपर भी देखना है।

**श्री सतीश प्रधान:** कल तक आप लोग एक-दूसरे को गाली-गलौच कर रहे थे अब गले मिल रहे हैं।

**श्री एच० हनुमनतप्पा:** हमने गला नहीं मिलाया है, उनके साथ, आप लोगों ने कहा है....**(व्यवधान)**

**श्री सतीश प्रधान:** यह विवाद बहुत पुराना है, सालों से चल रहा है। वहां मराठावासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां अभी तक जितने भी चुनाव हुए बेलगांव में, धारवाड़ एरिये में, वहां सभी चुनाव लोकतंत्र के अनुसार महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने जीते और इसलिए इस विषय का भी निर्णय जल्द से जल्द सरकार को करने की आवश्यकता है। यही मेरा मुद्दा है और यह मैं सरकार से आह्वान करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विषय पर आप जल्द से जल्द निर्णय करें। धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** श्री बलविन्दर सिंह।

**सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर** (पंजाब): राष्ट्रपति जी ने जोइंट पार्लियामट्री सेशन में जो अभिभाषण दिया है उसमें बहुत अच्छी बात कही है। जैसा कि 36वां पैरा है, टाइम की कमी होने के कारण मैं नहीं कह सकूंगा लेकिन होना ऐसा चाहिए कि हर पार्टी को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है उसकी मजबूरी है इसलिए मैं सब कुछ नहीं बोल सकूंगा। लेकिन एक सिस्टम है, उसकी अपनी मजबूरी है, इसलिए मैं अपनी सब बात यहां पर नहीं बोल सकूंगा। लेकिन एक प्वाइंट जो कंट्री के लिए बहुत अच्छा है और पहली दफा इसको प्रेसीडेंड एड्रेस में लाया गया है, फर्स्ट टाइम यह बात आई है कि फैडरजिल्म पर बहुत जोर दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकाली दल की तरफ से जब हमने 1973 में पहली दफा आनन्दपुर रेजोल्यूशन पास किया गया था तो उस समय देश में कुछ लोगों ने बड़ा शोर शराबा किया था कि यह लोग सेकशेसन, की बात करते हैं। लेकिन यह बात जो सरकारिया कमीशन बना था उसने भी कही थी और आज जो हिन्दुस्तान में मेजर पोलिटिकल पार्टियां हैं वे भी यही बात करने लगी हैं। आज जो रीजनल पार्टिया हैं वे इस बात पर जोर देने लगी हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश को सही मायनों में तरक्की करनी है तो देश में फैडरल सिस्टम लागू होना चाहिए। इसलिए मैं जहां पर पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि यह जो बात यहां लाई गई है वह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जिसका इसमें वायदा किया गया है कि जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है उस पर गौर करने की कोशिश की जाएगी और फोर्स से उसका इम्पलीमेंटेशन किया जाएगा। अभी तक यह रिपोर्ट दबी पड़ी थी। लेकिन अब इस पर चर्चा हुई है। मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इस विषय को उठाया है। राष्ट्रपति तमाम पार्टियों के लोगों के साथ बात करने लगे हैं। उन पार्टियों को भी अपने शब्द वापस लेने चाहिए जो कहते थे कि यह गलत है, आनन्द साहब रेजोल्यूशन गलत है। हमने उसमें जो बातें कही थी उनको मैं दुबारा जोर देकर रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि Those parts should remain with the Centre. They are: Defence, currency, communication and foreign policy. इन चार के बाद जो विषय हैं वे सब स्टेटों के पास होने चाहिए। अगर इस कंट्री ने सही तरक्की करनी है तो इसके लिए फैडरल सिस्टम जो है उसको सही मायनों में हमें लागू करना होगा और अभी तक दिल्ली की सरकार जो स्टेट की सरकारों को चलाती हैं, रिमोट कंट्रोल से, अगर ऐसा नहीं होगा तभी देश तरक्की करेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं और राष्ट्रपति जी ने जो अपने एड्रेस में माना है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वे बड़े जोर से आगे आई हैं और देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बी०जे०पी० जो पार्टी है मैं उसका धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने यह माना है कि देश की तरक्की में रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो मेन अपोजीशन पार्टी है मैं उससे भी यह कहना चाहता हूं कि अब आप भी अपनी पालिसी क्लियर करें कि क्या आप फैडरल सिस्टम चाहते और क्या आप चाहते हैं कि यह सही मायनों में लागू हो। संविधान बनाते समय हमने जिस फैडरल सिस्टम की बात कही थी वह

आहिस्ता आहिस्ता यूनिटेरी सिस्टम में बदल गया है जो कि देश के लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मेन अपोजीशन पार्टी है उसको भी अपना प्वांइट क्लियर करना चाहिए कि क्या वह फैडरल सिस्टम के पक्ष में है? और जो रीजनल पार्टीज का ग्रोथ हो रहा है उसको वह टालरेट करती है या नहीं, इस प्वांइट को उन्हें क्लियर करना चाहिए। अभी तक कंट्री के सामने जो सही सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम जो होना चाहिए था वह अभी तक नहीं आया है और रीजनल पार्टियां, स्टेट सिस्टम हावी होता जा रहा है और जिस प्रकार से स्टेट की एसपरेशंस बढ़ी है उसको देखते हुए इसे माना जाना चाहिए। सेकेंड, मैं कहना चाहता हूं कि प्रेसीडेंट एड्रेस में एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। मैं उनका धन्यवादी हूं जो एग्रीकल्चर पालिसी में इसमें सुधार करने के बारे में बातें कही गई हैं। अगर कंट्री को इम्पलाइमेंट की दिशा में आगे बढ़ना है और देश का सही डेवलपमेंट करना है तो हमें एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि एक समय था जब जय जवान, जय किसान का नारा इस देश ने दिया था। यह क्यों दिया था क्योंकि देश बड़ी मुश्किल में था और कभी अमेरिका, भी रशिया के सामने कणक के लिए, तो कभी चावलों के लिए कभी किसी चीज के लिए हाथ पसारता था। लेकिन पंजाब के किसान आगे आए और पंजाब ने देश में जो अनाज की कमी थी उस कमी को सरप्लस में बदल दिया और इसके कारण आज हमारा देश फूडग्रेन के मामले में, हम कह सकते है कि सरप्लस है। जय जवान, जब कारगिल इश्यू पर हमारे जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए, हथियारों की भी कमी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सिर हथेली पर रखकर देश की एक इंच धरती के उस पार नहीं जाने देंगे और इसलिए हम सब पार्टीज के लोगों ने सारे देश के लोगों ने उनको सलूट करते हुए उनको सम्मान दिया और स्टेट सरकारों ने भी कि उनकी फेमिली के लोगों को रोजगार दिया इसके लिए यत्न किया। लेकिन जो जय जवान की बात है, वह मैं नहीं मानता क्योंकि किसान तो मुश्किल में पड़ गया है। जो देश को अनाज देने वाला किसान है, उसके बारे में इकोनोमिक सर्वे आफ इण्डिया की रिपोर्ट यह बताती है कि पंजाब का किसान 5700 करोड़ रुपये का कर्जाई हो गया है। पंजाब का किसान किस लिए कर्जाई हो गया है? उसने देश के लिए अनाज दिया है। लेकिन अनाज का रेट प्राइस इंडेक्स के साथ नहीं चला। यह तो देखा गया कि गरीब को अनाज सस्ता मिले लेकिन प्रोड्यूसर का बिलकुल ख्याल नहीं रखा गया। इसलिए किसान कर्जाई हो गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि पंजाब का किसान देश के लिए कर्जाई हुआ, देश के लिए उसने अपना नुक्सान किया है। पंजाब के किसान ने अनपी जायदाद खत्म कर ली। पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी, लुधियाना की रिपोर्ट यह बताती है कि पंजाब की जो लैंड है वह डिप्लीट हो रही है, उसके जो प्रोडक्शन वाले तत्व हैं, वह खत्म हो रहे हैं। उन तत्वों को फिर से ठीक करने के लिए वाटर रिसोर्सेज़ खत्म हो रहे हैं। पेस्टीसाइड वगैरह के कारण पंजाब का जो सब से ज्यादा अच्छा इनवायर्नमेंट था, सब से अच्छा वातावरण था, वह भी खत्म हो रहा है। इसलिए हम यह कहेंगे कहीं कोयला पैदा होता है, कहीं आयल पैदा होता है या दूसरी जो भी चीज़ पैदा होती है, उसके लिए उस स्टेट को रायल्टी दी जाती है लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाबी किसान को रायल्टी देने के बजाय कर्ज के जाल में फंसा दिया गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को सोचना चाहिये और सभी पार्टीज़ को भी सोचना चाहिये। आज देश की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, पंजाबी जवान की, पंजाबी किसान की देश को फिर से जरुरत पड़ेगी। कहीं ऐसा न हो कि देश फिर से मुश्किल में फंस जाए और अनाज शायद मांगे

से भी न मिले। इसलिए हमें किसान को उत्साहित करना चाहिये और उसको कर्ज के जाल से निकालना चाहिये, उसकी हेल्प करनी चाहिये। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो डीज़ल का प्राइस बढ़ाया गया है, मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा। डीज़ल प्राइस जो बढ़ाया गया है, मैं उसके बारे में यह कह सकता हूं कि इसकी सब से ज्यादा मार, सब से ज्यादा बोझ पंजाबी किसान पर पड़ेगा। आप यह कहेंगे कि यह कैसा, भारत के बाकी हिस्से के किसान कहां गये? बात यह है कि पूरे हिन्दूस्तान में जितने ट्रेक्टर हैं, उनका एक चौथाई पंजाब में हैं। पंजाब में 9 लाख टयूबवेल इरेगेशन के लिए हैं। इसके इलावा देश में जितने ट्रक हैं उसके प्रोपोर्शनेटली पंजाब में ट्रक बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब का किसान पूरे देश में जितनी डीज़ल की खपत होती है, उसकी 30 प्रतिशत खपत पंजाब में करता है। इसलिए जो सेस या टेक्स डीज़ल पर लगाया गया है उसमें से 50 प्रतिशत हिस्सा रूरल डवलपमेंट के लिए जो दिया जाता है। पहले तो मैं जो टेक्स लगाया गया है, अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इसका विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया है, इसका कीमतों पर असर पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पहले यह कहा कि बीस साल में सब से कम इनफ्लेशन रहा है, प्राइसेज़ डाऊन आई हैं लेकिन अब वह अप टर्न में जा रही हैं। इस तरह से यह एक सर्कल बन जाएगा, चेन बन जाएगी और फिर से मंहगाई बढ़ेगी। इसलिए कंज्यूमर और प्रोडयूसर पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। ट्रेडर को तो कोई नुक्सान नहीं होगा, वह तो अगले से निकाल लेता है। इसलिए जो यह डीज़ल का प्राइस बढ़ाया गया है, इस पर फिर से गौर करना चाहिये। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं. . . **(समय की घंटी)** कुछ हमारा टाइम है और कुछ हमारे साथियों का टाइम है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** साथियों के टाइम का ऐसे सदन में बंटवारा नहीं होता है।

**सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर:** वह कह रहे हैं कि आप बोल लें।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** वह मंत्रिमंडल के विस्तार में होता है, समय में नहीं होता।

**सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर:** दो चार मिनट मुझे दे दीजिये। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये, मैं जल्दी से कह लेता हूं। डीज़ल पर जो सेस है जिसको रूरल डवलपमेंट के लिए दिया जाना है, मैं आपके ज़रिये यह कहना चाहूंगा कि पंजाब को ज्यादा मिलना चाहिये क्योंकि हम शेयर भी ज्यादा करेंगे इसलिए हमें डलवपमेंट के लिए टेक्स का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिये। तीसरी बात में सेक्युलरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं। टाइम तो आप मुझे दे नहीं रहे हैं, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था और हमारा कहने का फर्ज़ भी है लेकिन हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, देश वाले भी शायद सुनना नहीं चाहते हैं। सेक्युलरिज़म की बात यहां कही जाती है। मुझे देख कर हैरानी होती है, मैं सुन कर हैरान होता हूं, सब पार्टियां जोर जोर से चिल्ला कर कहती हैं कि सेक्युलरिज्म इस कंट्री का बेस प्वाइंट है, सब कहते हैं कि हम ज्यादा सेकुलर हैं। बहुत बुरी बात है अगर एक भी इन्सान की मौत हो जाए। एक जानवर की मौत भी हो जाए, वह भी बहुत बुरी बात है। हमारा देश धर्मी लोगों का देश है। लेकिन अगर इस देश में कहीं माइनारिटी के दो क्रिश्चियंस की डेथ हो जाती है तो सारी पार्लियामेंट यह बात कहती है कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम यह कहना चाहेंगे कि इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर राजधानी के अन्दर चार चार हजार कत्ल हो जाते हैं। बीस बीस साल के बाद न कोई कत्ल का मुकदमा चलता है, न कोई फेस करता है, न कोई बात करता है, मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसा सेक्युलरिज्म है, किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, डबल पालिसी कैसे चल रही है? यह अगर देश की राजधानी है तो बोकारो, कानपुर

की हिस्ट्री सुन लें। इस पार्लियामेंट में फिगर आई हैं कि तीन-तीन हजार लोग वहां कत्ल हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें सारे लोगों के मन में सही सोच पैदा करनी चाहिए कि अगर कंट्री को आगे ले जाना है, सही यूनिटी के साथ आगे बढ़ाना है तो सेक्युलरिज्म पर पूरे जोर से हमें एकमत होकर जोर देना चाहिए। कहीं एक जानवर की मौत होती है, मवेशी की होती है तो वहां पर भी हम सबको अफसोस करना चाहिए। लेकिन इस कंट्री में जिसमें इतने-इतने सारे हजारों लोगों की मौत हो गयी है, अभी तक किसी ने सारी भी नहीं की। यह मुझे बड़े अफसोस की बात लगती है और यहां कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं। यह समझ में नहीं आता है कि कैसे सेक्युलर लोग इस पार्लियामेंट में, हाउस में बैठे हुए हैं। यहां बड़े काबिल लोग भी बैठे हैं और बड़ी-बड़ी पार्टियां भी बैठी हैं। इसलिए आनरेबुल वाइस चेयरमैन साहब में आपके जरिए तीन-चार प्वाइंट्स ब्रीफ में कहना चाहता हूं। एक तो जो डीजल प्राइस की राइज की गयी है यह गलत की गयी है। मैं उसके साथ नहीं हूं और जो रिजरवेशन की गयी है वह अच्छी बात है। करनी चाहिए और जो पंजाब में लैंड की डिप्लीशन हो रही है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प होनी चाहिए। जो मिलिट्री का कारगिल का इश्यू है उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि सबने बधाई दी है, हम भी बधाई देते हैं हमारे जवानों को लेकिन साथ में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान में एक आर्मी में भी ऐसा चलने लगेगा कि पापूलेशन के बेस पर इनरोलमेंट होगा तो यह बात देश के लिए बदकिस्मती की बात है। वहां तो मेरिट होनी चाहिए कि किसका कद कितना है, किसकी छाती कितनी है। अगर वहां भी यह नहीं देखेंगे, पापूलेशन देखेंगे तो फिर इस देश का परमात्मा ही राखा है। इसलिए हम तो इतनी ही बातें कहेंगे जिन पर गौर करना चाहिए। बाकी जो प्रेजीडेंट साहब ने कहीं हैं हम उनका भी सपोर्ट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अच्छा कहा, अच्छे पैरे पहली दफा इस भाषण में लाए हैं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Before I call upon the next speaker, I have to take the sense of the House. We have a few speakers left. We want to conclude the debate. If you so agree, we can sit beyond five o'clock and conclude this discussion.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, provided the time allotted to each Member is not encroached upon by other Members by way of interruptions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Being a veteran Member, you must have observed that we are trying to enforce the time-limit.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, there is a statement by the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Yes, that is a listed Business.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We can have that after the discussion on the Motion of Thanks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Yes, before the House rises for the day.

DR. C. NARAYANA REDDY (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for allotting me a few minutes to speak on the President's

Address, in spite of the constraint of time. Sir, I was delighted to hear the honourable President stating that it is natural for our country to look at her past with pride and her future with hope and confidence. I treat this statement as highly realistic. According to Stephen Spender, an eminent modern English poet of 1930s, "Past is a bucket of ashes". I recollect, I remind the august audience here, he said that Past is a bucket of ashes. But one should not forget that under the ashes, there are bright spots. It depends on one's lung power to blow up the ashes and discover his path. In this context, I can say that we have been undermining our glorious past, the legacy of our unique culture. It is high time the Government took every possible step to protect our rich heritage of culture and efforts should be made to build the future on the foundations of the past. I also appreciate the efforts of the Government to put all the Indian languages on the computer network. Just now, we heard the speech of a honourable Member in Tamil, one of the richest languages of India. Why not we prepare our Indian languages to suit, to match, all the strategies, plans and innovations that are applicable to English? I am, happy to state a realistic fact that much before most of the European languages were born, most of the Indian languages were not only born, but they also produced rich literary works. We must be proud of them. In this context I would like to say that we do not find our languages finding a deserving place even after 50 years of independence. I would like to quote Lord Macaulay's statement made in 1835 while presenting the new Education Policy of India. He said: "I am going to give a new culture to India. Whether the British regime in India exists or not, our language and culture will remain for ever". So, it is not our culture; it is their culture, the English culture, foreign culture, foreign language. That was the statement made by Lord Macaulay. Even today, after 50 years of Independence, it is relevant. It is unfortunate that his prophecy is being proved true in Independent India till now, in letter and spirit. Westernization in every walk of life is the fashion of the day. I am not against employing English in different sectors, but it should not be at the cost of the mother tongue. It is unfortunate to note that in some of the privately-managed schools, convent schools, the mother tongue is not at all compulsory, even as a second language. I do not mind if the medium of instruction is in English. I do not mind if the first language is English, but at least the place of second language should be given to the mother-tongue. Now, what is happening is that they put the mother-tongue in the second place and say that the student can substitute it with 'special English'. A student, who joins those schools does not know the alphabets of the regional language or the mother tongue. It is highly deplorable. The Government has to take stern measures in this regard. It is evident why in the place of the mother tongue, he speaks the other tongue.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Double tongue.

DR. C. NARAYANA REDDY: Double tongue belongs to the political area. Please do not bring in such expressions here. We proclaim that the culture of a nation is the identity of a nation. Please go through the slogan given by the Department of Culture. We proclaim that the culture of a nation is the identity of a nation.

यानी अस्मिता है संस्कृति, एक राष्ट्र की अस्मिता है।.....**(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य:** हिन्दी में बोलना चाहिए।.....**(व्यवधान)**

**डा० सी० नारायण रेड्डी:** जी, मैंने इससे पहले बोला था कि क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको पता चले। आपको पता चलेगा यह कि क्यों बोल रहा हूं। समझाने के लिए बोल रहा हूं, अनुवाद से दूर रहने के लिए बोल रहा हूं, मैं। ठीक है।.....**(व्यवधान)**

There is every possibility of losing our identity, of losing our culture, of losing India's languages.

In the early part of his speech the Hon. President has given a glorious picture of the regional parties in shaping the destiny of our nation. He rightly said: "The participation of regional parties in managing the affairs of the country at the national level in a stable and coherent coalition, augurs well for our democracy and federal polity". Sir, I compare the polity of a country to a green tree. The national parties are like the main branches and the regional parties are like twigs—small branches. The tree will not have a totality and grandeur without either of them. Similarly, a polity cannot be successful without the harmonious blending of the national parties and the regional parties. The hon. President has, therefore, rightly appreciated the participation of regional parties in strengthening the federal polity.

It is heartening to note that the government has decided to create a separate Depatement of Primary Education and Literacy. Here, I would like to make an observation on literacy. In view of the size of our population, the efforts of the machinery shall have to be increased manifold. In a period of ten years, that is, from 1981 to 1991, we could register an increase of 8.65 per cent in the rate of literacy, that is, from 43.56 per cent in 1981 to 52.21 per cent in 1991. It is interesting to observe that the increase in female literacy is 9.53 per cent, whereas the increase in male literacy is 7.75 per cent only. It clearly indicates the onward march of 'Nari Shakti' over 'Purusha

Sir, we must congratulate the people of Kerala for their sustained efforts in this regard. The State has 89.81 per cent literacy and it is 100 per cent in Ernakulam District. The Honourable President has also referred to the participation of youth in the sports and arts fields. It is the misfortune of this country that though we have about 100 crore population, we are unable to

get a medal in the Olymic games. According to reliable information, sports organizations are engulfed in political bickerings, with very little time left for promoting sports. It is high time we create sports infrastructure in every nook and corner of the country and provide a sports atmosphere. I hope the concerned sports authorities would accept my comments sportingly.

Before I conclude, Sir, I would like to emphasise that our Government should take every possible step to promote our culture, languages, arts and sports, to shape our younger generation into perfect human beings. I am quite optimistic in this respect. I am not at all pessimistic about our bright future. We have to strive hard to achieve the goal. Sir I would like to quote one 'sher'—before the bell rings—from my Urdu gazal—a Telugu poet writing a gazal in Urdu—to strengthen my stand in this regard, as a final remark about the future.

'ये गलत है कि खड़ी है राह आगे गुल्फिसां,'

फूल बरसाने वाली राह आगे खड़ी है, ऐसा नहीं है .....

'ये गलत है कि खड़ी है राह आगे गुल्फिसां, मैं चला कांटों पर मुस्तकदिल को लाने के लिए।'

Thank you.

**श्री संघ प्रिय गौतम:** उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अंत में संसद् सदस्यों से एक अपेक्षा की है कि लोगों ने आप को चुनकर भेजा है, उन्हें आप से बड़ी अपेक्षाएं हैं। वे लोग आशा करते हैं कि संसद की कार्यवाही उच्च-स्तर की होगी और सभी सदस्य अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर आपसी सहमति और सहयोग की भावना से कार्य करेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि संसद के आगामी सत्र में तथा इस के बाद के सत्रों में दोनों सदनों में रचनात्मक परिचर्चा होगी।

मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को जिन्होंने इस परिचर्चा में अब तक भाग लिया है, बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। महोदय, मैं कल से सुन रहा हूं। यहां बड़ी सकारात्मक बहस और चर्चा हुई है। आलोचना हुई है, लेकिन समालोचना हुई है और सुझावों के साथ समालोचना हुई है जिसमें राष्ट्रहित को सामने रखा गया है। इसलिए राष्ट्रपति जी की इस अपेक्षा के अनुकूल हम संसद् सदस्य खरे उतर रहे हैं। इस तरह एक आशा की किरण हम को नजर आती है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय जो अपना गठबंधन है जनतांत्रिक, उसको बधाई देना चाहता हूं, इसके नेताओं को, इसके घटक दलों को बधाई देना चाहता हूं। काश कि, श्री जनेश्वर मिश्र जी यहां पर उपस्थित होते। उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया, बड़े तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए, लेकिन उन्होंने एक सिक्के के एक ही पहलू को परिलक्षित किया, काश वह सिक्के के दूसरे पहलू को भी सुनते। पिछले एक दशक से हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में बड़ी क्षति हुई है, बड़ा ह्रास हुआ है और बड़ी गिरावट आई है। राजनैतिक क्षेत्र में तो बहुत गिरावट आई, अस्थिरता आई, राजनीतिज्ञों के मान-सम्मान में कमी आई और राजनैतिक दलों ने, राजनैतिक नेताओं ने गैर-जिम्मेदाराना बहुत से ऐसे काम किए, जिनसे जनता का विश्वास उनमें घटा। इसलिए देश के सामने सबसे पहला एक मुद्दा यह था कि इस राजनैतिक अस्थिरता को कैसे दूर किया जाए, गिरती हुई राजनैतिक अवधारणा जो लोगों में हमारे प्रति हो गई है उसको कैसे

दूर किया जाए। इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन मेरे छोटे से दिमाग के आधार पर तीन कदम बहुत जरूरी थे।

उपसभाध्यक्ष जी, पहली बात, जिसकी ओर मैं कांग्रेस के सदस्यों का ध्यान खासतौर से चाहूंगा। काश कि इस देश में राष्ट्रीय राजनैतिक दल भी मजबूत रहते और क्षेत्रीय दलों का भी महत्व रहता तो यह इतनी क्षति न होती, लेकिन हमारे राष्ट्रीय राजनैतिक दल कमजोर होते चले गए। कांग्रेस की स्थिति देखिए, लोकसभा में 1984 में 415 सदस्य निर्वाचित हुए, 1989 में 195 रह गए, राजीव जी की हत्या की हमदर्दी के बावजूद 1991 में 231 ही आए, यदि हत्या न हुई होती तो शायद डेढ़ सौ ही रहते, 1996 में 141 आए, 1998 में 139 आए और 1999 में 112 ही रह गए।

इब्तिदाएइश्क है रोता है क्या।
आगे आगे देखिए होता है क्या। .....(**व्यवधान**)

कहीं जीरो पर न रह जाएं। प्लीज, सुन लीजिए। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल को मजबूत होना चाहिए, लेकिन मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को।

मैं अकेला ही चला था जनिबे मंजिल,
मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

उपसभाध्यक्ष जी, 1984 में आए थे 2, 1989 में हो गए 86, 1991 में हो गए 120, 1996 में हो गए 162, 1998 में हो गए 181 और 1999 में हो गए 182 और अगर अपनी नालायकी न होती तो जो 30-40 अपने आप घटा लिए, वह मिलाकर सवा दो सौ होते। .....(**व्यवधान**) ..... मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप सुनिए। आप में मोरल करेज नहीं कि जो आप अपनी गलती को स्वीकार कर लो। तो राष्ट्रीय राजनैतिक दल मजबूत हो, जो स्थिरता के लिए एक मुद्दा आधार बन सकता है। इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। जब एक राष्ट्रीय दल मजबूत नहीं बनता और बहुमत लाने की स्थिति में नहीं पहुंचता तब तक इस देश में एक सघन राजनैतिक गठबंधन क्षेत्रीय दलों के साथ होना चाहिए और वह सघन गठबंधन तब हो सकता है, जब कार्यक्रम एक हो, नेता एक हो। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने क्षेत्रीय घटक दलों को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं को, कि उन्होंने चुनाव से पहले एक सघन गठबंधन बनाया, कार्यक्रम निर्धारित किया और एक नेता में विश्वास दिया।

उपसभाध्यक्ष जी, तीसरी चीज, अगर स्थिरता फिर भी न आए तो फिर संविधान के ऊपर भी सोचना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

इन तीनों दृष्टिकोणों से मैं बधाई देता हूं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन को कि उन्होंने राजनीतिक स्थिरता पैदा करके इस देश के लोगों के सपनों को साकार किया है।

अभी जनेश्वर मिश्र जी कह रहे थे कि डीज़ल के दाम बढ़ गए और बड़ा नुकसान देश का हो रहा है, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिए की बार-बार जब चुनाव होते हैं तो लाखों कारें सड़कों पर दौड़ती हैं और डीज़ल कारों में सड़कों पर बर्बाद होता है। अगर ये चुनाव जल्दी-जल्दी न हों तो क्या हम उसे बचा नहीं सकते? इस देश में करोड़ों बच्चे बगैर पुस्तकों और कागज़ों के पढ़ नहीं पाते, जल्दी-जल्दी चुनाव होते हैं तो क्या पर्चों और पोस्टरों में कागज़ बर्बाद नहीं होता? यह एक दूसरा प्रश्न है। इसलिए चुनाव

जल्दी-जल्दी न हों, ऐसी व्यवस्था हमें अपने देश में करनी चाहिए। जो पैसा आज अस्पतालों पर, सड़कों पर, कालेजों पर खर्च होना चाहिए, वह चुनाव में खर्च होता है और उससे जनता का विश्वास घटता है और इसी कारण परसैंटेज आफ पोलिंग हर बार गिरती चली जा रही है, लोगों की दिलचस्पी चुनाव में कम होती जा रही है। इसलिए चुनावों को जल्दी-जल्दी होने से रोकने के लिए राजनीतिक स्थिरता पैदा करना जरूरी है और इसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, कल श्री बिसि जी ने ध्यान दिलाया था कि इस अभिभाषण में क्या मुद्दे होते हैं, क्या कंटेंट्स होते हैं। पिछली बार की तेरह महीने की सरकार ने विशेष रूप से चार मुद्दे लेकर वे अपनी नीतियां बनाई थीं— देश की सुरक्षा शुचिता, सामाजिक समरसता और स्वदेशी। एक आपको घटना सुनाता हूं। मैं गाज़ियाबाद से आ रहा था, जाड़े के दिनों में सुबह पांच बजे पैट्रोल पम्प पर एक अकेला पैट्रोल डालने वाला था। एक दम्पत्ति, जिसमें जेवर पहने हुए महिला थी, पैट्रोल भरवाकर जब बैठने ही वाला था तभी एक आदमी, जो रोबर था, उसने एक चद्दर डाल रखी थी और जो गन्ना होता है, उसका एक बड़ा टुकड़ा उस चद्दर में से इस तरह बाहर करके उसने उस दम्पत्ति को कहा कि अगर ये जेवर नहीं उतारे तो गोली मार दूंगा और इस तरह उसने उन्हें लूट लिया क्योंकि उस दम्पत्ति ने समझा कि वास्तव में, सचमुच रिवाल्वर होगी। हमारे देश की इतनी शक्ति थी, लेकिन एटम बम नहीं था हमारे पास इसलिए छोटे-छोटे देश हमको धमका दिया करते थे। इसलिए हमने अपने देश की सुरक्षा को मजबूत किया।

मान्यवर, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के जीवन में शुचिता आवश्यक है। मैं बधाई देता हूं अपनी इस सरकार को और इससे पहली सरकार को कि उन्होंने सामाजिक जीवन में शुचिता का परिचय दिया और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या उस तरह का कार्य नहीं किया।

तीसरी चीज़ है, मान्यवर, सामाजिक समरसता। कल से मैं सुन रहा हूं, एक भी कम्युनल रायट नहीं हुआ। अभी एक सज्जन ने कहा था कि आपने बात का बतंगड़ बना दिया। आप जानते हैं कि मैं स्वयं अल्पसंख्यक हूं, दलित परिवार से आया बुद्धिस्ट हूं मैं। मुझे उतनी ही हमदर्दी है इसाई, सिख, मुसलमान, सबसे जितनी मुझे बुद्धिस्ट से हमदर्दी है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में धर्मान्तरण होता है, इसाई लोग सिखों का धर्मान्तरण क्यों नहीं करते? इसाई लोग मुसलमानों का धर्मान्तरण क्यों नहीं करते? जब मुसलमानों का धर्मान्तरण होगा तब ये क्या कहेंगे और जब सिखों का धर्मान्तरण होगा तब क्या कहेंगे? ....**(व्यवधान)**...लेकिन ये हिन्दुओं का ही धर्मान्तरण क्यों करते हैं और हिन्दुओं के धर्मान्तरण में भी ये अपर क्लास का धर्मान्तरण क्यों नहीं करते? ....**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** संघ प्रिय जी, आप धर्मान्तरण के विषय पर मत बोलिए, धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलिए।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** मैं इसी पर बोल रहा हूं। जिस दिन दूसरे धर्मावलंबियों का धर्मांतरण होने लगेगा तब आपको मालूम पड़ेगा। यह दलितों का ही धर्मांतरण क्यों होता है? इसलिए कि वे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, अशिक्षित हैं, बेघर हैं, बेगुनाह हैं, अगर उनसे मोहब्बत है तो यहां माईनोरिटीज़ के सैकड़ों इंस्टीटयूशंस हैं क्या वहां रिज़र्वेशन पालिसी लागू है? क्यों नहीं लागू करते आप रिज़र्वेशन पालिसी अगर आपको उनसे हमदर्दी है तो?

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहंगा कि इनके खिलाफ जो दंगे होते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से अगर आपका परिचय कराऊं तो मैंने 23 मर्तबा जेल काटी है इसके लिए और सत्याग्रह किया है सामाजिक समरसता के लिए। ये लोग कहते हैं कि एक विशेष वर्ग के लोग चिल्लाते हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण होता है इसलिए हिंदू संगठन चिल्लाते हैं अगर नहीं होता तो नहीं चिल्लाते। मैं इसकी निंदा करता हूं अल्पसंख्यकों पर कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए।

चौथी चीज यह है कि स्वदेशी का कंसेप्ट बड़ा व्यापक है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती से संचालित होती है। में बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को कि पिछली बार सारे राष्ट्रीय बजट का 60 प्रतिशत खेती के लिए निर्धारित करके उन्होंने आज खेती की उपज को इतना बढ़ा दिया है कि अब की बार रबी की बंपर क्रॉप हुई है और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को।

अब सामाजिक न्याय की बात आती है। हमने कहा कि हम अधिकार देंगे, सामाजिक अधिकार देंगे। महोदय, पहली बार इस मंत्रिपरिषद में 8 महिलाएं मंत्री बनी हैं। इतना बड़ा सामाजिक न्याय महिलाओं को पहले कभी नहीं मिला (समय की घंटी) अभी तो मेरे 15 मिनट बाकी हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** आपके जो दूसरे साथी हैं, उनको समय नहीं मिलेगा फिर।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** ठीक है, 2 मिनट और दे दीजिए। महोदय, पहली बार 11 दलित लोग सरकार में मिनिस्टर बने हैं और 3 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, जो कभी किसी सरकार में नहीं बने। यह सामाजिक न्याय दिलाने वाली सरकार है। आज इतना बड़ा सामाजिक न्याय का अधिकार दलितों और महिलाओं को मिला है ....(**व्यवधान**)

**श्रीमती जयंती नटराजन:** आपको क्यों नहीं मिला?

**श्री संघ प्रिय गौतम:** मैं महामंत्री हूं। मंत्री बनकर छोटा हो जाऊंगा।

**श्री दीपांकर मुखर्जी:** (पश्चिमी बंगाल) सबको छोटा बना दिया आपने।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** हमारे सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके और उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और अपनी सरकार से यह निवेदन करता हूं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फोरवर्ड लिखा था जनसंघ का डाक्यूमेंट जब तैयार किया गया जनवरी 14,1973 में तो उसमें उन्होंने जो लिखा था वह मैं क्वोट करना चाहता हूं। महोदय कल नेता विरोधी दल ने सही कहा था कि शिक्षा और दवा के क्षेत्र में गरीबों के सामने कठिनाई पैदा हो रही है। मैं भी गरीब समाज से निकलकर आता हूं। वाजपेयी जे ने फोरवर्ड में लिखा था कि "In its annunciation of the Party's aims, the manifesto expressed a resolve to rebuild India as a social and economic democracy. On economic issues, the Jan Sangh approach, right from the outset has been based on pragmatic considerations and not on dogmas. It rejected both complete nationalization as well as free enterprise and favoured a middle course."

महोदय, मैं दूसरी प्रार्थना और करना चाहता हूं कि हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में कहा है कि उपयुक्त कानूनी, सरकारी तथा सामाजिक प्रयासों के द्वारा और बड़े पैमाने पर शिक्षा तथा शक्ति सम्पन्न बना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के इस काम में कभी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मैंने एज ए लॉयर देखा है The Supreme Court has overruled its many decisions. इसलिए कोई फाइनल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। जब हमारी राजनीतिक इच्छा-शक्ति हो तो हमें कानून बनाकर के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रावधान हैं, जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करना चाहिए। इन शब्दों के साथ श्री अरुण शौरी जी द्वारा प्रस्तावित और श्री विरुम्भी द्वारा समर्थित प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI KORAMBAYIL AHAMMED HAJI (Kerala): The hon. President delivered his Address. The people of this country expect that the noble traditions of this great country would be upheld and safeguarded. The main function of every Government is to unite the country. In our country, approximately, a hundred crore pepole of different religions, languages, culture and different geographic features live together. So this country can go ahead only with the co-existence and cooperation of different sectors of the society. Unity in diversity is India's individuality. Our country can go ahead only in this way. Any acitivity ignoring this fact will destroy our country. Another vision of the Government is to work for the welfare and progress of all the people and their general uplift, without any discrimination. It is also the Government's duty to give equal opportunity to all the people and bringing them into the national mainstream.

Protection of the geographical boundaries of the country is the main duty of the Government-Insecure boundaries are dangerous for the safety of the nation. Sir, we should try to solve all sorts of problems with our neighbouring countries in a peaceful manner. I hope the Government will continue with their efforts to solve all the problems, keeping this in view.

The Lahore bus journey was good. But we should see that the enemy does not misunderstand our efforts for peace as our weakness.

A war will bring untold miseries to the people. Then the precious resources have to be utilized for meeting the war. So, we will have to avert wars and we will have to seek the path of peace. In the wake of the military coup in Pakistan the Government should be more vigilant and alert and see that the Military Government in Pakistan does not pose any threat to our country. Effective and suitable measures have to be taken to eliminate delays in the judicial system, as pointed out by our President. Due to various formalities the judiciary has become inaccessible to the ordinary people. So, the outdate formalities have to be repealed and justice should be made easily available to the poor people. In the best interest of the people belonging to the southern States, it is necessary to constitute a Bench of the Supreme Court in south India. Before I conclude I wish to state that the Government should realize the realities in our country and strengthen the unity and the secular nature of

our mother-land. Thank you.

SHRI K.M. SAIFULLAH (Andhra Pradesh): Sir, I thank the President for his Address and I support it provided it is implemented properly. In the President's Address there is a mention about stability, welfare of OBCs and minorities, 33 per cent reservation for ladies and a package of assistance for the welfare of the families of the jawans who laid down their lives during the Kargil operation. With regard to stability, the whole India is watching whether there is stability in its true sense, whether the stability is for power or whether the stability is for a prosperous India, because some of the leaders who accused each other have joined together. In that context, the whole of India is watching whether they will stick on to the stability of the country or whether they will stick on to power. I request the NDA Government and other people to keep up the image and get a good name by working for the stability of the country and not for power. They have mentioned about the welfare of the OBCs and the minorities. But they have not mentioned what they are going to do for the OBCs and the minorities. They have simply mentioned about welfare. In that context I want to tell the Government that if they want get good name for the Government, if they want to remove the apprehensions in the minds of the minorities that they are not for the minorities, it is the best opportunity for the NDA Government to provide some reservation for the OBCs and the minorities, both in politics and in employment so that the apprehensions created against them will vanish. This is the best opportunity for the Government to take advantage and give reservation to the minorities and the OBCs both in politics and in employment so that the bad name which was created by somebody else will go away. I request the Government to take this opportunity and act accordingly.

With regard to 33 per cent reservation for women, it was stated by three Government. All the women and everybody was watching when it would become a law. Still it stands as a dream. The President and the people say that there is stability now. In that context of stability, I request the NDA Government to introduce 33 per cent reservation for women and see that their dream is fulfilled. As regards 33 per cent reservation, I would like to bring to the notice of the Government of the NDA that in my State, in Andhra Pradesh, Mr. Chandrababu Naidu, had already introduced 33 per cent reservation in the Panchayat Raj Institutions, municipalities and local bodies and everywhere 33 per cent reservation is going on.

**[The Vice-Chairman (Shri Sanatan Bisi)** in the Chair] So far as reservation for minorities is concerned, it can be done by amending the Act. That is why the State Government of Andhra Pradesh has given the right to all the monority communities to become a member of the Panchayats and municipalities. In every municipality and every Panchayat and Zilla Parishad

there will be one or two members of minority communities to safeguard the interests of the monorities. If the Government of Andhra Pradesh can give 33 per cent reservation and also reservation to minorities, why can't the NDA Government do to? The NDA Government should do it immediately to remove the apprehensions in the minds of the People. I would request the Government to take this opportunity so that there is stability in the country, so that this Government can rule the country for five years.

So far as Kargil is concerned, we are proud of our Jawans who fought for the nation. By successfully testing nuclear weapons the Government has created confidence in the minds of the Indians that we are also strong. Whichever Government comes, we want a strong India. We must give full support to our Jawans who have fought in Kargil.

Thank you.

**श्रीमती कमला सिंहा** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों को तरेहवीं लोक सभा के गठन के बाद संबोधित किया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सरकार का आने वाले दिनों में काम करने का खाका दोनों सदनों के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किया। सरकार क्या करने जा रही है? क्यों ये चुनाव हुये? ये सब वह बातें इसमें विस्तार से कही गई हैं। मेरे पास चूंकि समय की कमी है और जो बातें मैं कहना चाहती थी शायद नहीं कह पाऊंगी और जिनका इसमें उल्लेख करना आवश्यक था। मैं सरकार का केवल ध्यान कुछ मुद्दों पर आकर्षित करना चाहूंगी। एक तो हिन्दुस्तान की आबादी भंयकर रूप से बढ़ती जा रही है और आबादी पर रोक लगनी चाहिये। आज के दिन में दुनिया में हर छटा व्यक्ति हिन्दुस्तानी है। अब इस आबादी को कैसे रोका जाए, पापुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोका जाए, सरकार इस पर विशेषरूप से ध्यान देगी, यह मैं अपेक्षा करूंगी। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

दूसरी कुछ और बातें हैं जिनका उल्लेख उसमें होना चाहिये था जो नहीं हुआ है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी। राष्ट्रपति जी ने बहुत विस्तार से बातों को रखा है फिर भी एक-दो बातें जो छूट गई हैं मैं उनका ही उल्लेख करूंगी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में माइग्रेंड लेबर के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। हिन्दुस्तान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और गांव में खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। इसलिये बड़ी संख्या में लोक काम की तलाश में शहर में आते हैं और वे शहर में इंसान की तरह से जीवन जीने के बजाय पशु की तरह जीवन जीने के लिये मजबूर हो जाते हैं। ये माइग्रेंड लेबर गांव से आकर स्लम बनाकर शहर को भी गंदा करते हैं। उनके लिये मजबूरी हो जाती है और दूसरी ओर उनके जीने का कोई रास्ता नहीं होता है और वे वापस भी नहीं जा पाते हैं। यह जो माइग्रेड लेबर का प्रॉब्लम है उसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना होगा। इस पर ध्यान देने के लिये केवल एक ही रास्ता है कि छोटे-छोटे शहरों में, ब्लाक लेवल पर छोटे-छोटे कल कारखाने अगर खुल जाए। स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्री का बड़े पैमाने पर जाल बिछा दिये जाए या फिर एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री का जाल बिछा दिया जाए और सही ढंग से मार्केटिंग का इंतजाम हो तो इसका एक रास्ता खुल सकता है।

चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ नहीं कहा है। कोई भी मां-बाप यह नहीं चाहता है कि उसके बच्चे काम करने के लिये जाएं लेकिन मजबूरन वे काम करने के लिये भेजते हैं और लाखों बच्चे काम करने जाते

हैं। हमारे देश में करीब दस मिलियन यानी एक करोड़ बच्चे खासकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बच्चे होते हैं जिनमें लड़कियों की संख्या भी है और लड़कों की संख्या भी है। जब ये काम करने के लिये जाते हैं तो इनके साथ फिजिकल और मेंटल टार्चर होता है तथा एक्सप्लायटेशन भी होता है। खासकर लड़कियों का तो शोषण कई तरह से होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यह शोषण छोटे-छोटे बच्चों का भी होता है। सारी दुनिया में चाइल्ड लेबर के बारे में कहा है और खासकर आई०एल०ओ० की ओर से कहा जा रहा है 'देयर शुड नोट बी ऐनी चाइल्ड लेबर'। अपने यहां रेडियों और टेलीविजन में हर रोज प्रचार होता है लेकिन खाली प्रचार से तो काम नहीं बनेगा। चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन के लिये पोजिटिव प्रोग्राम बनाना होगा नहीं तो यह बदलने वाला है नहीं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में तेरहवीं लोक सभा में हुये चुनाव के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह इस सदी का अन्तिम चुनाव है। यह सही है कि यह अंतिम चुनाव है और इस सदी में हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह संसद पांच साल तक कार्य करेगी। इसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। महोदय, मैं बिहार से आती हूं और इस सदन में बोलते हुये कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि इलैक्शन में धांधलियां हुई, करप्शन हुआ है। मेरे मन में एक शंका, एक प्रश्न आता है कि हम बाहरी दुनिया के लोगों को कहते है कि we are the largest democracy in the world. But are we really a democratic country.

जिस देश में आधे से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और ये गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग अपना बोट देने नहीं जाते हैं, स्वेच्छा से अपना प्रतिनिधि चुन नहीं पाते हैं और जहां पर चुनाव होता है वहा पोलिंग स्टेशन पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। चुनावों में 'बाहुबली' नया शब्द आया है। बाहुबली हथियार लेकर खड़ा रहता है और बूथ केप्चरिंग करता है। सारे हिन्दुस्तान में यह बीमारी फैल गई है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी 1957 में बिहार की बेगूसराय कांस्टीट्एन्सी में यह परफेक्ट तरीके के साथ शुरू हुआ था और उसके बाद 1974 में जब जय प्रकाश जी का आन्दोलन शुरू हुआ तो जयप्रकाश जी ने कहा था कि मैंने सुना है चुनाव के पहले ही बैलेट बॉक्स बन्द हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश उस दिन की मीटिंग में मैं भी वहां मंच पर मौजूद थी और मैंने अपने कानों से सुना था। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान भर में यह फैल गया है। लोकतंत्र को अगर सही मायने में बचाना है या लोकतंत्र को उसके रूप में रहना है तो क्राइम, मनी एंड करप्शन, कास्ट जो प्रभाव बढ़ रहा है, इससे बचना होगा। सरकार को निश्चित रूप से एक नई दिशा तय करनी पड़ेगी ताकि हमारे देश के लोग सही मायने में वोट दे सकें।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में छोटे राज्यों के गठन के बारे में चर्चा की है। मेरा उनसे और वर्तमान सरकार से विनम्र निवेदन होगा कि छोटे राज्यों का गठन अवश्य किया जाए। हम उसके समर्थक है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया जाए और स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत देखा जाए कि कौन-कौन से राज्यों से छोटे राज्य बनाया जाए। बिहार के एक हिस्से को काट कर बंनाचल की बात चल रही है। मैं चाहती हूं कि वनांचल का गठन अवश्य हो लेकिन केवल बिहार को काटकर नहीं। वनांचल के जो दूसरे हिस्से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल बिहार सबको मिलकर एक प्रान्त बनाया जाए। जो ऐसा प्रान्त बनेगा जिसका वास्तव में भविष्य होगा।

जो एक ऐसा प्रांत बनेगा जिसका सचमुच में भविष्य होगा, जो इंडस्ट्रियलेट डेवलमेड स्टेट बनेगा। ऐसा करना चाहिये नहीं तो केवल बिहार के अगर काटा जाएगा तो इससे बिहार के लोगों को मानसिक रूप से दुःख पहुंचेगा। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करुंगी। में बिहार से आती हूं, हमारा बिहार, खासकर के उत्तर बिहार छह महीने बाढ़ की चपेट में रहता है, आना-जाना असंभव हो जाता है, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है और यहां हम केवल हाय-हाय करेंगे या भारत सरकार से चाहें कि भारत सरकार बाढ़ रोकने के लिये, बाढ़ सहायता के लिये कुछ रकम दे दे उससे कुछ बात नहीं बनेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की सारी नदियां, सच कहा जाए तो पूरे उत्तरांचल की नदियां भारत के बाहर से आती हैं, बिहार मैं ये नदियां नेपाल से, हिमालय से जन्म लेकर आती हैं और आकर बिहार के उत्तर के हिस्सों में बहकर गंगा में मिलती हैं। इस हालत को बदलने के लिये नेपाल के साथ एक जोइंट वाटर कंट्रोल कमीशन बनाना चाहिये। जब तक यह वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंट्रोल कमीशन नहीं बनाया जाएगा तब तक बिहार को बाढ़ की चपेट से नहीं बचाया जा सकता है। मैं हर बात को इस साल, हर बार इस सदन में कहती आई हुई। बी० पी० सिंह की सरकार के समय में यह कहा गया था, मेरे एक रेजोल्यूशन के बहस के उत्तर में कि हम इसको जल्दी करने जा रहे हैं किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं वर्तमान सरकार से अपेक्षा करूंगी इस दिशा में उचित कार्रवाई करे।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कारण और दूसरे अन्य कारणों से इंटरनेशनल टेरेरिज्म की वृद्धि हुई है। हमारे देश के अंदर भी तरह-तरह के टेरेरिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल टेरेरिज्म की चपेट से बचाने के लिये, खासकर के बिहार का जो नेपाल का बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर है, वह बहुत ही पोरस बॉर्डर है और बंगलादेश के साथ भी बिहार का जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वह भी पोरस बॉर्डर है। मैंने इसमें पढ़ा है कि बंगालदेश के साथ जो बॉर्डर है उसको घेर दिया जाएगा लेकिन नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर है और दूसरे जो बॉर्डर हैं उनका हम क्या करेंगे? स्मगलिंग इतनी तेजी से होती है कोई हिसाब नहीं है और साथ ही साथ आई०एस०आई० का पूरे उत्तर बिहार में जाल फैलाया गया है। नकली रुपयों की प्रिंटिंग हो रही है। पांच-पांच रुपए के नोट छप रहे हैं, सौ-सौ रुपये के नोट छप रहे है। कौन सी फेक मनी है, कौन सी असली मनी है पता ही नहीं चलता है। इस हालत को अगर सुधारना है तो इस पोरस बॉर्डर को जो बिल्कुल स्मगलर पैराडाइज है, उसे रोकने के लिये सही कदम उठाना पड़ेगा नहीं तो बहत मुश्किल होगी। आगे आने वाले दिनों में इतनी परेशानी बढ़ जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल होगा मैं राष्ट्रपति जी को धंयवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने अभिभाषण में नारी शक्ति, युवा शक्ति का उल्लेख किया। नारी शक्ति इस देश की आधी आबादी है। खैर 33 प्रतिशत आरक्षण वाली बात उन्होंने की इसके लिये में वर्तमान सरकार को, हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने देखा है, इस बार जो बिजनेस की लिस्ट आई है उसमें भी लिस्टड है। मैं चाहूगी इस बार सभी दल, दोनों सदनों के, लोक सभा के तथा राज्य सभा के, सभी मिलकर, खासकर मुख्य विरोधी दल कांग्रेस पार्टी इसमें साथ देकर कम से कम इस विधेयक को तो इस सत्र में अवश्य पारित करा दे ताकि आने वाली पीढ़ी यह कहें कि कम से कम एक काम तो कांग्रेस ने कंस्ट्रक्टिव किया, कनस्ट्रक्टिव वर्क करने में सरकार का साथ दिया। इतनी बात कहकर मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

5.00 P.M.

SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA (Andhra Pradesh): Sir, I would like to congratulate the Government for taking a resolve to start the second generation reforms, multi-sectoral growth and also the pledge to overcome the scourtage of poverty, unemployment and discrimination, and the usher in an era of economic and social change. This is a bold departure from the past. It is clear from the persual of the President' Address that the Government has decided to give top most priority to social sector development. In the field of education, a separate department of Primary Education and Literacy has been created. The Government also proposes to announce an action plan to give a greater thrust to female literacy and primary education, besides formation of a programme for provision of primary school buildings for all unsound habitations. Apart form the formulation of a National Health Policy, the Government has decided to improve the rural infrastructure. The Government has made a firm commitment to provide clean drinking water to all the villages in the next five years.

Sir, coming to the crucial point of representation of women, I would like to draw the attention of the House that women constitute half of the population of the world, but they are a politically deprived lot. This is not a myth, but a harsh reality. I would also state that giving of administrative, legislative, political and economic power to women is the most burning issue of the present-day world. But is spite of the plans and promises of the repective Governments is most of the Afro-Asian countries and elsewhere, the members of the fair sex, at times, become the target of various kinds of injustice, physical violence, mental torture, discrimination in employment, etc. Sir, almost all the constitutions of the world talk of equality between men and women. But, in practice, the latter is the loser and the sufferer. According to a recent U.N. bulletin, women have not achieved equality with men in any country. No one has raised his or her voice in this respect. It seems to have become an accepted norm in the corridors of power that men have to be given the first preference. This tendency has to go. It is a matter of dismay that in a large number of countries, across the globe, there is no urge in men to share their powers of governing the society and running the administration with women. I would like to say that no national could prosper unless there is a serious effort to empower women, and invest in the girl child.

Keeping the plight of women in view, I am happy to note that the Government has now decided to reserve, through legislation, 33% seats for women in Parliament and State legislatures. I hope this will be done as early as possible.

Sir, I am happy to say that my Guru, my mentor and philosopher, late Supremo Shri NTR, has introduced me to politics and has given me the social status at an early age. He has also given property rights to women. I am really happy to say that our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, has taken many steps in order to empower women. True to his commitment, he allocated more number of seats for women in the Assembly as well as in the Parliament elections, than any other political party has done. The TDP is the first party to pass a resolution favouring 33% reservation of seats for women in the Legislature.

I am very happy that the Government has decided to provide free education to the girl child up to the college-level, including professional courses, and setting up of a development bank for women entrepreneurs in the small-scale and tiny sector, which will go a long way in resolving the sufferings of women. Sir, I congratulate the Government on this provision and I sincerely hope that our friends in the Opposition would extend cooperation, especially in regard to pssing the proposed legislation which is being brought by the Government very soon.

I would also draw the attention of the House to the extensive damage caused to public and private property in Srikakulam district in Andhra Pradesh, as a result of the cyclonic storm which struck north coastal Andhra Pradesh on 17th October, 1999. In this context, already, our dynamic Chief Minister Chandrababu Naiduji, has requested for Rs. 40 crores as initial assistance for relief. I would, therefore, humbly request the hon. Prime Minister to release the amount as asked for by the State Government.

Once again, I am thankful to the President for addressing the Joint Session of both the Houses. I am thankful to the Chair for giving me this opportunity to say a few words. Apart from this, the Government of Andhra Pradesh has submitted a memorandum on giving relief to farmers who have suffered heavy losses on account of the drought in the State. I hope, the Government will, definitely, come to the rescue of the State Government for helping the drought-affected farmers also.

**श्री मोहम्मद सलीम** (पश्चिमी बंगाल): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दो रोज़ से राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर यहां चर्चा हो रही है। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। यहां पर एक सवाल स्टेबिलिटी के बारे में उठा है, स्थायित्व के बारे में उठा है। पिछले कई चुनावों में भी यह सवाल उठता रहा है और इस बार भी यही कहा गया है। लेकिन सिर्फ 181 से 182 हो जाने से इंस्टेबिलिटी खत्म हो कर स्टेबिलिटी आ जाती है, ऐसे आंकड़े का यह मामला नहीं है। यह बात तय है कि हर दौर में यह कहा जाता है। कभी यह कहा जाता था कि एक दल की सरकार होने से स्टेबिलिटी होगी, बहुत से दल होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब वह मामला चला गया है, अब तो कोलीशन बनाना ही पड़ेगा। तो फिर आप कहते हैं प्रि-पोल और पोस्ट पोल, एक एक वक्त एक एक किस्म की थ्यौरी बनाई जाती है। उसमें हमारा कोई बहस का मामला नहीं है। लेकिन अब तो प्रेस में भी देख रहे हैं

कि संख्या इधर उधर से, जोड़-तोड़ करके भी इकट्ठी की जा सकती है और आपने अपनी नालायकी की बात तो तस्लीम कर ली है, हालांकि उत्तर प्रदेश का नाम नहीं कह रहा हूं ...(व्यवधान) मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यह शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं ...(व्यवधान) लेकिन यू०पी० में हमने देखा कि संख्या की इकट्ठा कर लेने से बहुत स्टेबिलिटी हो जाती है ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है। लोक सभा के चुनाव में भी आप देखें। अभी भी रहेंगे वे पता नहीं है कल्याण सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो सिर्फ संख्या के आधार पर अगर स्टेबिलिटी दिखी जाए तो यह गलत होगा, मैं यह कहना चाह रहा था।

दूसरी तरफ एक सरकार बनी है दिल्ली में। प्रधान मंत्री जी के बारे में लोगों ने कहा कि एक लहर सी बनी है सब जगह। लोगों ने चाहा कि ऐसे एक प्रधान मंत्री हों। लेकिन उनके अपने ही दल की सरकारें जहां थीं वहां स्टेबिलिटी बढ़ी या चली गयी? ऐसा हमने पिछले एक साल में देखा, इस चुनाव में भी देखा। आपके पास गुजरात, हिमाचल और यह झूलता हुआ उत्तर प्रदेश था। दिल्ली में आपने सरकार बनायी। इसका मतलब है कि जो कन्सेन्सस की बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं, कोशिश होने चाहिए कि सबको लेकर किस तरह से चला जाए और वह चलने की पहली शर्त यह होगी कि अलग-अलग रीजनल पार्टीज, अलग-अलग स्टेट्स की जो एस्पेरेशंस हैं जो आशाएं हैं उनको भी कार्यक्रमों में जगह देनी पड़ेगी। कन्फ्रेंटेशनिस्ट या डॉट-केयर, इस तरह से अगर मंत्रिमंडल चलाया जाएगा तो फिर वह चल नहीं सकता है। एक तो आपके अंदर जो लोग हैं, एन०डी०ए० के अंदर, सो-काल्ड नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, इसका कोआर्डिनेशन हो या जो भी हो, वह किस तरह से चलेगा? ...(व्यवधान) ठीक है वह देखा जाएगा 6-7 महीने में। मतलब इतना नहीं ...(व्यवधान) सदन के नेता कह रहे हैं कि पोप को आमंत्रित किया गया और जो फर्म एलाइज हैं, प्रोपोल एलाइज हैं उनके नेता यहां सदन में कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है कि सरकार ने दावत दी है या नहीं। यह जो गैप हो जाता है कम्युनिकेशन का यह एक बड़ी शक्ल भी ले सकता है ...(व्यवधान) मैं कम समय में बोलना चाह रहा हूं।

अब फेडरलिज्म की बात है। संघ का जो ढांचा है, हमारे जो पिलर्स हैं — मार्डन इंडिया की बात कही गयी, राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि हमारा 50 साल का रिपब्लिक का एक्सपीरियंस है और आने वाली सदी में, मिलेनियम में हम जा रहे हैं तो उसके जो बुनियादी पिलर्स हैं उसमें एक जो फेडरलिज्म, संघीय ढांचा है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप बड़ी पार्टी हैं और आपके जो एलाइज हैं उनकी भी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए क्योंकि सिर्फ तीन स्टेट्स में गवर्नमेंट हैं। जो पार्टिसिपेटिंग एलाइज हैं वे भी कहां हैं। नान-पार्टिसिपेटिंग एलाइज भी हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकतर राज्य जो हैं वे अलग-अलग पार्टियों के द्वारा परिचालित हैं और आपको सरकार चलाते समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा तभी इस देश की स्टेबिलिटी का सवाल आ सकता है।

इसी तरह से डेमोक्रेसी दूसरा हमारा पिलर है। यह जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं उनकी भी जो मर्यादा है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। राज्य सभा में आपका बहुमत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सभा को छोड़कर हम चलाएंगे। पिछले दौर में ही हमने यह देखा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको इसकी अच्छी जानकारी है। यह राज्य सभा काउंसिल आफ स्टेट्स है और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारा कांस्टीटयूशन और हमारा जो संघीय ढांचा है उसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। आप अगर इसको छोड़कर सोचेंगे कि चलो बाई पास के रूट से ले लेते हैं तो फिर

स्टेबिलिटी का सवाल नहीं रहेगा। संख्या रहने से भी लोक सभा में नहीं रहेगा। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।

तीसरा, हमारा सेक्युलरिज्म है — धर्मनिरपेक्षता जब पिछली बार भा०ज०पा० नेतृत्व की सरकार आई थी, गठबंधन की तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सेक्युलरिज्म अंग्रेजी में तो था लेकिन पता नहीं क्यों संघ परिवार को आपत्ति है धर्मनिरपेक्षता शब्द में तो जब हिंदी में इसका अनुवाद हुआ तो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म ही रखा गया। मतलब उसमें दूसरा कोई हिंदी नहीं होता है क्योंकि यह शब्द भारतीय परंपरा के साथ नहीं है ऐसा कहा गया। इस बार मैंने देखा कि उससे थोड़ा आगे बढ़े हैं और पंथनिरपेक्षता यह हिंदी में कहा गया है। जो भी आप कहें जिस तरह से भी कहें लेकिन जो अलग-अलग संप्रदाय के लोग हैं, धर्म विश्वास के लोग हैं उनके प्रति आप ...(**व्यवधान**) अभी जेनुइव वे नहीं कह रहे हैं। इनजेनुइन, जेनुइन कुछ नहीं कह रहे हैं, पंथनिरपेक्षता कह रहे हैं। जो भी कहें लेकिन जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है और उसमें अलग-अलग धर्म विश्वास के जो समुदाय हैं। उनकी जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने की जम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी और सरकार के जो पार्टियों के पिल्लर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पिल्लर्स हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिन्दू परिषद् हो, जिनको आपने पिछले दस साल गवारा किया, 2 से 182 आने में और जो सेंटीमेंट्स तथा इमोशंस को आपने गवारा किया, तो उनकी रास भी आपको पकड़ कर रखनी पड़ेगी। ...(**व्यवधान**) नहीं, मैंने तमाम को कहा, संघ परिवार कहा तो उसका जो है वह घोड़े पर चढ़ना आसान है, लेकिन घोड़े की लगाम को कस कर पकड़ना और भी ज्यादा जरूरी है। उसे आप पकड़ेंगे और सही ढंग से चलायेंगे, यह मैं आपसे अनुरोध करूंगा, वरना फिर तो हम लोग हैं ही। फिर हम लगाम पकड़ेंगे।

तीसरी बात, रेफॉर्म्स के बारे में है, उदारीकरण के बारे में है। यहां पर मैं तो दस साल से हूं और संघ प्रिय गौतम जी आप भी पुराने हैं। हमने स्वदेशी-स्वदेशी बहुत सुना। आपके चार भाषण देने वालों में से पहले तीन तो स्वदेशी भाषा में बोले ही नहीं, इस सदन में जब मैं पहले आया था तो पहले भाषा के बारे में बहुत कहा जाता था और भाषा के बारे में सवाल भी उठाया जाता था, लेकिन अभी शायद एक्सैप्टेंस बढ़ गया है। चार में से तीन तो अंग्रेजी भाषा में बोले और एक हिन्दी में बोले। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मलकानी जी ने भाषण शुरू किया बिल क्लिंटन के भाषण से। मतलब यह हमारी आशंका की बात है। यहां पर इस भाषण में यह कहा गया कि हमारा एक कंसेंसस है। फॉरेन अफेयर्स में एक नेशनल कंसेंसस है। ...(**व्यवधान**) जो हमारी विदेशी नीति के बारे में पिछले एक-डेढ़ साल में कुछ तोड़-मरोड़ देने की कोशिश की गई, लेकिन आने वाले दिनों में आज की बदली हुई स्थिति में आप ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी हालत में जबकि राज्य सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हैं और यहां आपके अंदर, आपके नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के अंदर अलग-अलग दिशा के लोग हैं। दो सदनों में से एक सदन के अंदर आपका बहुमत नहीं है और उस जगह पर आप कंसेंसस बनाने की बजाय तोड़ेंगे तो वह बहुत घातक होगा। यह चेतावनी मैं शुरू से ही देना चाहता हूं। इसी तरह से रेफॉर्म्स के बारे में भी है। आपने खुद कहा है, सराहा है, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और यह कभी नहीं करेंगे। आपके मंत्री अलग-अलग जा करके कह रहे हैं। बिहार में जा करके कह रहे हैं कि हम टूरिज्म में प्राइवेट पार्टिसिपेशन करायेंगे, एन०जी०ओज़ का पार्टिसिपेशन करवायेंगे। कोई मंत्री बंगाल में जा कर कह रहे हैं कि रेल में हम प्राइवेट सैक्टर्ज़ पार्टिसिपेशन करवायेंगे, एन०जी०ओज़ का पार्टिसिपेशन करायेंगे। अगर

प्राइवेट सैक्टर के पास ही इतनी दौलत होती कि वह आपकी सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए आपको ला करके देता तो फिर आपको विदेशी निवेश के लिए रोज़ाना 365 दिन के अंदर 360 दिन विदेश में जा करके काटने नहीं पड़ते और कहना नहीं पड़ता कि आप पूंजी निवेश करो। उसके लिए आपकी पूरी नीति है और आपकी जो स्वः निर्भर अर्थ नीति है उसमें इस तरह से दरार पैदा नहीं करनी पड़ती और उसे चरमरा करके तोड़ना नहीं पड़ता कि हमको विदेशी के पूंजी के निवेश की जरुरत है। कहां से फंड आयेगा वह तो आपको देखना पड़ेगा। आपने कहा डाउनसर्ज इन द एक्सपेंडीचर ऑफ् गवर्नमेंट, सरकार के खर्चों में कमी आयेगी और इसी भाषण में यह है कि कितने नए विभाग खोले गए। आपने कहा कि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, लेकिन पूरे देश को पता है कि अलग-अलग दल जो नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस में आपके साथ आए हैं, उनमें से कुछ लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन कल अगर वे भी कहें कि हम सरकार में हिस्सा लेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश वाले हैं अगर कल बदल करके कहें कि हम हिस्सा लेंगे या हरियाणा वाले कहें कि हम हिस्सा लेंगे तो फिर आपको और भी बहुत से विभाग खोलने पड़ेगे। ...**(व्यवधान)** हां, और भी विभाग खोलने पड़ेगे और फिर आप अपने भाषण में यह कहेंगे कि कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, एफीसिंएसी बढ़ाने के लिए तो नए-नए विभाग आप खोल रहे हैं सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए।....**(व्यवधान)**

**श्री नीलोत्पल बसु:** समेटने के लिए।

**श्री मोहम्मद सलीम:** मंत्री को समेटने के लिए या मंत्री द्वारा समेटने के लिए। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं...**व्यवधान)** यह एक कंट्राडिक्शन है। सरकार कुछ द्वंद्व से शुरू हुई है। इस द्वंद्व की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो यहां बहुत नेक इरादे की बात कही गई है, बहुत नेक इरादे कहा गया है, आपके पालिसी मैटर्स 50 साल और आने वाले 1000 साल में हमारे देश में क्या होना चाहिए वह भी इसमें है, एक मिलियेनियम के लिए भी क्या-क्या होना चाहिए, यह आल पायस जो डिज़ायर्स हैं वह सब इसमें हैं, लेकिन जो ठोस कार्यक्रम हम चाह रहे हैं, वे नहीं हैं। इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पिछले भाषण में भी थीं और उसके बाद सरकार चलाई गई। लेकिन उसे लागू करने की जो बात है आप अगर उसी तरह से देखें, और अगर मैं छोटी-मोटी मिसाल दूं, जैसे लोक पाल बिल, सैन्ट्रल विजिलैंस कमीशन के बारे में बिल, महिलाओं के लिए 33 परसेंट आरक्षण के बारे में बिल। इस बार प्रसार भारती के बारे में आप ने नहीं कहा जबकि पिछली बार कहा था और पहला शब्द था कि हम प्रसार भारती को मजबूत करेंगे। लेकिन हम ने 13 महीने देखा कि प्रसार भारती के स्वशासन को किस तरह से मरोड़ा गया। मंत्रियों को बदला गया, लेकिन बोर्ड नहीं बदला गया और राज्य सभा में बिल, भी नहीं लाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे राजनीतिज्ञ जनता के सामने विश्वसनीयता खो रहे हैं, आप राष्ट्रपति जैसे ओहदे को क्यों इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आप करना नहीं चाहते हैं, जो आप के इरादे नहीं हैं, वह सब आप सिर्फ भाषण देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ने इस बार प्रसार भारती के बारे में क्यों नहीं कहा जबकि पिछली बार आप ने प्रसार भारती के बारे में बहुत लंबी-चौड़ी बात की थी आप ने दो मिलियन हाउसेस के बारे में कहा है जोकि पिछली बार भी कहा गया था। एक करोड़ बेरोजगारों को नौकरी के बारे में पिछली बार भी कहा गया था, इस बार भी कहा है आप की विश्वसनीयता बढ़ जाती अगर आप कहते कि हम ने एक करोड़ नहीं 80 लाख कर दिए, 80 लाख नहीं 30 लाख कर दिए और अब हम एक करोड़ करेंगे। हम 20 लाख हाउसेस नहीं कर पाए, लेकिन 2

लाख, 4 लाख, 5 लाख किए हैं और अब की बार 20 लाख करेंगे। इस में यह नहीं है जोकि होना चाहिए था। इसी तरह से आप ने एक के बाद एक कमीशंस , कमेटीज, टासक फोर्स की घोषणा कर दी है। तो सिर्फ मंत्री ही नहीं, डेमोक्रेटिक एलाइंस में और भी डेमोक्रेटिक एस्पेरेशंस है जिस में आप को बहुत से मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर की तरह टास्क फोर्स के चैयरमैन बनाने पड़ेंगे। इस तरह आप ने यह भी घोषणा कर दी है कि बहुत-सी वकैंसीज हैं बेरोजगारों के लिए, लेकिन जो मुख्य सवाल है, वह यह है कि आप साधन कहा से जुटाएंगे, इस बारे में एक भी शब्द नहीं है।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** सांसदों का 20 हजार कर लिया, कहां से आ गया पैसा?

**श्री मोहम्मद सलीम:** तो महोदय हमें हताशा ही हुई है। हम चाह रहे थे कि नए मिलेनियम की शुरूआत में जैसे राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि एक नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसी तरह से एक नई दिशा में नई सरकार एक ठोस कार्यक्रम लेकर जनता के सामने उसे विश्वास दिलाने के लिए हम सब मिलकर सहमति के आधार पर नए युग की शुरुआत करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस में वही पुरानी कहीं हुई, सुनी हुई बातें और लफ्फाजी है। यह सरकार का दोष है कि उस ने जो पुराने वायदे थे, उन को पूरा नहीं किया और फिर से इस अभिभाषण में डाल दिया। उस ने एक भी कार्यक्रम के बारे में कोई ठोस एक्शन प्लान या टाइम-बांउड प्रोग्राम नहीं रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस बारे में कोशिश करेगी और जो विरोधी पक्ष की राय है, उस को महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में समेटकर राष्ट्र के सामने उजागर करेगी। धन्यवाद।

†[شری محمد سلیم "مغربی بنگال": اپ سبھا ادھیکش
مہودے، دو روز سے راشٹرپتی کے ابھی بھاشن پر یہاں چرچا ہو
رہی ہے۔ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں میں انکو دہرانا نہیں چاہونگا۔
یہاں پر ایک سوال اسٹیبلیٹی کے بارے میں اٹھا ہے، استحکام کے
بارے میں اٹھا ہے۔ پچھلے کئی چناؤ میں بھی یہ سوال اٹھتا رہا ہے،
اور اس بار بھی یہی کہا گیا ہے۔ لیکن صرف ۱۸۱ سے ۱۸۲ ہو جانے سے
انسٹیبلٹی ختم ہوکر اسٹیبلٹی آجاتی ہے۔ ایسے آنکڑوں کا
یہ معاملہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر دور میں یہ کہا جاتا ہے، کبھی یہ کہا
جاتا ہے کہ ایک دل کی سرکار ہونے سے اسٹیبلٹی ہوگی، بہت سے
دل ہونگے تو اسٹیبلٹی نہیں رہے گی۔ اب وہ معاملہ چلا گیا ہے،
اب تو کولیشن بنانا ہی پڑے گا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں پری پول اور پوسٹ

†[ ] Translitration in Persian script.

پول، ایک ایک وقت میں ایک ایک قسم کی مجبوری بنائی جاتی ہے۔
اسمیں ہمارا کوئی بحث کا معاملہ نہیں ہے لیکن اب تو پریس میں بھی
دیکھ رہے ہیں کہ تعداد ادھر ادھر سے، جوڑ توڑ کر کے بھی اکٹھی کی جا
سکتی ہے اور آپ نے اپنی نالائقی کی بات تو تسلیم کر لی ہے، حالانکہ
اتر پردیش کا نام نہیں کہہ رہا ہوں۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔ میں نہیں کہہ
رہا ہوں۔ میں یہ شبد نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ "مداخلت"۔۔
۔۔۔ لیکن یو۔پی میں ہم نے دیکھا کہ تعداد کو اکٹھا کرنے سے بہت ابیٹ بھی
ہو جاتی ہے۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔ ایسا نہیں ہے۔ لوک سبھا
کے چناؤ میں بھی آپ دیکھیں گے۔ ابھی بھی رہیں گے وہ پتہ نہیں
ہے۔ کلیان سنگھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہونگے یا نہیں ہونگے۔
تو صرف تعداد کے آدھار پر اگر اسٹیبلٹی گنی جائے تو یہ غلط ہوگا،
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک سرکار بنی ہے دہلی
میں۔ پردھان منتری جی کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ایک
لہر سی بنی ہے سب جگہ۔ لوگوں نے چاہا کہ ایسے ایک پردھان
منتری ہوں۔ لیکن انکے اپنے ہی دل کی سرکاریں جہاں تھیں
وہاں اسٹیبلٹی بڑھی یا چلی گئی؟ ایسا ہم نے پچھلے ایک سال
میں دیکھا، اس چناؤ میں بھی دیکھا۔ آپ کے پاس گجرات، ہماچل
اور چھوٹا سا اتر پردیش تھا۔ دہلی میں آپ نے سرکار بنائی ہے اسکا
مطلب ہے کہ جو کنسینسس کی بات کر رہے ہیں، اسکی کوشش ہونی
چاہیئے کہ سب کو لے کر کس طرح سے چلا جائے، اور وہ چلنے کی پہلی شرط
یہ ہوگی کہ الگ الگ ریجنل پارٹیز الگ الگ اسٹیٹ کی جو آشائیں
ہیں انکو بھی پروگراموں میں جگہ دینی پڑے گی۔ کنفرنٹیشنسٹ
یا ڈومی نیٹ کرنے کا اسطرح سے اگر منتری منڈل چلایا جائے گا تو پھر
وہ چل نہیں سکتا۔ ایک تو آپ کے اندر جو لوگ ہیں، این۔ڈی۔

اے - کے اندر "سو کالڈ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس" اسکا کوآرڈی
نیشن ہو یا جو بھی ہو وہ کس طرح سے چلے گا ... "مداخلت" ... ٹھیک
ہے وہ دیکھا جائے گا - ۶ - ۷ - مہینے میں - مطلب اتنا نہیں ... "مداخلت"
سدن کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ یو پی کو آمنترت کیا گیا اور جو فرم الائز ہوا،
پری پول الائز ہیں انکے نیتا یہاں سدن میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم
نہیں ہے سرکار نے دعوت دی ہے یا نہیں - یہ جو گیپ ہو جاتا ہے
کمیونیکیشن کا یہ ایک بڑی شکل بھی لے سکتا ہے ... "مداخلت" ...
میں کم وقت میں بولنا چاہ رہا ہوں -

اب فیڈرل ازم کی بات ہے - سنگھ کا جو ڈھانچہ ہے، ہمارے
جو پلرس ہیں ... ماڈرن انڈیا کی بات کہی گئی، راشٹرپتی جی
نے بھی کہا کہ ہمارا ۵۰ سال کا ریپبلک کا تجربہ ہے آنے والی
صدی میں ملینیم میں ہم جا رہے ہیں تو اسکے جو دو بنیادی پلرس
ہیں اسمیں ایک جو فیڈرلزم سنگھیہ ڈھانچہ ہے اسکو آپ کو دھیان
میں رکھنا پڑے گا - آپ بڑی پارٹی ہیں اور آپ کے الائز ہیں انکی
بھی ریسپیکٹ رکھنی چاہیئے، کیونکہ صرف تین اسٹیٹ میں گورنمنٹ ہے -
جو پارٹی سپورٹنگ الائز ہیں وہ بھی کہاں ہیں - نان پارٹی سپورٹنگ الائز
بھی ہیں لیکن اسکا دھیان رکھنا پڑیگا کہ زیادہ تر راجیہ جو ہیں وہ
الگ الگ پارٹیوں کے ذریعہ پرچالت ہیں اور آپ کو سرکار چلاتے
وقت اسکا دھیان رکھنا پڑیگا تبھی اس ملک کے استحکام کا
کا سوال آسکتا ہے -

اسی طرح سے ڈیموکریسی دوسرا ہمارا پلر ہے یہ جو پارلیمنٹری
ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹ کے جو دونوں سدن ہیں انکی بھی جو مریادہ ہے
اس پر بھی دھیان رکھنا پڑے گا - راجیہ سبھا میں آپ کا بہومت نہیں ہے
اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ راجیہ سبھا کو چھوڑ کر ہم چلا لیں گے پچھلے دور

میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے۔ آپ سبھا ادھیکش ہو دے آپ کو اسکی اچھی جانکاری ہے یہ راجیہ سبھا کاؤنسل آف اسٹیٹس ہیں اور ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہمارا کانسٹی ٹیوشن اور ہمارا جو سنگھیہ ڈھانچہ ہے اس کا ایک اہم ستون ہے۔ آپ اگر اسکو چھوڑ کر سوچیں گے کہ چلو باگی پاس کے روش سے بیٹھے ہیں تو پھر اسٹیبلٹی کا سوال نہیں رہے گا تو ادریش سے بھی لوگ سبھا میں نہیں رہے گا اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑیگا۔

تیسرا ہمارا سیکولرزم ہے۔ دھرم نرپیکشتا۔ جب پچھلی بار بھاجپا کی قیادت میں سرکار آئی تھی گٹھ بندھن کی تو راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں سیکولرزم انگریزی میں تو تھا لیکن پتہ نہیں کیوں سنگھ پریوار کو آپتی ہے دھرم نرپیکشتا شبد میں تو جب ہندی میں اسکا ترجمہ ہوا تو سیکولرزم کو سیکولرزم ہی رکھا گیا۔ مطلب اسمیں دوسرا کوئی ہندی نہیں ہوتا کیونکہ یہ شبد بھارتیہ پرمپرا کے ساتھ نہیں ہے ایسا کہا گیا۔ اس بار میں نے دیکھا کہ اس سے تھوڑا آگے بڑھے ہیں اور پنتھ نرپیکشتا یہ ہندی میں کہا گیا ہے جو بھی آپ کہیں جس طرح بھی کہیں لیکن جو الگ الگ سمپردائے کے لوگ ہیں دھرم وشواس کے لوگ ہیں ان کے پرتی آپ ۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔ ابھی جیٹون وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان جیٹون، جیٹون کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، پنتھ نرپیکشتا کہہ رہے ہیں، جو بھی کہیں لیکن جو ہماری دھرم نرپیکشتا ہے اور اس میں الگ الگ دھرم وشواس کے جو سمپردائے ہیں ان کی جو آشنکائیں ہیں انہیں دور انہیں دور کرنے کی ذمہ داری سرکار کو لینی پڑے گی اور سرکار کے جو پارٹنرس کے ستون ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو ستون ہیں چاہے بجرنگ دل ہو، چاہے وشو ہندو پریشد ہو، جن

کو آپنے پچھلے دس سال گوار اگیا ۲ سے ۱۸۲ آنے میں اور جو سینٹی مینٹس کو آپ نے گوارا کیا تو انکی ۔ اس بھی آپکو پکڑ کر دیکھنی پڑے گی۔ ۔۔۔ "مداخلت"۔۔ ۔ پنس میں نے تمام کو کہا ہے سنگھ پریوار کو کہا تو اسکا جو ہے وہ گھوڑے پر چڑھنا آسان ہے، لیکن گھوڑے کی لگام کو کس کر پکڑنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، اسے آپ پکڑیں گے اور صحیح ڈھنگ سے چلائیں گے، یہ میں آپ سے انورودھ کرونگا ورنہ پھر تو ہم لوگ ہیں ہی، پھر ہم لگام پکڑیں گے۔

تیسری بات ریفارمس کے بارے میں ہے آدادی کرن کے بارے میں ہے ۔ یہاں پر میں تو دس سال سے ہوں اور سنگھ پریہ گوتم جی آپ بھی پرانے ہیں، ہم نے سود یشی و دیشی بہت سنا۔ آپ کے چار بھاشن دینے والوں میں سے پہلے تین تو سودیشی بھاشا میں بولے ہی نہیں۔ اس سدن میں جب پہلے آیا تھا تو پہلے بھاشا کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا تھا اور بھاشا کے بارے میں سوال بھی اٹھایا جاتا تھا، لیکن ابھی شاید ایکسپٹنس بڑھ گیا ہے۔ چار میں سے تین تو انگریزی بھاشا میں بولے اور ایک ہندی میں بولے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ملکانی جی نے بھاشن شروع کیا بل کلنٹن کے بھاشن سے، مطلب یہ ہماری آشنکا کی بات ہے، یہاں پر اس بھاشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ایک کنسینسس ہے، فارن افیئرس میں ایک نیشنل کنسینسس ہے فارن افیئرس میں ایک نیشنل کنسینسس ہے ۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔ جو ہماری ودیشی نیتی کے بارے میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں کچھ توڑ مروڑ دینے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسی حالت میں جبکہ راجیہ سرکاریں الگ الگ پارٹیوں کی ہیں اور یہاں آپ کے اندر آپ کے نیشنل ڈیمو کریٹک الائنس کے اندر الگ الگ وشنا کے لوگ ہیں ۔ دو سمونوں

میں سے ایک سدن کے اندر آپ کا بہومت نہیں ہے اور اس جگہ

پر آپ کنسینسس بنانے کی بجائے توڑیں تو وہ بہت گھاتک ہوگا - یہ چیتاونی میں شروع سے ہی دینا چاہتا ہوں - اسی طرح سے رفارم کے بارے میں بھی ہے - آپ نے خود کہا ہے، سدرا ہا ہے، شکشا کے بارے میں، سواستھ کے بارے میں اور یہ کبھی نہیں کریں - آپ کے منتری الگ الگ جا کر کہہ رہے ہیں - بہار میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹورزم میں پرائیویٹ پارٹیسپیشن کرائیں گے - کوئی منتری بنگال میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ریل میں ہم پرائیویٹ سیکٹرز پارٹیسپیشن کروائیں گے، این جی اوز کا پارٹیسپیشن کروائیں گے - کوئی منتری بنگال میں جا کر کہہ رہا ہے کہ ریل میں ہم پرائیویٹ سیکٹرز پارٹیسپیشن کروائیں گے، این جی اوز کا پارٹیسپیشن کروائیں گے - اگر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہی اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ آپکی سرکار کی جو ذمہ داری ہے اسے نبھانے کے لئے آپ کو لا کر کے دیتا تو پھر آپکو ودیشی نویش کے لئے روزانہ ۳۶۵ دن کے اندر ۳۶۰ دن ودیشوں میں جا کر کے گھومنے نہیں پڑتے اور ارتھ نیتی ہے اس میں اس طرح سے درار پیدا نہیں کرنی پڑتی اور اسے جرجر کر کے توڑنا نہیں پڑتا کہ ہم کو ودیشی نویش کی ضرورت ہے - کہاں سے فنڈ آئیگا وہ تو آپکو دیکھنا پڑیگا - آپ نے کہا ڈاؤن سرزان دی ایکسپینڈیچر آف گورنمنٹ، سرکار کے خرچوں میں کمی آئیگی اور اسی بھاشن میں یہ ہے کہ کتنے منتری وبھاگ جوڑے گئے - آپ نے کہا کہ کارڈ کے کسانا بڑھانے کے لئے ہیں، لیکن پورے دیش کو پتہ ہے کہ الگ الگ دل جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس میں آپکے ساتھ آئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ حصہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن کل

اگر وہ بھی کہیں کہ ہم سرکار میں حصہ لیں گے تو پھر آپ کو اور
بہت سے شعبے کھولنے پڑیں . . . "مداخلت" . . . ہاں اور بھی شعبے
کھولنے پڑیں گے اور پھر آپ اپنے بھاشن میں یہ کہیں گے کہ کاریہ
کشلتا بڑھ جانے کے لئے، افیشنسی اینسی بڑھانے کے لئے تو نئے نئے
وبھاگ آپ کھول رہے ہیں صرف منتریوں کی تعداد بڑھ جانے کے لئے . .
. . . "مداخلت" . . .

شری نیلوتپل بسو: سمیٹی کے لئے ۔
شری محمد سلیم: منتری کے سمیٹی کے لئے یا منتری کے ذریعہ
سمیٹی کے لئے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں . . . "مداخلت" . . . یہ
ایک کنٹراڈکشن ہے ۔ سرکار کچھ دونوں سے شروع ہوئی ہے، اس دونو
کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک طرف تو یہاں بہت نیک ارادہ
کی بات کہی گئی ہے۔ بہت نیک ارادہ کہا گیا ہے، آپکی پولیسی میٹرس
پچاس سال اور آنے والے سو سال میں ہمارے دیش میں کیا ہونا
چاہیے، وہ بھی اس میں ہے ایک ملینیم کے لئے بھی کیا کیا ہونا چاہیے
یہ "آل پائنٹس" جو ڈیزائرس ہیں وہ سب اس میں ہیں لیکن جو
ٹھوس پروگرام ہم چاہ رہے ہیں اس میں نہیں ہیں ۔ اس میں ایسی
بہت سی چیزیں ہیں جو پچھلے بھاشن میں تھیں اور اسکے بعد سرکار
چلی گئی، لیکن اسے لاگو کرنے کی وجوہات سے آپ اگر اسی طرح سے
دیکھیں اور اگر میں چھوٹی سی مثال دوں جیسے لوک پال بل،
سینٹرل ویجیلنس کمیشن کے بارے میں بل، خواتین کے لئے ۳۳ فیصد
ریزرویشن کے بارے میں بل، اس بار پرسار بھارتی کے بارے میں
آپ نے نہیں کہا جبکہ پچھلی بار کہا تھا اور پہلا سنسد تھا کہ ہم پرسار

بھارتی کو مضبوط کریں گے لیکن ہم نے ۱۳ مہینے دیکھا کہ پرسار بھارتی کے سوشاشن کو کس طرح سے مروڑا گیا - منتریوں کو بدلا گیا لیکن بورڈ نہیں بدلا گیا اور راجیہ سبھا میں بل بھی نہیں لایا گیا - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے سیاسی لوگ عوام کے سامنے

اعتماد کھو رہے ہیں آپ راشٹرپتی جیسے عہدے کے کیوں اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ جو آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو آپ کے ارادے نہیں ہیں - وہ صرف آپ سب بھاشن دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس بار پرسار بھارتی کے بارے میں کیوں نہیں کہا جبکہ پچھلی بار آپ نے پرسار بھارتی کے بارے میں بہت لمبی چوڑی بات کی تھی - آپ نے دو ملین ہاؤسز کے بارے میں کہا ہے جو کہ پچھلی بار بھی کہا گیا تھا - ایک کروڑ بے روزگاروں کو نوکری کے بارے میں پچھلی بار بھی کہا گیا تھا اس بار بھی کہا ہے - اعتماد بڑھ جاتا اگر آپ کہتے کہ ہم نے ایک کروڑ نہیں ۸۰ لاکھ کر دیے، ۸۰ لاکھ نہیں ۳۰ لاکھ کر دیے اور اب ہم ایک کروڑ کریں گے - ہم ۲۰ لاکھ ہاؤسز نہیں کر پائے، لیکن دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کیے ہیں -

اور اب کی بار ۲۰ لاکھ کریں گے اس میں یہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا - تو گو پہلے اسی طرح سے ایک کے بعد ایک کمیشن، کمیٹی، ٹاسک فورس کا اعلان کر دیا ہے - تو صرف منتری ہی نہیں ڈیموکریٹک الائنس میں ایسپیریشن ہے، تو صرف منتری ہی نہیں جس میں آپ کو بہت سے منسٹر، اسٹیٹ منسٹر کی طرح ٹاسک فورس کے چیئرمین بنانے پڑیں گے - اس طرح آپ نے یہ بھی گھوشنا کر دی ہے کہ بہت سی ویکینسیز ہیں بے روزگاروں کے لیے، لیکن جو خاص سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سادھن کہاں سے جٹائیں گے، اس بارے میں ایک بھی شبد نہیں ہے -

شری سنگھ پریہ گوتم: سانسدوں کا ۲۰ ہزار کر دیا، کہاں سے آگیا پیسہ۔

شری محمد سلیم: تو مہودے، ہمیں مایوسی ہوئی، ہم چاہ رہے تھے کہ نئے ملینیم کی شروعات میں جیسے راشٹرپتی مہودے نے کہا ہے کہ ایک نئے منتری منڈل کا گٹھن ہوا ہے، اس طرح سے ایک نئی دشائیں، نئی سرکار ایک ٹھوس کاروکرم لیکر جنتا کے سامنے ایسے وشواس دلانے کے لئے ہم سب ملکر سہمتی کے آدھار پر نئے یگ کی شروعات کریںگے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، اسمیں وہی پرانی گھسی پٹی باتیں اور لفاظی ہے۔ یہ سرکار دوش ہے کہ اس نے جو پرانے وعدے تھے، انکو پورا نہیں کیا اور پھر سے اس ابھی بھاشن میں ڈال دیا۔ اس نے ایک بھی پروگرام کے بارے میں کوئی ٹھوس ایکشن پلان یا ٹائم باؤنڈ پروگرام نہیں رکھا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آنے والے دنوں میں سرکار اس کے بارے میں کوشش کرے گی اور جو ورودھی پکش کی طرف سے دئے ہے، اس کو مہامہم کے بھاشن کے دھنیواد پرستاؤ میں سمیٹ کر راشٹر کے سامنے اجاگر کرے گی۔ دھنیواد۔

["ختم شد"]

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice Chairman, Sir. the President, in his Address, has carried out a very comprehensive and detailed survey of what the Government proposes to do in the forthcoming administration. In his Address, tribute has been paid to our officers and soliders who have made a supreme sacrifice in Kargil. It has also been mentioned that the Kargil conflict has also underlined the need for modernization of our defence forces. I wish to say that independent India has a long histroy of neglect and sidelining of our armed forces. This has generated an unhealthy degree of skepticism and cynicism within the armed forces. Almost all the Governments since independence have made promises, but they have not kept those promises. It is not good for the armed forces. It

is not good for the nation because it adds fuel to the feeling that God and soliders are remembered only in times of need, and thereafter they are forgotten. Kargil'99 is merely symbolic. Four hundred and sixty-two officers and men have been killed. I am going by newspaper figures. They may or may not be accurate. Six hundred and eighty-four officers and men were injured earlier. I would like to state that these figures are symbolic because this is the fifth time that Indian Army and the Indian Air Force have fought at this very place in Kargil. The first was in 1948, then twice in 1965 and the fourth time was in 1971. In 1999, it was the fifth time that our forces have fought the same enemy at the same place, that is, at Kargil. India achieved Independence on 15th August, 1947. The Indian Army and Air Force was in action in Kashmir within three months, that is, on 27th October, 1947 and, since them they have fouth three general wars with Pakistan; one general war with China; and an almost continuous succession of insurgencies, proxy wars and internal security operations. A saying has come up in the Army that the nation has been at peace, but the Army has always been at war. As a resul. of this, in addition to the figures that I have quoted in regared to Kargil, which, I say, are only symbolic, since 1947, the Defence Forces have lost in the neighbourhood of approximately twenty thousand soliders and about three times that number have been injured. One hopes this Government will honour the promises it has made because armies, navies and air forces are not created overnight. They require time, they require money, they require attention, they require dedication and I would like to say that they also require love. The defence expenditure has been a subject about which all parties have said that it should be reduced. This is logical, but I am afraid it is not applicable to our country because we live in a very unstable and dangerous part of the world. It is incorrect to view defence expenditure as a mere question of defence versus development; rather, I think, we must reorient our outlook and visualise defence expenditure more in the nature of a life insurance for the nation. It has to be paid. The Govenrment must make up its mind to devote three per cent of the G.D.P. to defence, on a sustained basis. The defence forces also base their development on a series of Five Year Plans, internally drawn up, internally scrutinised, internally presented. For example, the 8th plan was from 1992-97 and the 9th defence plan is, hopefully, in progress from 1997, which will last till 2002. But I regret to say, Mr. Vice-Chairman, that our defence plan has been a total farce because finances have neither been adequately allotted, nor have they been allotted on an on-going basis.

I now come to the question of civilian control over the defence forces. Civilian control over the defence forces is the very basis of a democratic system, and it is the basis of the democracy that we run in India also. But I am afraid civilian control of the armed forces pertains to civilian, political

control. It has been aberrated, it has been distorted, in our country to mean civilian bureaucratic control and there is a great deal of heart-burning within the Services on this issue. This is not good for our armed forces, is not good for our country, is not good for our Government.

This must be corrected by giving the Armed Forces their requisite say is decision-making in departmental matters of defence as well as in national security. The present Government in its previous incarnation, if I may use the word, had proposed the integration of the Service Headquarters with the Ministry of Defence so that the Defence Forces would have a direct say in decision-making on the Armed Forces. I would urge upon the Government, when they develop the defence planning further, to see that this plan is put into execution.

Procurement procedures for equipment must be simplified and revised, because these procedures take an unusually and unduly long time to finalise. The price of an equipment, which is contracted for at a particular period of time, by the time the procedural formalities are completed, increases manifold. We speak of inflation. Seven per cent inflation is the usual figure, but as far as defence equipment is concerned, inflation figures are more, in the region of 20 to 30 per cent a year. So, if we think of acquiring a piece of equipment in one year, if our decision-making process takes three years, 5 years, 10 years or 15 years, by the time we agree to accept that equipment, the whole price is beyond our reach.

I have recently read in the papers that the Government has decided to acquire new equipment for the Army and the Navy. without going into the details, may I say that procurement of these equipments were proposed five to ten years ago. And now, under the impetus of the Kargil operations, under the impetus of the Kargil blood-letting, we have now suddenly woken up and have decided to import these equipments. This is not a new story. it has been happening since 1962. After every war we have fought, similar pious sentiments have been expressed and, after a while, they have been quietly forgotten.

Structured plans for acquisition of equipment are drawn up, are ignored, are delayed, until there is an operation, men get killed, officers get killed, and then, suddenly, there is a rush to spend money to acquire equipment. This must not happen in future.

The proposed integration of the Ministry of Defence and the Service Headquarters must be done on principles of modern management. They are top heavy; they are unwieldy and they must be restructured to enable a fast, quick and a streamlined modern decision-making.

The National Security Council has been established, but I do note there is a grievous omission. The National Security Council, incidentally, is not a new idea. It was there is 1947, when Lord Louis Mountbatten, the first Governor-General, proposed a Cabinet Committee on Defence, in which the then Prime Minister, the then Defence Minister, the Home Minister and other Ministers were part of. In that Committee, the three Chiefs were Attending Members. I notice that in the National Security Council, as presently constituted by the present Government, the three Chiefs are not Attending Members. I think this lacuna should be removed.

The Arun Singh Committee Report, which was formulated sometime in 1980, has been gathering dust. I am aware of the contents, but since it is a matter of detail, I would not like to go into it here. The Arun Singh Committee Report must be studied and implemented.

As far as indigenisation of the equipment is concerned, the Defence Research and Development Organization plays a very major role in this. Allocation to the DRDO must be increased. I would like the Government to ensure that the DRDO is also held accountable and responsible for the progress of the various experimental measures that they are taking so that we have, at the end of their efforts, something tangible on the ground. We had a long history of projects which have gone on almost permanently; at the end of it, the desired equipment is still nowhere in sight. Defence production factories, ordnance factories, defence public sector units, must have similar norms of accountability These norms should be imposed upon them. They must be made to understand that what our Armed Forces require is good equipment at compatible prices, of a compatible quality, in a compatible time. With that, I will conclude my statement this evening, by thanking the President for his Address. Thank you, Sir.

SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated): Mr Vice-Chairman, Sir, thank you very much. I want to draw your attention, the attention of the House, and the attention of he country, to the diplomatic aspects of the Kargil opeation. I want to commend the Prime Minister for having led the whole thing with sagacity and restraint and we have come out very successfully. I want to know about the meetings between Mr. Niaz Naik and Mr. Misra. There were about five visits to Pakistan and to India. We do not know what was behind them. It has been said that they had the official blessing. But what was it about? I am told this was part of the agreement reached in Lahore. The House, the nations does not know about it. What was it? It has been said that Mr. Nawaz Sharief had paid the price? Is it so? The information is that he has been beaten up two or three days ago. I am sure that the Government is aware of that. If Mr. Nawaz Sharief has paid the

price for trying to reach an agreement with Vajpayeeji, then, don't we have any duty?

I would like to know whether it is a fact that Mr. Clinton, President of the U.S.A. was very emphatic that we should talk to the military Government in Islamabad. Our Prime Minister has very rightly rejected it. But is it a fact that there is a pressure that we must talk to Gen. Musharraf? As our Foreign Minister had said earlier, there will be no talks with Pakistan until they end the cross-border terrorism. Unless there is some kind of a democratically-elected Government the, we cannot talk. Now whom should we talk to? This takes me to the question on our side of Kashmir. Sir, Pakistan has taken itself out of purview. But we must do something on our side of Kashmir. Kashmir is Kashmir. There were allegations from very responsible persons. Two former Union Ministers, Mufti Saheb and Soz Saheb, have stated that the elections in Kashmir were rigged. If that is so, what has been done? Don't we have any duty? I personally think, this matter calls for the appointments of a parliamentary committee to go into these allegations.

Let us talk to the people in Kashmir because it is very important. We are not after the territory, we are wanting the people of Kashmir with us. And this Parliamentary Committee may be able to know what is happening there. The TADA which does not exist in the rest of the country is still operating in Kashmir and people are detained without any rhyme or reason. From all sources it is clear that, the administration in the state exists only on paper and it does not exist on the ground. Don't we owe any duty to that part? When we are enjoying democracy in the country, should not the people of Jammu and Kashmir also enjoy democracy? It is no use only sending forces. Maybe you have to deal with terrorism, but I am reminded of an incident. One Chief Minister of Jammu and Kashmir—who is now dead—came to New Delhi to talk to the Prime Minister of that time here—also dead—and said, "I want two factories or two public sector undertakings in Kashmir". And the reply of the Prime Minister was, "I can give you two divisions, but I cannot give you two factories." Now, if you are not willing to invest there, if our problem is always that we have to win it over through some kind of force, the police or the army, then, what message are we sending about our democracy, what we stand for? All the time we are saying that we are going to help them economically. Vajpayeeji also said so. But there is nothing reaching there. And there is so much of corruption. I very much emphasise that the Parliamentary Committee must be appointed to go to that place to tour the State and also try to negotiate with the people there and talk to them and also find out if the election which has been held has been a rigged one. I mean, the percentage of polling has been so low. In that case, maybe there is a need for fresh elections. Let us have a fair and independent election. We want Kashmir. It is part of our country. But we should also see

to that is democracy there. As I said, they also know what democracy is in this country. My feeling is that the problem in Jammu and Kashmir has been, for years, that while we have practiced one kind of democracy here, it has not really been allowed to be applied there and we are in the midst of this kind of trouble.

Probably, somewhat the same thing is in the north-east. Not many people go there. But whenever you go there, you feel as if democracy is not allowed to prosper there. I recall, when I was briefly India's High Commissioner in London, Phizo died. He said, "My demand, my experiment has been wrong. Nagaland must have some kind of status within India". If it is within India, then, what is the problem? We can apply Article 370 there also. That is not a problem. Autonomy can be given. But is anybody making some effort about these things?

I think the Vajpayeeji Government will tomorrow be judged on the basis of how it solves the two problems—the north-east and the Jamu and Kashmir. I am not talking of Pakistan. I am talking of our own area. How do we sort out these problems?

Lastly, Sir, I would like to lodge a complaint. A caretaker Government is a care-taker Government. Parliament consists of two Houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. I tried my best. I wrote about it. I wrote to the President. I wrote to the Prime Minister saying, "This is the Rajya Sabha. Let it meet. Let it have some kind of say on the Government. Nobody heard me. I think the time has come when the Rajya Sabha must assert itself. The Rajya Sabha is a part and parcel of the Parliament and some method should be evolved whereby the Rajya Sabha is also taken into confidence. When the Kargil conflict was going on, at least, the Members of the Rajya Sabha should have been informed about the whole conflict. But it was not done. It is really a tragedy. As far as I am concerned, I can say: "Look here, I have been here for two years. There have been two elections within six months and my period has shrunk by two, three months." I request that the role of the Rajya Sabha should be discussed separately. The Rajya Sabha, being a Council of States, is a continuing House. This House must have a check on Caretaker Governments.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, I rise unfortunately not to endorse the Address of the Hon'ble President to the Joint Session. Sir, I have been carefully listening to the speeches that were made yesterday and today. While, on the one hand, I deeply appreciate the Government for extending the olive branch towards the Opposition, seeking reconstruction of India, seeking regeneration of India, seeking a constructive basis on which to build the country for the future—indeed, this should be the endeavour of every single citizen of the country and I welcome this attempt on the part of

the Government— I would like to place on record that it is not so easy to brush aside a fundamentally flawed foundation, it is not so easy to forget the past thirteen months, the past elections that have taken place, the important events that have been dispatched with a certain cavalier attitude because these are events which have a pfofound and far-reaching significance for not just today's Indians, but the entire future generation of India, and I speak, Sir, particularly for the women of this country who have had, till today, very little say in decision-making, very little say in the process of decision-making. How can we embark upon a reconstruction that is based upon a fundamentally flawed foundation? How can we embark upon a reconstruction which is based on an election mandate that has been secured without any fundamental principles or ideology? How can we embark upon a reconstruction by forgetting the tremendous sacrifice made by nearly 500 jawans and by over 600 of them who were wounded. Sir, celebrating the victory diwas in Srinagar, on the death of our soldiers, was an act which was extraordinarily in bad taste. There were intruders in Kargil. We have differences of opinion. We believe, the Government has been guilty of gross negligence in allowing the intruders to come in the first place. Many of us believe that the Prime Minister embarked from Pakhran to Kargil by bus. But the events at Pokhran set off what happened at Kargil and there has been a gross negligence. But these are not matters to be spoken of lightly. Therefore, I will not speak of them lightly. I will only say that it was extraordinarily in bad taste; to celebrate it as a victory day because it was certainly not a victory day for the families of those jawans who were killed, for those jawans who were wounded, for those widows and children who are languishing without the members of their families who were killed in the war. It should have been a day of mourning; it should have been a day of introspection, it shold have been a day when the country took stock of what stand it had taken, why these lives were lost; why we are not able to build bridges of friendship with our neighbours, why it has become a gesture of strength to take on our neighbours and kill people. What happened to the legacy of the freedom movement? Sir, this is a fundamentally flawed theory on which the concept of a jingoistic nationhood is sought to be created by the present Government, which I deeply regret. How can we forget the terrible consequences of nuclear weaponisation? Sir, I find it utterly appalling when they make this claim that the bomb and Pokhran tests had enhanced our prestige. I have no hesitation in standing up here and saying that this country does not need nuclear weapons. I know, many of my colleagues may disagree with me, but I have very good reasons for saying this. How do we forget the terrible consequences of this nuclearisation? Sir, how do we forget, above all,—just not based upon the past, even based upon what Mr. Advani, the Home Minister, has said,—based upon what the President's Address has said.

the dangerous sugar-coated fascism that is being offered by this Government as a palliative for instability, a fixed term for the Lok Sabha, a fixed term for Parliament? Sir, it is fascism, a sugar-coated fascism, and I will come to that later. Therefore, these are fundamentally flawed theories which have been offered to a troubled nation because they have been coated with sugar and presented to us as a panacea for all evils. Sir, the Twelfth Lok Sabha was one of the shortest Lok Sabhas in the history of India, and I think—and I stand correct if I am wrong—it was the shortest Lok Sabha in the history of this country. It lasted for 412 days. We all know the troubled history of the Twelfth Lok Sabha; there is nothing for me to go into it any more.

As regards the Thirteenth Lok Sabha, Sir, I would like to make here one or two very important points. Sir, the Thirteenth Lok Sanha elections were fought and the mandate that was secured by the ruling party is a mandate that was secured by a Coalition that exists without ideology. Sir, I am sorry to say that far from moving from the basis of ideology into a cohesive alliance, it seems to me—and I say with responsibility and I say with respect—that in my own State, Tamil Nadu, the Parties like the DMK and the AIADMK which were on opposite side of the spectrum have simply changed over to the other side to suit their own purposes. I ask myself, "What ideological basis is it that these Parties have shifted their stand and have gone over to a completely opposite side?" Sir, this has happened all over the country. This has happened in Haryana, this has happened in Tamil Nadu, this has happened all over the country. Sir, the reason why I am pointing out this is not to score a narrow political point. It is easy for Mr. Advani and for the Prime Minister to say, "We put all the contentious issues on the backburner. We will not talk about the contentious issues. Let us talk about building the nation." But I have a major problem here, Sir, because the parties which are part of the NDA in Tamil Nadu, for example, the PMK and the MDMK, in their election manifesto have said that they will seek a separate EELAM in Sri Lanka. The BJP has, of course, kept out of this by not having a manifesto at all. The BJP I think, is equally significant, which has given the Prime Minister to this country, or, in whose name these elections were won does not even have a manifesto.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Last year, we had our manifesto and we were working on that. ...*(interruptions)*...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: The NDA had a manifesto. The BJP did not have it. Sir, certain things, which I say, I can only say, based on what I believe in. Sir, I cannot make certain people understand; it is not possible. It does not lie within my capacity to make those people understand, nor is it my duty! Therefore, this manifesto stands for a better ideology. I don't want to take much time of the House. There are only two or three

remarks which I want to refer to. Nobody can dispute when I SAY that every single item in the NDA's manifesto is almost the same as that of the Congress Party's manifesto. So, what the BJP and the other NDA parties have really done is this. They cobbled together an alliance for the purpose of coming to power, and these things, according to me, is suspect. All right, they have come to power. But I now call upon them to make sure that the conflicting claims of their various partners—for example; the PMK has now said in Tamil Naidu that they should allow the sale of liquor, that they should allow the sale of arrack, that they should liberalize the prohibition regime, are resolved. The Chief Minister of the State has already said that it is not easy to do so. But there are divergent, totally divergent views, on very important issues among the alliance partners. The only reason why they have come together is for the sake of power. And, therefore, to call this a mandate from the people, is, I think, stretching the truth a little too far. Another very important issue about the elections— Sir, I will not take much time of the House—is that these elections have never, in the history of this country or any other country, been characterized by such a low level of debate. Again, I do not want to waste the time of the House. I am deeply disturbed, as a citizen and as a woman, at the kind of talk on the women of the country that senior leaders of the NDA have indulged in. Mr. Pramod Mahajan compared Mrs. Sonia Gandhi, the President of the Congress Party, with Monica Lewinsky. How can a Cabinet Minister refer to a Leader of the Opposition like that? Comparing her with Monica Lewinsky. What did Mr. George Fernandes say? He said....(*Interruptions*).

Please, let me make my speech. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SANATAN BISI): Gautamji...(*Interruptions*)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Earlier, you were in the Congress Party. Now you are talking about other parties. You have crossed the floor. What for? Everybody is sitting here for power.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: What are you talking about? I am saying that this election has been characterized by an extraordinary low level of attack against women.

AN HON. MEMBER: Who started this?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Shri Pramod Mahajan started it; Shri George Fernandes started it, Dr. Murli Manohar Joshi continued it; and the Prime Minister did nothing to stop it. It was an extraordinarily low attack on women. It is a shame; it is a blot on Indian civilization. You should be ashamed of yourself to be sitting there. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Madam, please conclude now.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Yes. I am coming to the next point. I will make just two more points. The other issue that I would like to talk about is...*(Interruptions)*. The House has been extended. *(Interruptions)*. The House has already been extended. The other issue that I would like to raise is that the lead motive of this Government seems to be to militarize, to muscularise and to masculanize. We say, we are together, we are a great people. We welcomed the Bomb. We say that we have joined the elite nuclear club. But then, Sir what is there to be so proud about a weapon of destruction that was cynically tested on the Buddha Purnima day? We are celebrating the 50th anniversary of Independence and the Prime Minister, in one stroke, totally erased the legacy of the freedom movement, the Panch Sheel, non-alignment, non-violence and the dream of a world of alternatives. Sir, there was so little a debate on the cynical attempt by the BJP to create this jingoism. I just want to read this and then I will conclude. The concerned citizens of this country are saying this.

Whilst applauding the undoubted capability of our scientific and technological community, let us understand clearly that there was never any doubt or question and it certainly did not need these five tests to denonstrate about the talent of our scientific community. For the BJP to claim political mileage and the credit for acting tough and decisively is another myth. Those who have made these tests possible have been working quietly and invisibly for over two decades and every government in power has contributed to that process. There is no question that the nuclear—haves, as with many in the developed world, have demonstrated cynical double standards with regard to the less well-to-do countries. Sir, in fact, the CTBT, and the need for total disarmament have been appreciated by everybody. Equally, our right to develop our technological and scientific base is unquestionable and has been demonstrated in countless ways. Today, we have forfeited that position. Today, we have voluntarily chosen to forfeit that position and given up the intrinsic civilizational values for which this country has been respected the world over, for some questionable short term gains and the right to join precisely those nations and that club whose values we have ridiculed in public fora all over the country. Most importantly, Sir, we have lost, or, certainly postponed, an invaluable opportunity to build peace in our own region and we have more certainly laid the ground for another arms race.

6 P.M.

Just look at the number of things that this one bomb could have cost us. This one nuclear bomb can finance the construction of 3,200 houses for the rural poor under the Indira Awas Yojana. Each Agni missile can finance annual operation of 15,000 grassroot rural primary health centres. Each missile production facility can finance two time, more than what the Central

Government had funded in 1998-99 for treating 7,50,000 hectares of rain-fed areas under the watershed development programme. So, the list goes on. We are trying to create a nation where the women of this country have no choice at all. All that we want to do is to prove the macho credentials of this nation by creating some pseudo security problems when the people are actually suffering from lack of drinking water and housing for all.

Finally, since Mr. Jaswant Singh, the hon. External Affairs Minister is here, I would just like to make one plea to him. In the forthcoming SAARC summit there is a proposal, the SAARC Convention on Preventing and Combatting Trafficking in women and Children for Prostitution. This is a draft which is going to be signed by all the SAARC countries and India has drafted this. The draft is seriously deficient in many ways because it just provides for commercial prostitution and trafficking in women when money is exchanged. It does not provide for the kind of trafficking that goes on in domestics, it does not provide for the kind of trafficking in which children are abused, both sexually and as domestic workers. Many NGOs have approached the External Affairs Ministry with certain corrections to this draft. I am told that the Ministry had given them a very poor hearing. I would like to make a personal plea to the hon. External Affairs Minister that before the SAARC summit, please talk to us so that certain very important concerns that have been raised by the NGOs regarding trafficking in women and children can be at least presented to the Government before India becomes a signatory.

My last point is about Cauvery. In fact, I had given an amendment. But, unfortunately, I was not here to move the amendment. Therefore, it could not be incorporated. The President's Address does not mention a word about Cauvery. Half the election was fought on what the BJP Government has prided itself, that is, solving the Cauvery water problem. What has happened now is that rains have come and, therefore, the problem does not have the crucial edge which it had earlier. Cauvery is the life blood of Tamil Nadu. It represents the difference between life and death to the people of Tamil Nadu. I don't want to waste time by going into the history of it. The fact is that it has gone up to the Supreme Court; it has gone up to the Cauvery Water Tribunal and since 1974 we have had over 30 discussion, bilateral talks, between Karnataka and Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu have over 22,000 hectares of land where the crops are completely failing unless the rain comes. The Government of Karnataka continues to build dams. I am not going into that. The process of dialogue was on. The Prime Minister had called the Chief Ministers for a meeting and the Karnataka Chief Minister said that he was unwell and unable to attend the meeting. I am not casting any aspersion. Some say it was because of the elections. Now, there is a

complete silence on Cauvery issue. I deeply regret that the President's Address has not made any reference to how he hopes to solve this problem. There are three or four doctrines which are used to solve the problem. One geographical question is this—since the waters begin in Karnataka whether Karnataka has a prior right as an upper riparian State or whether free flow of water should be permitted to the lower riparian States. All these issues need to be sorted out. I would, therefore, urge upon the Government, through you, Sir, not to wait till it reaches a flash-point and riots take place next year and to immediately start a dialogue when the rains have come and when everybody is very cool-headed to solve the very important problem of Cauvery Water. Otherwise, this will create unnecessary tension between two friendly neighbouring States.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon. Members, I have to make an announcement. The hon. Minister, Shri Jaswant Singh, has got some other appointment. He will make the statement tomorrow and clarifications will also be taken up tomorrow.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): Sir, let me make the statement today and the clarifications can be taken up tomorrow. I did not want to fracture the discussion that is taking place on the President's Address.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, the statement can be made tomorrow.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** यह डिसाइड हुआ है कि आज सब खत्म करना है।

**श्री रमा शंकर कौशिक** (उत्तर प्रदेश): डिसाइड करने वाले तो आप हैं और हम लोग है। इसको कल ले लीजिए।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (उत्तर प्रदेश): इसको कल ले लीजिए। कल प्रधान मंत्री जी जवाब देंगे। एक घंटा कल दे दीजिए।

**श्री जसवन्त सिंह:** इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है कि आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा आज ही सम्पन्न हो और प्रधानमंत्री जी का उत्तर कल हो। यह पहले ही तय हो चुका है और अब माननीय सदस्यों का इस बात का गुहार करना शायद उचित नहीं होगा। यह चर्चा आज समाप्त हो जाए। ज्यादा से ज्यादा घंटा भर और लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कल सुबह इसका जवाब देंगे। (व्यवधान)

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** प्रधानमंत्री जी 12 बजे जवाब दे दें। एक घंटा इसके लिए रख दीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** आप बैठिए। मैं बोल रहा हूं। हम लोग, सदन यह डिसीजन ले चुका है। आज इसको खत्म करना है। आज सब का भाषण खत्म होना है। कल प्रधानमंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** निर्णय तो यह भी हो चुका था कि माननीय मंत्री जी आज ही जवाब देंगे। जब उसमें तब्दीली की है तो इसमें भी तब्दीली कर दीजिए।

**श्री जसवंत सिंह:** मुझे एक निवेदन और करना है। जो....

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:** कल 11 बजे से 12 बजे तक इस पर बहस हो जाए। हमारी भावनाओं की कद्र तो कीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** उसी के लिए तो बैठे है।

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:** आजके बजाय यह कल 11 से 12 बजे, एक घंटे हो सकता है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** हम लोगों ने हाउस में तय किया हुआ है कि इसको आज खत्म करना है। मेंबर लोगों ने डिसीजन लिया हुआ है।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, once a decision has been taken. It should not be changed every time.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, there is another request which I have to make. I would explain why this House should sit for some more time. The other House is currently voting on the Constitution Amendment Bill for extension of the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and that message has to come to this House which will enable this House to take up that business. That is another reason why we should continue.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I consider it a privilege to participate in the discussion on the President's Address. But because of paucity of time I will limit my comments to one or two topics. In fact, I will focus the attention of the Government to Para 10 of the President's Address which enunciates, what is called, the Draft Nuclear Doctrine'. Para 10 says that this Draft Nuclear Doctrine has already been prepared and presented for public debate. I think this is for the first time in the history of any country that a Draft Nuclear Doctrine prepared by the NSAB is being presented for public debate without the Government first enunciating its position. We still do not know what the Government's stand on the doctrine is; and yet, we are asked to participate in public debate. But having said that, let me go into some basic features of this doctrine because like everything else in the President's Address, which is replete with platitudes, there is no reference to the prevailing ground reality. What is being evolved in this draft nuclear doctrine is the concept of a credible minimum nuclear deterrent. Now, it is very important to understand this concept. What is a credible minimum nuclear deterrent? With reference to which nuclear power are we talking of a minimum nuclear deterrent? We do not know that yet. We know for a fact that Russia today has 11,000 nuclear warheads. We know for a fact that the United States has 8,500 nuclear

warheads; Ukraine has 1,500 nuclear warheads; Khazakhstan has 600 nuclear warheads; China has 300 nuclear warheads; Belarus has 36 nuclear warheads, and in the times to come, probably Iran, Iraq and some other countries also would join the list. Israel itself has 300 nuclear warheads. We will also develop them in the years to come. So, with reference to which country are we talking about this and for whom is this deterrent meant? When we talk of the concept of a minimum deterrent, it must be with reference to some country. And when we talk of the credibility of the deterrent, when we talk of a credible minimum deterrent, the credibility must be with reference to some country. It may not be credible for the United States. It may not be credible enough for Pakistan. But in this draft nuclear doctrine, what is mentioned is that it is with reference to every country in the world. This credible minimum nuclear deterrent will be applicable with reference to every country. I don't understand this First, the Government must explain what this concept means. Then, Sir, what is even more strange is the statement in this draft nuclear doctrine of 'no first use'. In other words, India will never use it first. so, we will wait for somebody to attack us. The deterrent is meant to deter others form attacking us. But when somebody attacks us,—because it is a 'no first use' doctrine—we should have adequate capacity, adequate retaliatory capacity, to respond. If somebody attacks us,—we do not know who that somebody is—them, we will have to assess whether there are enough nuclear arsenals in our possession so that we are in a position to retaliate adequately. The third aspect of this doctrine is that we will not use our nuclear weapons against any non-nuclear State; also, we will not use these weapons against a country which is not aligned with any nuclear weapons State.

These are the three broad features of this doctrine. I don't want to go into other technicalities because we have very little time. But one of the features which I wish to point out is that this nuclear doctrine is based on a triad concept, that we must have an aircraft which can deliver warheads; we must have mobile land-based missiles, and we must have sea-based missiles. This is the triad. In other words, we must have nuclear capacity in the form of aircraft, mobile land-based missiles and sea-based missiles. Now, having said that, the question is: What are the cost involved? For the first time again, we have a draft doctrine, without referrence to the costs. I will indicate to the Members of this House that the making a nuclear bomb itself is only seven per cent of the cost. The deploying of the bomb is 55.7% of the cost. The targeting and the control-mechanism is 14.3% of the cost. Defending ourselves against an attack is 16.1% of the cost. So, for developing a nuclear arsenal, for developing a bomb, you are only deploying 7% of your resources. The balance of 93% has yet to come. And here is a draft doctrine which does not even tell us where the resources are going to come from.

Let me just give you an idea as to what these resources will entail. supposing we were to develop a nuclear-attack submarine fleet. One nuclear-attack submarine of the quality of the 'Sea-Wolf', which belongs to the United States, cost nine billion dollars. The total investment that the Government of India expects under the FDI in a year, which a part of the President's Address, is ten billion dollars and so far, we have never got more than three billion dollars. So, to develop one sea-based missile launch carrier, we have to spend nine billion dollars. From which are you going to get the money? Why are you trying to fool the people of this country, just as in everything else? You are certainly taking the people of this country for a ride by enunciating a doctrine which is all in the air, which has no basis, as far as the ground reality is concerned; and you are stating to the world that you have become a nuclear State. Sir, there is a time in the history of every country when it reaches a cross-roads of its desting, when you have to decide on taking a certain path. If you take a wrong decision, the process is irreversible. This nuclear doctrine, on the one hand talks about weaponisation and, on the other talks about disarmament. It enunciates that we believe in universal disarmament and, at the same time, you are putting forth to the people of the country a programme of weaponisation for which you do not have the resources and for which you will have to pay the price you are forcing the people of this country to pay that price.

Sir, to develop any kind of a minimum credible deterrent, you will have to spend a sum of not less than seventy thousand crores of ruppees in the next ten-year period. These are not the computations that I have made. These are the computations made by experts in the field who have carried out, what is called, a "nuclear audit." From where are you going to get the seventy thousand crores?

Now, you are saying that the defence budget will have to increased by eight thousand crores of rupees. It is very interesting to note that the total expenditure on the defence budget, annually, is Rs. 38,000 crores, which is the cost of one nuclear submarine. So, I do not understand; what is the basis of enunciating policies of this nature, putting it in documents like this, without being transparent in your policies? This is what you did throughout the course of the last eighteen months. You have made policy statement after policy statement fooling the people of the country and persuading them to vote for you.

Unfortunately, the people of this country are not aware of what the reality is. Becuse the time is short, Sir, I will not talk much on this aspect, but I will touch on an aspect which is close to my heart, which is in paragraph 27 of this Address, It relates to judicial reforms. Again, the same palatitudes, repeated year after year, without any reference to ground reality. You say,

Sir, "The Government will institute effective measures to eliminate chronic delays in the dispensation of juste." How often has the Government said it, year after year, but what is your plan of action? How are you going to deal with the question of delay? We know that there are delays in the dispensation of justice, but we have not yet heard from you a framework within which you are going to resolve those delays. Do you want to increase the number of judges? If you want to increase the number of judges, you know, that is a State Subject, you don't have the power to increase the number of judges. Administration of justice is a State Subject. So, you will have to get the consent of the States. Are the States willing to incur that much expenditure for increasing the number of courts? At this point in time, for every million in this country, the average number of judges is 8.5, when in fact, for every million people in this country, you need a minimum of 50 judges. The United Kingdom has a minimum of 100 judges for every million people. So, do you have the resources to raise the number from 8.5 to at least 50? If you have the resources, do you have the political will? If you have the political will, will you get the cooperation of the State Governments? What is your plan of action? I can go paragraph after paragraph, reading through the President's Address, and make similar comments on each of your policy decisions. This seems to be a kind of manifesto ready for another election. You talk here, Sir, in paragraph 27, of carrying out suitable reforms in the judicial system. What reforms are you talking about? Please tell us. Please give us a framework. I know, You will say that in the days to come, these plans will be placed before the people of this country, as you have been saying over and over again, that you come up with a plan of action which will satisfy the hon. Members of this House. I know you will say all that, and you will keep repeating it to the people of this country, and you will do nothing. But the time has come. We want to cooperate with you. On behalf of my party, I want to state here that we want to cooperate with you ....(*Time-bell*)... One Second, Sir. We want to cooperate with you; please come up with these plans. I am cocussing only on these two issues because of paucity of time. I hope, Sir, the Government takes into account the observations that I have made when formulating its policies. I am exteremely greateful to the President for his gracious Address. Thank you very much.

**श्री रमा शंकर कौशिक:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए मैं अरुण शौरी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने महात्मा गांधी का कथन अपने अभिभाषण के शुरू में ही उद्धृत किया है और श्रीमन्, अफसोस तो इस बात का है कि उस कथन का जरा सा भी अंश इस पूरे अभिभाषण में कहीं भी प्राप्त नहीं होता, जो उन्होंने 48 पैरों में यह अभिभाषण दिया है उन 48 पैरों में से किसी में भी महात्मा गांधी के इस कथन का कहीं भी लेशमात्र भी जिक्र नहीं है। श्रीमन्, महात्मा गांधी का कथन कि मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूंगा जो भारत को सभी बंधनों और आश्रयों से मुक्ति दिलाए, बड़ा अच्छा होता अगर महामहिम

राष्ट्रपति जी अपना मूल भाषण किसी भारतीय भाषा में देते। कम से कम किसी एक बंधन से तो मुक्त होते। लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राष्ट्र-प्रमुख को एक विदेशी भाषा में अभिभाषण देना पड़ता है या देते हैं। मैं हिन्दी भाषा की बात नहीं कर रहा, वह किसी भी भारतीय भाषा में भाषण देते तो यह जो उद्धरण दिया गया है उसका कुछ फायदा या उस के प्रति कुछ कर्त्तव्य-निर्वहन होता।

मान्यवर, महा-महिम राष्ट्रपति महोदय का यह अभिभाषण एक ऐसा दस्तावेज होता है जिस में सरकार की मंशा और उस के ठोस कार्यक्रम बताए जाते हैं कि इस एक वर्ष में सरकार क्या-क्या करना चाहती है। यह बात सही है कि यहां जितने भी 48 पैरा हैं उन में बड़े भारी सब्जबाग दिखाए गए हैं और ऐसा लगता है कि एक साल के अंदर हमारे देश का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन उस काम के लिए धन कहां से आएगा यह जिक्र नहीं है। महोदय, यह बात भी सही है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो एजेंडा या मेनिफेस्टो था, उस का पूरे-का-पूरा समावेश राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है और वह कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, यह होना चाहिए। लेकिन कोई भी एजेंडा हो या मेनिफेस्टो हो, वह जब तक किसी ठोस कार्यक्रम के आधार पर न हो तब तक उस के निर्गुण की कोई महत्ता नहीं है अर न ही उस से कुछ हल होने वाला है। यह पूरे-का-पूरा अभिभाषण निर्गुण है और बिना किसी कार्यक्रम के एक सब्जबाग दिखाने का सपना है जो इस में निहित है। महोदय, इस में बताया गया है कि 20 लाख मकान बनेंगे, लेकिन कहां से बनेंगे, कब तक बनेंगे, यह सारी बात नहीं बतायी गयी है। इस में यह भी बताया गया है कि एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कैसे देंगे? आप यह काम लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के मार्फत करेंगे, यह कुछ नहीं बताया गया है। खाली एक बात दिखाई पड़ती है कि विश्व व्यापार संगठन के जरिए और विदेशी पूंजी निवेश के जरिए इस देश का कायाकल्प हो जाएगा।

महोदय, इस में आधा दर्जन से ज्यादा कमेटियों का जिक्र किया गया है। उस में जो अस्थाई स्थिति है या जो देश में जल्दी-जल्दी चुनाव हो रहे हैं, उस के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर सरकार या हर पार्लियामेंट के मेंबर या हर विधान सभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो। महोदय, यह एक अच्छी इच्छा है इस में कोई शक नहीं है। देश में जल्दी-जल्दी चुनाव हों, यह स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या स्थाई सरकार या स्थाई पार्लियामेंट के जरिए से ही अच्छी सरकार आ सकती है और इस स्थिति का क्या कारण है, इस बारे में नहीं सोचा गया है। क्या हमारी संसदीय प्रणाली में दोष है या हमारे राजनीतिक चरित्र में दोष है। महोदय, आज हमारे देश में हमारे राजनेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मैं उस में सभी को शामिल कर रहा हूं और खुद को भी शामिल कर रहा हूं, इस के चलते आज हमें इस बात को सोचना चाहिए कि स्थाई सरकार ही अच्छी सरकार है या वही समाज को सुधारने का पैमाना नहीं है। कितने ही अच्छे लोग क्यों न हों, वह सभी खराब भी हो सकते हैं। इस में कोई शक नहीं है। वह क्या करते हैं या उस समय क्या निर्णय लेते हैं, यह एक अलग बात है। तो हम अपनी संसदीय प्रणाली में दोष ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक चरित्र में दोष नहीं ढूंढ रहे हैं।

श्रीमान् हमारे यहां मुरादाबाद, मेरठ और गाजियाबाद जिले में एक वाहन चलता है जिसे जुगाड़ कहते हैं। यह मैं एक जोक की बात कह रहा हूं क्योंकि यहां कोई हंसी की बात नहीं होती है और सभी लोग एक गंभीर माहौल बनाए रखते हैं। तो एक विदेशी हमारे यहां पर्यटन के लिए आया और उसने उस वाहन को देखा। लोगों ने उसे बताया कि यह वाहन जुगाड़ से बना है। उस ने कहा कि बहुत बढ़िया चीज है

यह जोकि जुगाड़ से बन गयी। अब न उस में मोटर जैसे पहिए थे और न मोटर-कार या जीप जैसा इंजन था। खाली जो हमारा पंप सेट था, उस का इंजन उस में लगा हुआ था। जब वह इंजन घुमने लगा और घूमता रहा तो उस की घड़ी खराब हो गयी और उस ने हमारे यहां घड़ीसाज को उसे दिखाया। घड़ीसाज ने कहा कि साहब, यह तो इतनी बढ़िया और बाहर की घड़ी है, इसका पुर्जा तो यहां नहीं मिलेगा, मैं इसे जुगाड़ से ठीक कर देता हूं। उसने घड़ी ठीक कर दी और घड़ी चल निकली। आगे गया तो उसकी कार में खराबी आ गई तो कार के मामले में भी यही बात हुई कि साहब, इसके स्पेयर पार्ट तो यहां मिलते नहीं, जुगाड़ से इसे ठीक कर देते हैं और कार ठीक हो गई। जब वह अपने देश में पहुंचा तो उसने अपने राष्ट्रपति से कहा कि हिन्दुस्तान के पास एक ऐसी बढ़िया चीज है कि जुगाड़ से हर चीज चल जाती है, उस चीज के बारे बात की जाए। तो उन्होंने हमारे यहां के प्रधान मंत्री जी को फोन किया कि भाई, यह जुगाड़ क्या चीज है, वह हमें भी तो दो। हमारे प्रधान मंत्री जी नी कहा कि मैं भी तो जुगाड़ से प्रधान मंत्री हूं और यह जुगाड़ आपको दे दूंगा, तो यहां क्या होगा?

महोदय, सवाल इस बात का है कि हम इस बात पर गौर करें कि हम जुगाड़ में भी कोई ठोस, समयबद्ध कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं या नहीं? केवल सत्ता के लिए अगर मेल होगा तो चाहे वह किसी भी सरकार के लिए हो, वह सरकार चल नहीं सकती, उसमें स्थायित्व नहीं हो सकता। यह कोई जरूरी नहीं है कि स्थाई सरकार ही कोई अच्छा शासन दे सकती है, वह खराब भी शासन हो सकता है। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। हम सब साथ हो गए, सब साथ थे लेकिन बाद में यह विवाद उठा कि भाई, दोहरी सदस्यता न हो। जब हम एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो हम दूसरी जो संस्था है, जो राजनैतिक संस्थाएं हैं, कोई सामाजिक संस्थाएं नहीं हैं, जिसका कि सवाल उठा था और उस पर मामला खतम हो गया। ..... **(व्यवधान)**

**श्री ललितभाई मेहता** (गुजरात): राजनैतिक संस्था नहीं है।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** बिल्कुल राजनैतिक संस्था है। कौन कहता है कि राजनैतिक संस्था नहीं है।..... **(व्यवधान).....**

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** नहीं, नहीं, आप बैठिए। कौशिक जी, प्लीज, कनक्ल्यूड कीजिए।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** मैं यह मानता हूं कि राजनैतिक संस्था है।

**श्री ललितभाई मेहता:** आप मानते है, यह गलत है।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** ठीक है, यह आपका नजरिया है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** कौशिक जी, आप खतम कीजिए।

**श्री ललित भाई मेहता:** कभी आप चुनाव लड़े हैं? इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कभी?

**श्री रमा शंकर कौशिक** : हां, लड़े हैं।

**The Vice Chairman (Shri Sanatan Bisi):** Please, Please.

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमान् मैं यह निवेदन कर रहा था कि इससे स्थायित्व लाने के लिए ऐसा कानून बनाने या ऐसी व्यवस्था करने में नानिज्म का, फासिज्मा का बोध होता है। इस ढंग से अगर कोई

कार्यक्रम बनाया जाता है या इस ढंग से स्थायित्व दिया जाता है तो निश्चित रूप से वह हमको फासिज्म की ओर ले जाता और हमारे देश के लोकतंत्र का खातमा होता है। इसमें कोई शक नहीं है।

श्रीमान् किस प्रकार से आप डब्लूटीओं के जरिए से, विश्व व्यापार के जरिए से देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं? जो पिछले 9 साल का अनुभव है, जो हमने देखा है, उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे देश की क्या स्थिति हुई है। हमारा उद्योग कैसे चौपट हुआ है, हमारा दवाई उद्योग कैसे चौपट हुआ है, कपड़ा उद्योग कैसे चौपट हुआ है? यह सब हमने देखा कि डब्लूटीओ, विश्व व्यापार के जरिए से हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के लिए आप नीति बना रहे हैं, जैसा यहां पैरा में लिखा है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन की अपनी नीतियां बनी हुई हैं, अपनी उसकी शर्तें हैं। उसकी व्यापार शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेटेंट बिल लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बीमा विधेयक बनाना पड़ेगा। .....(**व्यवधान**).....

**श्री ललितभाई मेहता:** शुरुआत किसने की?

**श्री रमा शंकर कौशिक:** शुरुआत करने का नहीं है। सवाल यह है कि आज उसे कौन शुरू कर रहा है? ठीक है, हम यह कहते हैं कि यह गलत पालिसी है। .....(**व्यवधान**).....

**श्री ललितभाई मेहता:** राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है .....(**व्यवधान**)..... देश के हित को बेचने नहीं देंगे। यह कहा है .....(**व्यवधान**)

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** प्लीज, प्लीज, आप बैठिए। कौशिक जी, प्लीज।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** लेकिन जो आपने कहां, वह भी इस ढंग से कहा गया है, जिस ढ़ंग से आपने और बातों को कहा है, जिस ढंग से आपने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही है। इसका कोई मतलब नहीं है।

श्रीमान् जी, मैं अपनी बात कहकर खत्म कर रहा हूं। जो बात यहां कही गई है, उस पर मैं कह रहा था कि आप क्या नीति बनाएंगे? विश्व व्यापार संगठन की अपनी नीतियां हैं, अपनी शर्तें हैं और वह सारी बातें आप मान रहे हैं और उसके चलते आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके चलते काम नहीं कर रहे। आप पेटेंट बिल उसके चलते लाए हैं, बीमा बिल उसके चलते लाए हैं। यह सब आप उन्हीं शर्तों के चलते ही लाए हैं।

आखिर में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो यह सब्जबाग दिखाए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। किसी ठोस कार्यक्रम के ऊपर यह आधारित नहीं है, इसमें कोई समयबद्ध बात नहीं है और इसलिए इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो हम लोगों ने संशोधन दिए हैं उनको आप मानें और जो बातें मैंने यहां कही हैं या दूसरे साथियों ने कही हैं उन सब बातों को खेद सहित राष्ट्रपति जी को भेजा जाए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं। धन्यवाद।

**श्री डी॰पी॰ यादव (उत्तर प्रदेश):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए अभिभाषण और दस्तावेज़ से उभरी हुई तस्वीर के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मान्यवर, जिन भी कार्यक्रमों का सरकार ने ज़िक्र किया है, पिछली सरकार की बनिस्बत उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और बेहतर दिशा देने की बात इस दस्तावेज़ में कही गई है। हालांकि पिछली सरकार का अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन, मान्यवर, जो भी बातें इस दस्तावेज में हैं, मसलन बेरोज़गारों को रोज़गार की व्यवस्था, महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा, मैं समझता हूं कि यह अच्छे कार्यक्रम है। लेकिन, मान्यवर, इस भारतवर्ष में, जो कि एक कृषि प्रधान देश गिना जाता है, जहां पर किसान और मज़दूरों की संख्या 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है, किसानों के लिए कोई उपयोगी बातें, कोई कल्याणकारी कार्यक्रम इस दस्तावेज़ में नहीं है। यहां तक कि अभी तक किसानों के पास उनके गन्ने का मूल्य, जब कि गन्ने की फसल सर पर खड़ी है और किसान इस आशा में है कि उसका खेत खाली होगा अगली फसल के लिए लेकिन अभी तक उस गन्ने का मूल्य भी उस किसान के पास नहीं पहुंच पाया है सरकार के द्वारा।

मान्यवर, सरकार जो बेरोज़गारों को रोजगार देने की बात कहती है, मैं तो जानता हूं कि रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में हमें बहुत सारे फैक्टरी मालिकों के यहां फोन द्वारा या पत्र द्वारा नौजवानों को रोज़गार देने की बात कहनी पड़ती है लेकिन जिस भी मैनेजिंग डायरेक्टर या कम्पनी के दूसरे पदाधिकारियों से बात होती है तो मालूम होता है कि कम्पनी में छंटनी जारी है और हम 100 मज़दूर या कुछ पदाधिकारियों को निकाल देना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इस दौर में अगर हम यह समझते हैं कि हम आज के नौजवान को रोज़गार दे रहे हैं तो यह सिर्फ हमारी गलतफहमी हो सकती है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बेशक उत्पादन की दृष्टि से बेहतर उत्पादन देने की स्थिति में हो सकती है लेकिन जिस मुल्क में करोड़ों-करोड़ों हाथ बेकार हैं, जिस मुल्क का नौजवान बेरोज़गारी की चक्की में पिसता हुआ परेशान हाल में है, उसको रोज़गार देने की स्थिति में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहीं है।

मान्यवर, दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने बधाई की बात इसलिए कही कि करगिल और ऑपरेशन विजय के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को बधाई देता हूं और कहता हूं कि बधाई तो पूरे देश के लोगों को होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया और पूरे देश के लोग एक साथ मज़बूती से खड़े हो गए और यह इस देश के लिए गौरव और गर्व की बात है कि करगिल और ऑपरेशन विजय में विजय हासिल हुई। लेकिन, मान्यवर, ब्रिगेडियर योगेन्द्र सिंह यादव, जो कि मेरे क्षेत्र का रहने वाला है, परमवीर चक्र उसको मिला, सरकार ने सम्मान दिया और सारे शहीदों को, उनके परिवारों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को और हिन्दुस्तानियों को इस बात पर गर्व हुआ, लेकिन मैं महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा की बात पर आता हूं, मैं उसके गांव गया, वहां उनके परिवार वालों से मिला। आज भी गांव और देहात के जो नौजवान, किसान और महिलाओं के बेटे, इस देश की ताकत और अखंडता एक रखने की कोशिश में लगे हैं, जो अपनी जान तक की शहादत देने में भी पीछे नहीं हटते, उनकी स्थिति क्या है, उनके परिवार की स्थिति क्या है? उनके घरों में जो महिलाएं या माता-बहनें हैं, शिक्षा के नाम पर आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि श्री योगेन्द्र यादव के घर और परिवार के बीच जब मैं बैठा था तो मैंने पूछना चाहा कि उनकी माता जी या बहन कितनी पढ़ी-लिखी हैं, तो पता लगा कि गांव में कोई भी स्कूल की व्यवस्था नहीं है।

आज 50 साल की आज़ादी के बाद भी यह दुर्भाग्य इस मुल्क के लोगों के साथ जुड़ा है। बेशक हम यह कह सकते हैं कि बालकों और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देंगे लेकिन सवाल यह उठता है कि

अगर गांवों में स्कूल नहीं है, कालेज नहीं है तो फिर कहां पर वह व्यवस्था है जहां पर हम शिक्षा देंगे? यह बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने है। यही नहीं कई-कई गांवों के बीच कोई स्कूल नहीं है, कोई कालेज नहीं है। तो बुनियादी जरूरत के आधार पर सबसे पहली व्यवस्था तो यह होनी चाहिए कि यह कहने के बजाय कि हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, कहना यह चाहिए कि हम हर गांव में स्कूल खोलने का काम करेंगे, कालेज खोलने का काम करेंगे।

मान्यवर, इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दस्तावेज़ में आज जो समस्या देश के सामने गंभीर चुनौती लिए खड़ी है वह है यहां की बढ़ती हुई जनसंख्या। आज पूरे विश्व में 6 करोड़ के बीच एक करोड़ की आबादी के हिसाब से हमने अपनी भागीदारी तय कर ली लेकिन शिक्षा के नाम पर, रोज़गार के नाम पर, कानून और व्यवस्था के नाम पर हमारी सरकार कोई भागीदारी तय नहीं कर पाई। मेरा यह सुझाव है कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, यह बड़ी हैरत की बात है कि इस पूरे दस्तावेज़ में जिस पर्यावरण की समस्या से पूरा मुल्क जूझ रहा है और यह दिल्ली, जिस दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो कानून बनाती है, जो न्याय का रास्ता बताती है, वहां पर पर्यावरण की यह स्थिति है कि जो छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर खाली सड़क पर उसको सांस लेने के लिए छोड़ा जाए और लगातार भागती हुई मोटरों और दूसरे वाहनों के धुंए के बीच उसको 7-8 घंटे छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर डॉक्टरी परीक्षण के बाद वह बीमार पाया जाएगा। आज पर्यावरण की बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने है जो पूरे मुल्क को घेरे हुए है। मान्यवर, अगर इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वस्थ परंपराओं की बात केवल किताबों और विचारों तक सीमित रह जाएगी। इसलिए यह जरूरी था कि इस दस्तावेज़ में इस ओर इशारा किया जाता है और कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाता ताकि हम पर्यावरण और बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से निजात पाते।

मान्यवर, इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारें बनती हैं और अपने कार्यक्रमों को विस्तार देती हैं लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि सम्बल लोकसभा क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन है आसिफपुर। यह अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले का रेलवे स्टेशन है। बर्तानिया हुकूमत ने इसका उपयोग वहां के देशभक्तों को दबाने के लिए किया लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि 100 से भी ज्यादा शहीद और स्वतंत्रता सेनानी उस क्षेत्र में रहते हैं। चार जनपदों के बीच का यह रेलवे स्टेशन है जिसको अब सरकार ने हाल्ट के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। कहां करीब 125 बरस पहले बना रेलवे स्टेशन जो चारों जनपदों को जोड़कर विकास के नए आयाम हासिल कर सकता था और कहां यह निर्णय कि उस स्टेशन को बदलकर हाल्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार यह निर्णय लेकर किस प्रकार अपने कार्यक्रम को कल्याणकारी बना रही है।

महोदय, ऐसे वक्त में जब कि हम अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं और इस जुगत में है और सरकार भी इस जुगत में है कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए तो मेरा यह सुझाव है कि सरकार को गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए जो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग है जिस पर सारी व्यवस्थाएं चलती हैं उन लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए और वे महज़ दस्तावेज में न रहकर कार्यरूप में लागू हों, प्रैक्टिकल रूप में लागू हों।

---